चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 28 सितंबर-04 अक्टूबर, 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

व्यापमं घोटाला

ऐसी सीबीआई जांच से न्याय नहीं मिलेगा

फोटो-प्रभात पाण्डेय

भारत सचमुच अद्‌भुत देश है. यहां के घोटाले अद्‌भुत हैं. पानी, कोयला, हवा, तरंग, कुछ भी नहीं बचा है. इसी तरह यहां की जांच भी अद्‌भुत है. जैसे, सीबीआई जांच. कोयला घोटाला याद कीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तोता पिंजरे में कैद है, तोते को आज़ाद कीजिए. सरकार बदल गई, लेकिन क्या पिंजरे का ताला खुला? इस सवाल का जवाब व्यापमं घोटाले की जांच से निकलता है. घोटाले की शुरुआती जांच देखकर तो लगता है कि तोता अभी भी पिंजरे में है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ढाई महीने बाद भी सीबीआई व्यापमं घोटाले की जांच पूरी तरह अपने हाथों में नहीं ले सकी है. खुद सीबीआई ने शपथ-पत्र देकर कहा है कि उसके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह डीमैट घोटाले की जांच कर सके. व्यापमं घोटाले में 215 एफआईआर दर्ज हैं, 2,500 से ज़्यादा आरोपी हैं, जिनमें से 600 आरोपी फरार हैं. सीबीआई को उन्हें पकड़ना है, पूछताछ करनी है, लेकिन ढाई महीने बाद भी अब तक सीबीआई महज 107 मामले अपने हाथों में ले पाई है. अब आगे क्या होगा, इसका अनुमान लगाते रहिए. फिलहाल, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है चौथी दुनिया की यह विशेष रिपोर्ट:-

नवीन चौहान

आपने नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत ज़रूर सुनी होगी. ऐसा ही कुछ व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही जांच में हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने नौ जुलाई, 2015 को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अब तक तक़रीबन ढाई महीने गुज़र जाने के बाद भी सीबीआई इस मामले को पूरी तरह अपने हाथों में नहीं ले सकी है. जिन बड़े लोगों को एसटीएफ और एसआईटी ने गिरफ्तार किया था, उनमें से कई को 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल न किए जाने के कारण जमानत भी मिल गई है. मध्य प्रदेश सरकार भी येन-केन-प्रकारेण व्हिसिल ब्लोअर्स पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. इसका सीधा-सा मतलब यह है कि शिवराज सरकार सीबीआई जांच से डरी हुई है और वह मामले को रफा-दफा करने की पूरी कोशिश कर रही है.

यह जांच सजा देने के लिए है या जमानत देने के लिए

नौ जुलाई, 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए. सीबीआई ने 13 जुलाई को जांच अपने हाथों में ली. ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी अग्रवाल के नेतृत्व में सीबीआई की 40 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच कर रही है. शुरुआत में ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी/एसटीएफ द्वारा जांच जारी रखने की अपील की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई तक एसटीएफ को जांच जारी रखने का निर्देश दिया. यदि एसटीएफ 23 जुलाई तक आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल न करती, तो 245 आरोपी छूट जाते. इन 245 आरोपियों में सीबीआई ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन

सीबीआई के पास अधिकारियों की कमी

आम तौर पर सीबीआई में जांच का कार्य इंस्पेक्टर से लेकर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी करते हैं. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्त पदों को लेकर जो हलफ़नामा पेश किया है, उसके अनुसार, देश भर में चल रही जांचों के लिए पर्याप्त अधिकारी नहीं हैं. इसलिए उसका व्यापमं के साथ-साथ डीमैट की जांच भी हाथ में लेना संभव नहीं है. फिलहाल सीबीआई में अधिकारियों के कुल 981 स्वीकृत पदों में से 283 यानी तक़रीबन 25 प्रतिशत पद रिक्त हैं. डीआईजी स्तर के 39 पदों में से 12 और एसएसपी स्तर के 10 पदों में से छह पद रिक्त हैं. सीबीआई के पास पर्याप्त संख्या में विधि अधिकारी भी नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को व्यापमं संबंधी मामलों के लिए अलग से प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं, लेकिन हालत यह है कि विधि अधिकारियों के कुल 340 स्वीकृत पदों के मुक़ाबले 228 यानी 33 प्रतिशत कम अधिकारी उपलब्ध हैं. व्यापमं मामले में विभिन्न अदालतों में जमानत की तक़रीबन एक हज़ार से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन सीबीआई प्रोसिक्यूटर्स की कमी का हवाला देकर लगातार समय मांग रही है. ■

व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर्स प्रशांत पांडेय, आशीष चतुर्वेदी और डॉ. आनंद राय.

- ढाई महीने बाद भी सीबीआई मामले को पूरी तरह अपने हाथों में नहीं ले सकी.
- ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी अग्रवाल के नेतृत्व में सीबीआई की 40 सदस्यीय टीम कर रही है जांच.
- डीमैट के बड़े आरोपी उपरीत को मिली जमानत.
- एसआईटी ने 185 एफआईआर दर्ज की थीं.
- सीबीआई अब तक 107 एफआईआर अपने हाथों में ले सकी.
- आनंद राय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शपथ-पत्र दायर करके कहा, शिवराज मामले से हटने के लिए दबाव बना रहे हैं.

डीमैट और व्यापमं मामले के सबसे प्रमुख आरोपियों में से एक योगेश चंद्र उपरीत से सीबीआई ने ग्वालियर जेल में आठ घंटे तक पूछताछ की. उसके दो दिनों बाद यानी चार सितंबर को उनके ख़िलाफ़ चालान पेश करने में असफल रहने के कारण कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. यदि सीबीआई चाहती, तो पूछताछ के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने की मांग कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया.

योगेश उपरीत पहले ही यह बयान दे चुके हैं कि डीमैट के सारे सेलेक्शन पूर्व निर्धारित होते थे और हर साल राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री को 10 करोड़ रुपये डीमैट के किसी भी तरह के क्रियाकलापों पर आवाज़ न उठाने या किसी तरह की बाधा न पैदा करने के एवज में दिए जाते थे. बावजूद इसके, उपरीत जैसे हाई प्रोफाइल आरोपी की सीबीआई ने

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भाजपा ने जैसा चाहा, वैसा बांटा | P-3

बिखरता तिलिस्म, दरकती अर्थव्यवस्थाएं | P-4

शेखावाटी : हाईटेक खेती ने जीवन में बिखेरे खुशियों के रंग | P-7

ऐसी सीबीआई जांच से न्याय नहीं मिलेगा

पृष्ठ 1 का शेष

जमानत हो जाने दी. लेकिन, जेल से बाहर आने के बाद उनकी जान भी ख़तरे में बताई जा रही है. व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने उपरीत की जान को ख़तरा बताते हुए उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग सीबीआई के निदेशक से की है. आशीष का कहना है कि उपरीत पहले से ही कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी उम्र भी तक़रीबन 70 वर्ष है. यदि उपरीत जैसे मुख्य आरोपी की किसी भी तरह से मौत हो जाती है, तो इस मामले के बहुत-से सुबूत जमींदोज हो जाएंगे. इसके अलावा व्यापमं और डीमैट घोटाले के बीच की एक मुख्य कड़ी हट जाएगी, जिसका सीधा असर मामले की जांच पर पड़ेगा और बहुत-से आरोपी इस वजह से क़ानून के फंदे से बच निकलेंगे. उपरीत को जमानत मिलने के मसले पर डॉ. आनंद राय का कहना है कि सीबीआई की साठगांठ के बगैर ऐसा होना संभव नहीं था. यदि सीबीआई का वकील विरोध करता, तो उन्हें जमानत न मिल पाती.

व्हिसिल ब्लोअर्स से लेकर आम लोग तक सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं हैं. एसआईटी ने व्यापमं घोटाले में 185 एफआईआर दर्ज की थीं. पिछले ढाई महीने में सीबीआई केवल 107 एफआईआर अपने हाथों में ले सकी है. 78 प्रकरणों को हैंडओवर करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अचानक एसआईटी द्वारा इस संबंध में दर्ज 30 अन्य एफआईआर भी सामने आ गईं, जिन्हें पहले जान-बूझ कर लोगों के सामने नहीं लाया गया था. ऐसे में एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वह इन एफआईआर को अब तक क्यों दबाए बैठी थी? सीबीआई के हाथों में जांच जाने के बाद व्यापमं से जुड़े लोगों की मौत का सिलसिला पूरी तरह रुक गया है, यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है.

व्हिसिल ब्लोअर्स पर याचिका वापस लेने का दबाव

व्हिसिल ब्लोअर डॉ. आनंद राय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक शपथ-पत्र दायर किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उन पर व्यापमं मामले से हटने के लिए दबाव डाल रहे हैं. अपने शपथ-पत्र में आनंद राय ने कहा है कि 11 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अपने घर बुलाया और उनसे व्यापमं और डीमैट के विरुद्ध चल रहा अभियान बंद करने के लिए कहा. दोनों के बीच मुलाक़ात एक भरोसेमंद व्यक्ति के ज़रिये तय हुई थी और रात 9.45 बजे का वक्त तय हुआ. दोनों के बीच यह मुलाक़ात एक घंटे पांच मिनट तक चली. इस मुलाक़ात में गोपनीयता का खास ख्याल रखा गया था. राय के सुरक्षाकर्मी को बाहर ही रोक लिया गया था. इसके अलावा डॉ. आनंद के मुख्यमंत्री आवास आने की कोई एंट्री नहीं की गई. यहां तक कि सीएम हाउस के कर्मचारियों को भी इस मुलाक़ात की कोई भनक नहीं लगी. राय ने थोड़ी चालाकी दिखाई और सीएम का स्टिंग ऑपरेशन एक जासूसी घड़ी के ज़रिये कर लिया और इन सभी बातों को आधार बनाते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शपथ-पत्र दिया कि 11 अगस्त, 2015 को रात 9.45 से 10.50 बजे तक उनका मोबाइल सीएम हाउस की सुरक्षा चौकी में रहा. मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाक़ात कर उन्हें इंदौर वापस ट्रांसफर कराने समेत कई प्रलोभन दिए. इसके बाद हाईकोर्ट ने शिवराज सिंह को नोटिस जारी किया और उन्हें सात दिनों के अंदर अपना जवाबी शपथ-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया, लेकिन शिवराज सिंह ने अदालत को कोई जवाब नहीं दिया.

जेल भेजने और मार डालने की साजिश

इस घटना के बाद डॉ. आनंद राय और उनकी पत्नी का अगस्त-सितंबर माह का वेतन भी रोक दिया गया. आनंद राय का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए अधिकारी को निलंबन के दौरान आधी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उन्हें और उनकी पत्नी को दो-दो माह से वेतन नहीं मिला है. यह सीधे तौर पर दबाव बनाने का खेल है. इससे साफ़ ज़ाहिर है कि मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं कर रही है, जबकि वह व्हिसिल ब्लोअर्स पर याचिका वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और जांच प्रभावित कर रहे हैं. हालांकि, बाद में मुख्यमंत्री ने आनंद राय से मुलाक़ात की बात मीडिया के समक्ष मान ली. साथ ही उन्होंने कहा कि मुलाक़ात के लिए खुद आनंद राय ने अनुरोध किया था. लेकिन, आनंद राय ने ऐसे किसी अनुरोध से इंकार किया. उन्होंने कहा, यदि मुझे मुलाक़ात करनी होती, तो मैं लिखित में उनसे मुलाक़ात के लिए आवेदन करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रशांत पांडे के ख़िलाफ़ जो मुक़दमा भोपाल में दर्ज किया गया था, उसमें पुलिस ने 250 पृष्ठों की चार्जशीट दायर कर दी है. प्रशांत ने चौथी दुनिया को बताया कि यह उन पर दबाव बनाने की कोशिश है. सरकार को जिन मामलों में संजीदगी से जांच करनी चाहिए थी, उन्हें छोड़कर वह व्हिसिल ब्लोअर्स को क़ानून के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है. बकौल प्रशांत, मेरी पत्नी मेघना को 9.96 लाख रुपये के साथ 25 जुलाई को गिरफ्तार कर आरोप लगाया गया कि यह पैसा हवाला का है. जबकि सच यह है कि मेरी पत्नी शनिवार होने की वजह से उन पैसों को बैंक में जमा नहीं कर पाई. हमें एक फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर को पैसे देने थे, लेकिन ईडी और आईटी के अधिकारियों ने हमारी मेहनत की कमाई हमसे छीन ली. यह क़ीमत हमें व्यापमं में व्हिसिल ब्लोअर होने की वजह से चुकानी पड़ रही है. ये लोग मुझे जेल भेजने या फिर मार डालने की फिराक में हैं.

सीबीआई ने डीमैट की जांच के प्रति अनिच्छा जताई

सुप्रीम कोर्ट ने डीमैट घोटाले की सीबीआई जांच के लिए आशीष चतुर्वेदी और डॉ. आनंद राय द्वारा दायर याचिकाओं पर सीबीआई से जवाब मांगा था. सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि डीमैट घोटाला व्यापमं घोटाले से बड़ा है और उसके पास जांच के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि जब वह निजी मेडिकल कॉलेजों की राज्य कोटे की 42 प्रतिशत सीटों की जांच के लिए तैयार है, तो उसे डीमैट कोटे की 43 प्रतिशत सीटों की जांच से परहेज क्यों है? इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब देने के लिए अदालत से दो सप्ताह का समय मांगा. वहीं दूसरी तरफ़ पारस सकलेचा और अजय दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर व्यापमं की जांच में सीबीआई के ढीले रवैये पर आपत्ति ज़ाहिर की. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने डीमैट की जांच सीबीआई से कराने का विरोध किया और कहा कि व्यापमं के मामले सीबीआई ले रही है, निजी कॉलेजों ने अपनी सीटों के लिए डीमैट कराई है, इससे सरकार का कोई लेना-देना नहीं है. यह निजी मेडिकल कॉलेजों की निजी सीटों के लिए परीक्षा है.

सरकार का यह कहना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले ही टिप्पणी कर चुका है कि डीमैट घोटाले से दो पीढ़ियों का भविष्य खराब हो गया. सरकार की ज़िम्मेदारी लोगों को बराबरी का अधिकार सुनिश्चित करना है, लेकिन पैसे के बल पर बराबरी का अधिकार छीना जा रहा है. यदि कोई शिक्षण संस्थान राज्य में काम कर रहा है, तो वह ग़ैर-क़ानूनी तरीके नहीं अपना सकता. इसकी पूरी ज़िम्मेदारी सरकार की बनती है.

डीमैट की जांच से क्यों बच रही है सीबीआई

कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले एक सूची जारी की थी और डीमैट से जुड़े कुछ रसूखदार लोगों के नाम उजागर किए थे, जिनमें कुछ पूर्व न्यायाधीश, आईएएस-आईपीएस अधिकारी, प्रदेश के मंत्रीगण और 100 से ज़्यादा सांसद-विधायक शामिल हैं. कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते सीबीआई को मजबूरी में मामले की जांच करनी पड़ रही है. यदि सीबीआई डीमैट की जांच अपने हाथों में लेती है, तो इस काले कारोबार की सारी सच्चाई सामने आए जाएगी. लोगों को सीबीआई की कम स्टाफ वाली बात भी हजम नहीं हो रही है. डीमैट घोटाले से न्यायाधीश, नौकरशाह, नेता, डॉक्टर और बड़े कारोबारी जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद सीबीआई उन पर हाथ डालने से बचना चाहती है.

व्हिसिल ब्लोअर्स से लेकर आम लोग तक सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं हैं. एसआईटी ने व्यापमं घोटाले में 185 एफआईआर दर्ज की थीं. पिछले ढाई महीने में सीबीआई केवल 107 एफआईआर अपने हाथों में ले सकी है. 78 प्रकरणों को हैंडओवर करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अचानक एसआईटी द्वारा इस संबंध में दर्ज 30 अन्य एफआईआर भी सामने आ गईं, जिन्हें पहले जान-बूझ कर लोगों के सामने नहीं लाया गया था.

पारस सकलेचा

व्हिसिल ब्लोअर्स से आधिकारिक मुलाक़ात नहीं

सीबीआई ने पिछले ढाई महीने में व्हिसिल ब्लोअर्स के साथ आधिकारिक रूप से कोई मुलाक़ात नहीं की है. मध्य प्रदेश विधानसभा में व्यापमं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले पूर्व अदालत को तय करना है.

व्हिसिल ब्लोअर्स के वकील विवेक तनखा ने चौथी दुनिया को बताया कि सीबीआई बहुत धीमी गति से जांच कर रही है. पिछले दो-ढाई महीनों में उसने केवल मामलों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की, जांच के स्तर पर उसने अब तक कुछ नहीं किया है. दो महीने तक वह केवल मैन पॉवर और रिसोर्स की बात करती रही, इंवेस्टिगेशन की कोई बात नहीं हुई. बकौल तनखा, जब हमने अदालत से इंवेस्टिगेशन के बारे में कहा, तब अदालत ने सीबीआई से नौ अक्टूबर को इंवेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की बात कही. अब स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद यह मालूम हो पाएगा कि एफआईआर हैंडओवर करने के अलावा सीबीआई ने क्या किया है. जांच में सीबीआई को वक्त लगेगा. एसटीएफ/एसआईटी भी कई सालों से जांच कर रही थी, बावजूद इसके वह जांच में सफल नहीं हो सकी. हम चाहते हैं कि अच्छी तरह जांच हो जाए, यह सबसे बड़ी चीज है. इससे जो गुनहगार होंगे, उन्हें सजा मिल सकेगी. यहां सबसे बड़ी ज़रूरत उन मामलों की सही जांच होने की है, जिनमें पब्लिक सर्वेंट्स शामिल हैं.

सूत्रों का कहना है कि सीबीआई जांच के तरीके में बदलाव की तैयारी कर रही है. वह गिरफ्तार किए गए छात्रों एवं उनके अभिभावकों को गवाह बनाना चाहती है. सीबीआई का मानना है कि फिलहाल 2,600 लोग इस मामले में आरोपी हैं, जिनमें से 600 से अधिक फरार हैं. उसे लगता है कि जांच में इस संख्या में और भी इज़ाफा हो जाएगा. ज़ाहिर है, ऐसे में मामले की तह तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा और मुख्य आरोपी उसकी पकड़ से बाहर हो जाएंगे.

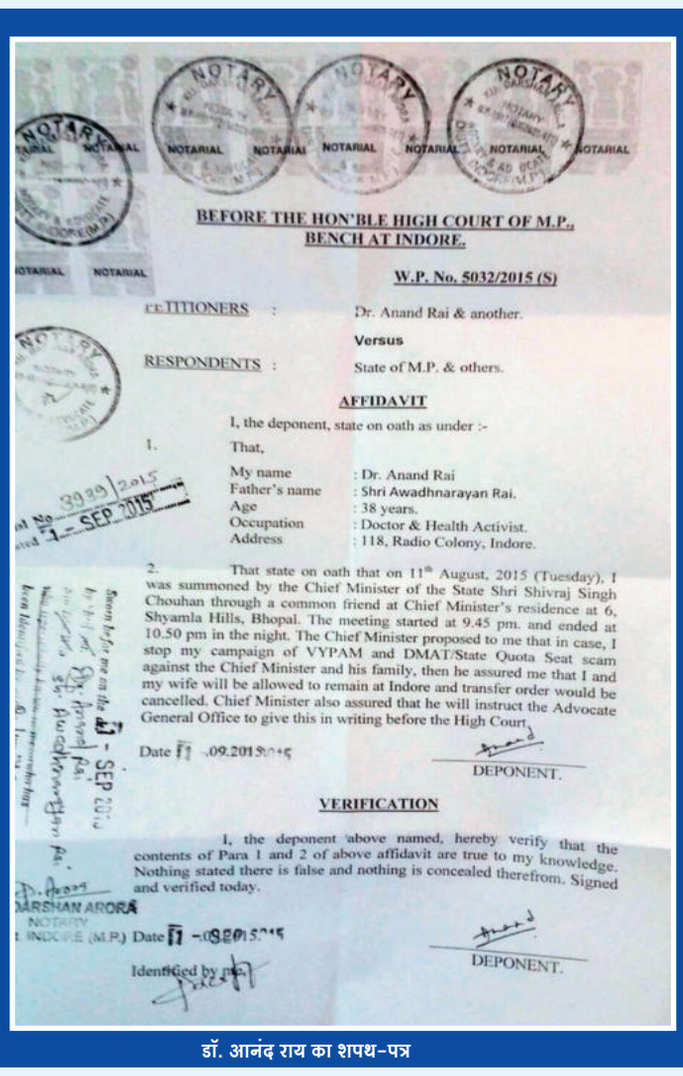

BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P., BENCH AT INDORE.

W.P. No. 5032/2015 (S)

PETITIONERS : Dr. Anand Rai & another.

Versus

RESPONDENTS : State of M.P. & others.

AFFIDAVIT

I, the deponent, state on oath as under :-

1. That,

My name : Dr. Anand Rai
Father's name : Shri Awadhnarayan Rai.
Age : 38 years.
Occupation : Doctor & Health Activist.
Address : 118, Radio Colony, Indore.

2. That state on oath that on 11th August, 2015 (Tuesday), I was summoned by the Chief Minister of the State Shri Shivraj Singh Chouhan through a common friend at Chief Minister's residence at 6, Shyamla Hills, Bhopal. The meeting started at 9.45 pm. and ended at 10.50 pm in the night. The Chief Minister proposed to me that in case, I stop my campaign of VYPAM and DMAT/State Quota Seat scam against the Chief Minister and his family, then he assured me that I and my wife will be allowed to remain at Indore and transfer order would be cancelled. Chief Minister also assured that he will instruct the Advocate General Office to give this in writing before the High Court.

Date 11.09.2015

DEPONENT.

VERIFICATION

I, the deponent above named, hereby verify that the contents of Para 1 and 2 of above affidavit are true to my knowledge. Nothing stated there is false and nothing is concealed therefrom. Signed and verified today.

Date 11-SEP-2015

DEPONENT.

डॉ. आनंद राय का शपथ-पत्र

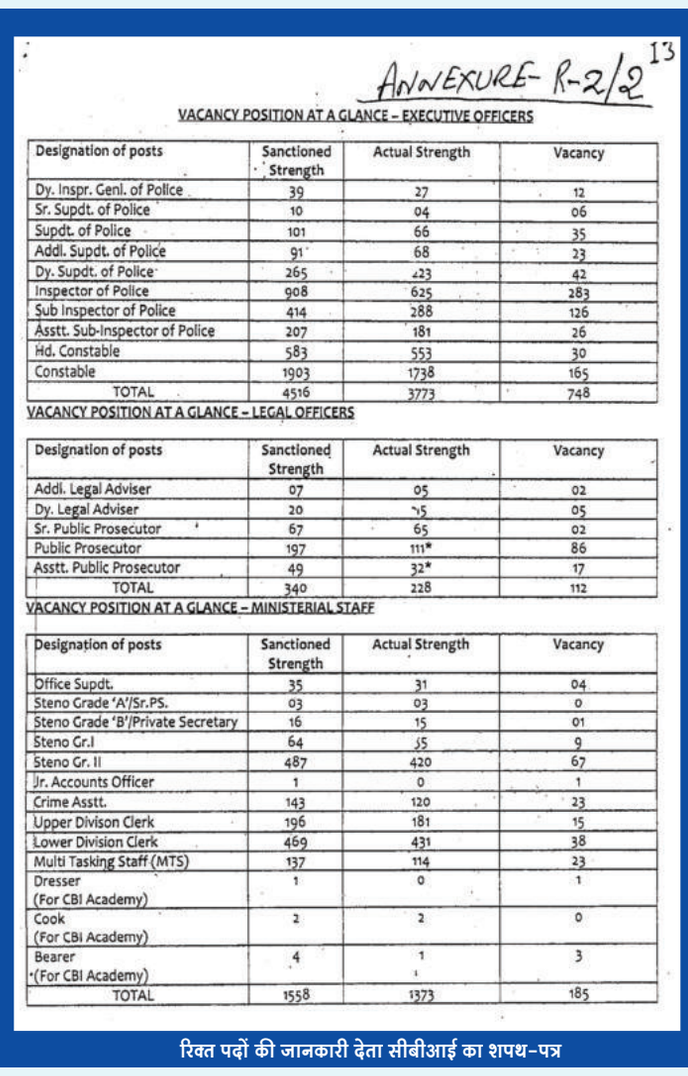

ANNEXURE- R-2/2

VACANCY POSITION AT A GLANCE – EXECUTIVE OFFICERS

Designation of posts	Sanctioned Strength	Actual Strength	Vacancy
Dy. Inspr. Genl. of Police	39	27	12
Sr. Supdt. of Police	10	04	06
Supdt. of Police	101	66	35
Addl. Supdt. of Police	91	68	23
Dy. Supdt. of Police	265	423	42
Inspector of Police	908	625	283
Sub Inspector of Police	414	288	126
Asstt. Sub-Inspector of Police	207	181	26
Hd. Constable	583	553	30
Constable	1903	1738	165
TOTAL	4516	3773	748

VACANCY POSITION AT A GLANCE – LEGAL OFFICERS

Designation of posts	Sanctioned Strength	Actual Strength	Vacancy
Addl. Legal Adviser	07	05	02
Dy. Legal Adviser	20	15	05
Sr. Public Prosecutor	67	65	02
Public Prosecutor	197	111*	86
Asstt. Public Prosecutor	49	32*	17
TOTAL	340	228	112

VACANCY POSITION AT A GLANCE – MINISTERIAL STAFF

Designation of posts	Sanctioned Strength	Actual Strength	Vacancy
Office Supdt.	35	31	04
Steno Grade 'A'/Sr.PS.	03	03	0
Steno Grade 'B'/Private Secretary	16	15	01
Steno Gr.I	64	55	9
Steno Gr. II	487	420	67
Jr. Accounts Officer	1	0	1
Crime Asstt.	143	120	23
Upper Divison Clerk	196	181	15
Lower Division Clerk	469	431	38
Multi Tasking Staff (MTS)	137	114	23
Dresser (For CBI Academy)	1	0	1
Cook (For CBI Academy)	2	2	0
Bearer *(For CBI Academy)	4	1	3
TOTAL	1558	1373	185

रिक्त पदों की जानकारी देता सीबीआई का शपथ-पत्र

ऐसे होनी चाहिए जांच

व्यापमं मामले में व्हिसल ब्लोअर्स के वकील विवेक तनखा का मानना है कि सीबीआई को एक छोर से मामले की जांच करनी चाहिए. इंदौर में व्यापमं से संबंधित पहली एफआईआर दर्ज हुई थी. उसके बाद ही मामले की परतें खुलनी शुरू हुई थीं. इसलिए सीबीआई को सबसे पहले उसी एफआईआर की जांच से शुरुआत करनी चाहिए. अगर सीबीआई यहां-वहां से मामले चुनकर जांच शुरू करती है, तो वह उलझती चली जाएगी. सीबीआई को एसआईटी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उसे घोटाले से जुड़ी तमाम बारीकियां मालूम हैं. वैसे भी शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को अपनी जांच जारी रखने का आदेश दिया था. इसके अलावा इस घोटाले की जांच भी 2-जी और कोयला घोटाले की तरह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से नौ अक्टूबर को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है. इसके बाद ही जांच की सही दिशा निर्धारित हो पाएगी. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 30
दिल्ली, 28 सितंबर-04 अक्टूबर, 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

navinonline2003@gmail.com

भाजपा की चिंता यह रही कि वह उतनी सीटों पर अपना सिंबल तो ज़रूर दे कि विधानसभा में अपने खुद के बहुमत लायक विधायक जुटा ले. उसका मानना रहा कि इतनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने से यह राजनीतिक ज़रूरत पूरी हो सकती है. वस्तुत: घटक दलों की सारी घेराबंदी भाजपा की यह चाहत पूरी न होने देने की थी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली.

भाजपा ने जैसा चाहा, वैसा बांटा

एनडीए में सीटों के बंटवारे के साथ भाजपा का बड़े भाई का रुतबा बरकरार रहा, इस संबंध में उसकी रणनीति सफल रही. भाजपा नेतृत्व, चाहे वह राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक, ने अपने हिस्से के लिए कम से कम एक सौ साठ सीटों की सीमा तय की थी. घटक दलों के दबाव के बावजूद भाजपा ने अपनी चाहत में कोई फेरबदल नहीं किया. हालांकि, रालोसपा ने काफी पहले फॉर्मूला दिया था कि पिछले चुनाव में एक सौ दो सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी थे, इस बार भी वैसा हो

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) एक क़दम और आगे बढ़ गया यानी घटक दलों में सीटों का बंटवारा हो गया. तमाम अगर-मगर और क़रीब एक हफ्ते की रस्साकशी के बाद यह काम अंजाम दिया गया. विधानसभा की 243 सीटों में से एक सौ साठ सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी. शेष 83 सीटों में से लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) को 40, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) को 23 और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) को बीस सीटें मिली हैं. साथ ही हम के पांच नेताओं को भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने की सुविधा दी जाएगी, ताकि उन्हें राजनीतिक विस्थापन की मार न झेलनी पड़े. सीटों के बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूला यह बना था कि जिस घटक दल ने लोकसभा की जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसकी छह गुना विधानसभा सीटें उसे मिलेंगी, क्योंकि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा की छह सीटें होती हैं. इस लिहाज से भाजपा को विधानसभा की 186, लोजपा को 42 और रालोसपा को 18 सीटें मिलनी थीं. चूंकि हम का गठन कुछ महीने पहले हुआ है, लिहाजा उसके लिए भाजपा को ही सीटों की व्यवस्था करनी पड़ी. बिहार की राजनीति में ऐसा प्रयोग पिछले कुछ चुनावों से होता रहा है. पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी के कई उम्मीदवार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे और विधायक बने. नीतीश कुमार के साथ संबंध विच्छेद के बाद कुछ तो वापस जद (यू) में चले गए और कुछ भाजपा में रह गए. भाजपा और हम के साथ वैसा ही रिश्ता बन रहा है.

एनडीए में सीटों के बंटवारे के साथ भाजपा का बड़े भाई का रुतबा बरकरार रहा, इस संबंध में उसकी रणनीति सफल रही. भाजपा नेतृत्व, चाहे वह राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक, ने अपने हिस्से के लिए कम से कम एक सौ साठ सीटों की सीमा तय की थी. घटक दलों के दबाव के बावजूद भाजपा ने अपनी चाहत में कोई फेरबदल नहीं किया. हालांकि, रालोसपा ने काफी पहले फॉर्मूला दिया था कि पिछले चुनाव में एक सौ दो सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी थे, इस बार भी वैसा हो. शेष 141 सीटें सहयोगी दलों में बांट दी जाए. लोजपा ने 70-80 सीटों की सूची दी थी, जबकि रालोसपा पचास से कम पर राजी न होने की बात कर रही थी. हम के नेता जीतन राम मांझी की चाहत भी बेहिसाब थी, पर वह पचास से कम सीटों पर मानने को कतई तैयार न होने की बात करते थे. लेकिन, शुरू से ही माना जा रहा था कि ये सारे दावे-दर-दावे दिल बहलाने के लिए हैं. हुआ वही, जो भाजपा ने चाहा. लोजपा की एक बड़ी शर्त हम के कुछ विधायकों-नेताओं को लेकर थी. उसके नेताओं (पासवान परिवार) का कहना था कि हम में उन लोगों की संख्या काफी है, जिन्होंने फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में जीत तो लोजपा के टिकट पर हासिल की थी, पर उसके साथ विश्वासघात कर जद (यू) में चले गए थे. अव्वल तो ऐसे लोगों को एनडीए में शामिल न किया जाए और यदि शामिल कर भी लिया जाए, तो उम्मीदवार न बनाया जाए. ऐसी सीटों की संख्या लगभग आधा दर्जन है. सीटों के आवंटन से साफ़ है कि उसकी शर्त स्वीकार नहीं की गई. जमुई ज़िले की दो सीटें जमुई और चकाई लोजपा के खास निशाने पर थीं. ये दोनों विधानसभा क्षेत्र चिराग पासवान के जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से हैं और यहां से पूर्व मंत्री एवं हम के नेता नरेंद्र सिंह के पुत्र विधायक हैं. ये सीटें लोजपा के हिस्से में डालने की बात भाजपा ने स्वीकार नहीं की. इसका मलाल पासवान परिवार को रहा है.

खास मांगें (शर्त भी कह सकते हैं) सभी घटक दलों की रहीं. रालोसपा का ज़ोर था कि बंटवारे में यदि उसे अपेक्षित संख्या

सीटों के आवंटन और उम्मीदवारों के चयन का काम जैसे ही ज़ोर पकड़ेगा, एनडीए दोहरे संकट का शिकार बनेगा. दलों में तनातनी बढ़ेगी और टिकटार्थियों का पलायन शुरू हो जाएगा. भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसे लेकर एनडीए के उसके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं. एनडीए में एक नया संकट है. घटक दल चाहते हैं कि उन्हें सीटें आवंटित कर दी जाएं, लेकिन भाजपा उनसे उन तथ्यों की पुख्ता जानकारी चाहती है, जो उनकी जीत के कारण बन सकते हैं.

में सीटें नहीं मिलती हैं, तो न सही, पर प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उसे कम से कम एक सीट ज़रूर मिले. लिहाजा उसके हिस्से में कम से कम चालीस सीटें आएं. यह भी नहीं होना था, सो नहीं हुआ. बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद जीतन राम मांझी के साथ जद (यू) के कुछ विधायक-मंत्री बगावत करके जुड़े रहे. उनमें से पांच विधायक मांझी की सहमति से भाजपा में शामिल हो गए और बाकी तेरह विधायक एवं दो विधान पार्षद मांझी के साथ रह गए. मांझी का कहना था कि इन सभी को विधानसभा की उम्मीदवारी देनी है, पार्टी को खड़ा करने में लगे कई प्रमुख लोगों को अवसर देना है, इसलिए उन्हें पर्याप्त सीटें चाहिए. फिर बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता की उनकी हैसियत को भी ध्यान में रखा जाए. लिहाजा उन्हें लोजपा से एक सीट भी कम नहीं चाहिए. अपनी इस दलील को मनवाने की हरसंभव कोशिश उन्होंने की, जो नाकाम रहीं. किसी भी क़ीमत पर एक सौ साठ सीटों से कम पर अपने प्रत्याशी न उतारने का भाजपा का प्रण पूरा हुआ. भाजपा की चिंता यह रही कि वह उतनी सीटों पर अपना सिंबल तो ज़रूर दे कि विधानसभा में अपने खुद के बहुमत लायक विधायक जुटा ले. उसका मानना रहा कि इतनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने से यह राजनीतिक ज़रूरत पूरी हो सकती है. वस्तुत: घटक दलों की सारी घेराबंदी भाजपा की यह चाहत पूरी न होने देने की थी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली.

विधानसभा की कोई दस सीटें रिजर्व रखने की भाजपा की रणनीति में एनडीए के घटक दलों ने पलीता ज़रूर लगा दिया. घटक दलों ने सीटों के बंटवारे का मुद्दा सार्वजनिक तौर पर जैसे ही उठाया, भाजपा ने कोई दस सीटें रिजर्व रखने की बात अनौपचारिक तौर पर शुरू कर दी. ऐसा करने का मकसद क्या है, यह भाजपा ने कभी साफ़ नहीं किया. राजनीतिक हलकों में माना गया कि उक्त सीटें उन अघोषित ताकतों के हित में रिजर्व रखी जा रही थीं, जो लालू-नीतीश के वोट बैंक को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं. इसका सीधा लाभ एनडीए को मिलना तय है. घटक दल चाहते थे कि यह व्यवस्था भाजपा अपने हिस्से से करे. इस मसले पर भाजपा को फिलहाल पीछे हटना पड़ा. राजनीतिक तौर पर अति-महत्वाकांक्षी रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी उसे अपना रुख बदलना पड़ा. भाजपा नेतृत्व का एक तबका रालोसपा को विधानसभा की 15 से 18 सीटें देने का पक्षधर था. उसका कहना था कि तयशुदा फॉर्मूले के हिसाब से भी रालोसपा को इससे अधिक सीटें नहीं देनी चाहिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की यह रणनीति क्षत-विक्षत करने में सफल रहे. रालोसपा को इस फॉर्मूले के बावजूद कम से कम पांच सीटें अधिक मिलीं. एक और मोर्चे पर भाजपा नेतृत्व को अपनी अनौपचारिक पहल की अनदेखी करनी पड़ी. भाजपा ने अपने सहयोगी दलों से विधानसभा सीटों के साथ संभावित प्रत्याशियों की सूची देने को भी कहा था, लेकिन सहयोगी दलों ने इस बात को तवज्जो नहीं दी. भाजपा का उद्देश्य जो भी रहा हो, पर सहयोगी दलों ने इसे अपनी आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप जैसा मान लिया. हालांकि, इसे नए सिरे से फिर शुरू करने की तैयारी की जा रही है. कहते हैं, सीटों की पहचान की प्रक्रिया में दलों से यह कैफियत लिए जाने की तैयारी है कि संबंधित सीट पर उनके प्रत्याशी कौन होंगे. यह प्रत्याशियों की स्क्रूटनी जैसा काम होगा. देखना है कि सहयोगी दल इस प्रक्रिया को कैसे ग्रहण करते हैं.

सीटों के बंटवारे के बाद कहने को तो एनडीए में सब कुछ ठीक है. हालांकि, लोजपा ने ज़रूर कहा है कि उसके साथ पूरा न्याय नहीं किया गया, पर उसने अपनी चिंता से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को अवगत करा दिया है. लोजपा या रालोसपा की शिकायत है कि उनके सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों की विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं रहने दी गई है, वहां प्रत्याशियों के चयन में सांसदों की सामान्य राय तक नहीं ली गई, पर चयनित उम्मीदवार की जीत की गारंटी में सांसदों की भूमिका अनिवार्य तौर पर तय की जा रही है. एनडीए के सहयोगी दलों का अनौपचारिक आरोप है कि वे अपने बड़े भाई की चौधराहट झेल रहे हैं. यह सच्चाई है कि पूरे बिहार में संगठनात्मक संरचना भाजपा की है. लोजपा और रालोसपा के भी समर्थक समूह दिखते हैं, लेकिन हम का ऐसा कोई ढांचा बिहार में तैयार नहीं हो सका है, उसके पास वक्त की कमी भी रही, लेकिन उसमें महत्वाकांक्षी राजनेताओं का समूह हावी रहा. चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हम के कई नेताओं को झटका लगा है. इसी के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद सिंह ने हम से इस्तीफ़ा दे दिया. बताते हैं कि उन्हें खुद और समर्थकों के लिए मधुबनी में कम से कम पांच सीटें चाहिए थीं, जो संभव नहीं हो सका.

एनडीए के सहयोगी दलों में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई है. सीटों के आवंटन और उम्मीदवारों के चयन का काम जैसे ही ज़ोर पकड़ेगा, एनडीए दोहरे संकट का शिकार बनेगा. दलों में तनातनी बढ़ेगी और टिकटार्थियों का पलायन शुरू हो जाएगा. भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसे लेकर एनडीए के उसके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं. एनडीए में एक नया संकट है. घटक दल चाहते हैं कि उन्हें सीटें आवंटित कर दी जाएं, लेकिन भाजपा उनसे उन तथ्यों की पुख्ता जानकारी चाहती है, जो उनकी जीत के कारण बन सकते हैं. भाजपा ने पिछले दिनों बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों का आंतरिक सर्वेक्षण कराया है. उम्मीदवारों के सहयोगी दल के होने से कोई खास फ़र्क़ नहीं पड़ने जा रहा है, पर भाजपा उनकी जीत के प्रति एक आश्वस्ति चाहती है. एनडीए के खाते में उसे विधानसभा की 185 प्लस सीटें चाहिए. इसके लिए वह कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती. जीत की हर तरह की पुख्ता व्यवस्था वाली भाजपाई शैली सहयोगी दलों की कार्य-संस्कृति से शायद मेल नहीं खा रही है, अंतर्द्वंद्व का यह एक बड़ा कारण है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मगध

निर्दलीय और छोटे दल हमेशा देते रहे चुनौती

चौथी दुनिया ब्यूरो

छोटे-छोटे राजनीतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशी जीत भले न सके हों, लेकिन वे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव में चुनौती बनकर ज़रूर सामने आते हैं. हालांकि, कभी-कभी उन्हें सफलता भी मिल जाती है. मगध में 26 विधानसभा क्षेत्र हैं. यहां 2010 के चुनाव में औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह बाजी मारने में सफल रहे थे. वहीं दूसरी ओर इसी ज़िले के गोह विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी डॉ. रणविजय कुमार महज कुछ सौ वोटों की बदौलत जीत का मुंह देख सके थे. उन्हें 47,378 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी राजद प्रत्याशी राम अयोध्या प्रसाद यादव को 46,684 वोट मिले. यहां निर्दलीय राधे श्याम यादव ने 1,027 और बृजनंदन सिंह यादव ने 2,093 वोट हासिल कर राजद प्रत्याशी की जीत को हार में तब्दील कर दिया. दोनों को मिले वोट राजद के थे. इसी तरह गया ज़िले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव 53,079 वोट पाकर जीत हासिल की थी, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी जदयू प्रत्याशी मोहम्मद अहमद को 48,441 वोट मिले. यहां अनाम पार्टी के प्रत्याशी बब्लू रविदास ने तीर-धनुष चुनाव चिन्ह के सहारे 8,942 वोटों पर कब्जा जमाया था. उक्त वोट जदयू के थे. वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पारस नाथ सिंह ने

राजनैतिक विकल्प पार्टी का झंडा

5,919 और कमलेश कुमार वर्मा ने 13,693 वोट हासिल कर भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह की जीत का अंतर कम कर दिया था.

इस बार भी छोटे-छोटे दल एवं निर्दलीय प्रत्याशी मगध में अपने-अपने चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय होकर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों को परेशानी में डालने की तैयारी में जुट गए हैं. मगध में सपा, बसपा, माकपा एवं फारवर्ड ब्लॉक जैसे दल भी सिर्फ़ लोगों के बीच चर्चा में बने रहने के लिए चुनाव लड़ते हैं. इनके अलावा इस बार कुछ अन्य राजनीतिक दल भी भाजपा, जदयू, राजद एवं कांग्रेस जैसे दलों के सामने चुनौती पेश करने के मूड में हैं, जैसे भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी, राजनैतिक विकल्प पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी. भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी और राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी गया ज़िले में अधिक सक्रिय हैं, वहीं राजनैतिक विकल्प पार्टी जहानाबाद ज़िले में. भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी ने गया में लगातार कार्यक्रम करके और नियमित रूप से घर-घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चला रखा है, जिससे अन्य बड़े दलों के संभावित प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया है. इस पार्टी के घोषित प्रत्याशी रंजीत कश्यप भले न जीतें, लेकिन कहीं वह बड़ी संख्या में वोट काट ले गए, तो किसी की संभावित जीत एक बार हार में बदल सकती है. इसी तरह राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी का प्रचार कार्यक्रम चल रहा है. इसके अलावा विभिन्न बड़े एवं क्षेत्रीय दलों के टिकट से वंचित नेता भी बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने दल के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दे सकते हैं. मगध के जिन विधानसभा क्षेत्रों में बागी प्रत्याशियों के मैदान में उतरने की आशंका है, उनमें गया ज़िले के टिकारी, गुरुआ, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज एवं शेरघाटी, औरंगाबाद ज़िले के ओवरा, गोह, रफीगंज एवं नवीनगर, जहानाबाद ज़िले के जहानाबाद, अरवल एवं कुर्था और नवादा ज़िले के वारिसअलीगंज एवं गोबिंदपुर प्रमुख हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

आज चीन में बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं. चीन में ऑरडोन जैसे घोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर की तादाद बढ़ती जा रही है, जहां सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ़ रहने वाले ही नहीं हैं. भारत में भी नौकरियों की कमी, खाली पड़े फ्लैट, बैंकों द्वारा दिए भारी–भरकम कर्ज, जिनका लौटना मुमकिन नहीं दिख रहा और औने–पौने दामों पर बिकती फैक्ट्रियां अर्थव्यवस्था के दरकने की कहानी बयान कर रही हैं. हर बार हम जब शेयर बाज़ार में गिरावट देखते हैं, तो बाज़ार में सुधार की हमारी उम्मीद और बढ़ जाती है, लेकिन यह खेल वर्ष 2008 से चल रहा है.

बिखरता तिलिस्म, दरकती अर्थव्यवस्थाएं

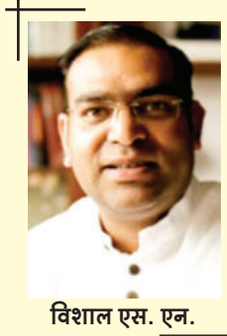

विशाल एस. एन.

एक बहुत पुरानी ग्रीक कहावत है, योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंग्थ कैन बी योर ग्रेटेस्ट वीकनेस. यानी आपकी सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी कमज़ोरी हो सकती है. यह कहावत आज की दुनिया में आउटसोर्सिंग मॉडल पर बिल्कुल सटीक बैठती है. 80–90 के दशक में सभी देशों ने अपनी सभी आर्थिक–सामाजिक समस्याओं का समाधान खोज लिया था. उस समय आर्थिक भूमंडलीकरण का बोलबाला था. किसी देश के बाज़ार के लिए किसी अन्य देश में उत्पाद बनाना भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही समझा गया, जिसमें अमेरिका एवं दूसरे पश्चिमी देशों के उत्पादों का भारत एवं चीन जैसे देशों में उत्पादन करने की प्रक्रिया को आउटसोर्सिंग कहा गया. पश्चिमी देशों को अब उत्पादन के झंझट से छुटकारा मिल गया था और भारत एवं चीन जैसे देशों में बनकर वही सामान कम मूल्य पर पश्चिमी देशों में उपलब्ध होने लगा. भारत एवं चीन जैसे विकासशील देशों में रोज़गार, निवेश और ढांचागत सुधार को बढ़ावा मिलने लगा तथा इससे भारत जैसे देशों में ग़रीबी से छुटकारा पाने का एक साधन मिल गया.

भारत एवं चीन जैसे देशों ने स्वयं को इस मॉडल के प्रति समर्पित किया. चीन ने सभी प्रकार के उत्पादों की क्षमताएं विकसित कीं. भारत ने सेवा एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में अपने आपको ढाला. हमारे देश के करोड़ों युवाओं को सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षित किया गया, रातोंरात हज़ारों इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, अंग्रेजी भाषा के उच्चारण के लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले और बंगलुरू, हैदराबाद, पुणे एवं गुड़गांव आदि शहरों में सेवाओं के केंद्र बने.

पश्चिमी देशों की कंपनियों में मुनाफा बढ़ने लगा, जिससे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगी. भारत एवं चीन जैसे देशों में तो नया देश गढ़ा जा रहा था. इस वजह से उनकी अर्थव्यवस्था लगातार दो अंकों में चल रही थी. यह मॉडल एकदम सही प्रतीत हो रहा था और काफी समय तक इस मॉडल ने काम भी किया. परंतु, जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में शेयर बाज़ारों में अरबों डॉलर की पूंजी पलक झपकते ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर गायब हो जाती है. रुपया डॉलर के मुक़ाबले 76 को पार कर जाता है और 80–82 से पहले ठहरता ही नहीं है. तमाम प्रयासों के बाद भी शेयर बाज़ार उठ नहीं पाता. तब यह सवाल उठता है कि कहीं अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत आउटसोर्सिंग ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी तो नहीं बन गई?

चीन की स्मार्ट सिटी जहां कोई रहने वाला नहीं है

सूरत का हीरा उद्योग

आउटसोर्सिंग निर्यात की तुलना में बिल्कुल अलग चीज थी, क्योंकि निर्यात में आपका उद्देश्य अपने देश के बाज़ार से अच्छी क़ीमत की आशा में चीजें बाहर भेजनी होती हैं, जबकि आउटसोर्सिंग में आपका अपना बाज़ार कहीं होता ही नहीं और आप पूरी तरह से अनजाने (एलियन) बाज़ार की मांग पर निर्भर होते हैं. आउटसोर्सिंग के मॉडल पर आधारित इन फैक्ट्रियों में जो उत्पाद बन रहे थे, उनका स्थानीय बाज़ार से कुछ लेना–देना नहीं था. वे ऐसे उत्पाद बना रही थी या ऐसी सेवाएं दे रही थीं, जिनकी कोई भी स्थानीय मांग नहीं है. पश्चिमी कंपनियों की अर्थव्यवस्था भी ऊपर की ओर चढ़ने लगी, लेकिन इसके साथ उन देशों से आम जनता की नौकरी के साथ–साथ क्रय शक्ति भी चली गई. भारत एवं चीन जैसे देशों में नौकरियां तो मिलीं, लेकिन कुछ ही लोगों को. पूरी दुनिया नौकरी–विहीन आर्थिक विकास (जॉबलेस ग्रोथ) की ओर बढ़ने लगी, जिससे अमीर–ग़रीब के बीच की आर्थिक खाई बढ़ने लगी. आम जनता की क्रय शक्ति कम होने के कारण इन उत्पादों और सेवाओं की मांग ख़त्म होने के कगार पर आ गई.

आज चीन में बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं. चीन में ऑरडोन जैसे घोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर की तादाद बढ़ती जा रही है, जहां सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ़ रहने वाले ही नहीं हैं. भारत में भी नौकरियों की कमी, खाली पड़े फ्लैट, बैंकों द्वारा दिए भारी–भरकम कर्ज, जिनका लौटना मुमकिन नहीं दिख रहा और औने–पौने दामों पर बिकती फैक्ट्रियां अर्थव्यवस्था के दरकने की कहानी बयान कर रही हैं. हर बार हम जब शेयर बाज़ार में गिरावट देखते हैं, तो बाज़ार में सुधार की हमारी उम्मीद और बढ़ जाती है, लेकिन यह खेल वर्ष 2008 से चल रहा है. जब भी शेयर बाज़ार में गिरावट होती है, तो अर्थशास्त्री कहने लगते हैं कि जल्दी ही अर्थव्यवस्था में V की आकृति में सुधार होगा. फिर वे अपनी भविष्यवाणी बदल देते हैं और कहने लगते हैं कि अभी सुधार में समय लगेगा और सुधार U की आकृति में होंगे. लेकिन, फिर भी जब सुधार का कोई संकेत नहीं दिखता, तो उन्हें W की आकृति में सुधारों की भविष्यवाणी करनी पड़ती है.

अभी हाल में विश्वविख्यात अर्थशास्त्री एवं रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने इंग्लैंड में बोलते हुए विश्व अर्थव्यवस्था के भयानक आर्थिक मंदी में जाने की आशंका व्यक्त की, परंतु अगले ही दिन सरकार की तरफ़ से स्पष्टीकरण आया कि यह विचार भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के नहीं हैं. तब हमें मानना पड़ेगा कि यह विचार एक निष्पक्ष एवं कुशल अर्थशास्त्री के हैं, जिन्होंने वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी की समय रहते सटीक भविष्यवाणी की थी. आशावाद अच्छा है, लेकिन अति आशावाद कभी–कभी हानिकारक होता है. हमारे नीति निर्माताओं की यह सोच है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के इस संकट से अछूता रहेगा, क्योंकि यहां की बड़ी आबादी और अंदरूनी मांग ही सब कुछ संभाल लेगी. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की अंदरूनी मांग है, लेकिन हम इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस मांग को चीनी कंपनियां पूरा नहीं करेंगी या किसी और देश की कंपनियां इस पर निगाह नहीं गड़ाएंगी?

आप बड़ी चतुराई से अपने उत्पादों एवं सेवाओं को दूसरे देशों में आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी समस्याओं को आउटसोर्स नहीं कर सकते. आज अगर भारत के सबसे संपन्न राज्यों में से एक में आरक्षण की मांग उठती है, तो हम यह नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि सूरत जैसे शहर, जो हीरे की पॉलिश के लिए पश्चिमी देशों की आउटसोर्सिंग का हब बना हुआ था, की लाखों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और लाखों लोग वहां नौकरियों से हाथ धो चुके हैं. जिस आउटसोर्सिंग के मॉडल को विश्व की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, वह आज सवालों के घेरे में है! अर्थनीति निर्माताओं एवं अर्थशास्त्रियों के सामने यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि जिस आउटसोर्सिंग के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का ताना–बाना बुना गया, कहीं वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी तो नहीं बन गई है? ■

(लेखक इंवेस्टमेंट बैंकर एवं जेन एडवाइजर्स के सीईओ हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

जल की असुरक्षा का सवाल घातक है

देश के 20 राज्यों के 2.5 करोड़ लोग फ्लोरोसिस एवं अन्य जल विषाक्तता से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोराइड और उससे होने वाली बीमारियों की गंभीरता की जानकारी सामने आए सात–आठ दशक बीत जाने के बावजूद न तो कोई प्रभावी कार्यवाही दिख रही है और न उसके निदान के लिए कोई ठोस कार्यक्रम लागू किए गए हैं. ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम बीमारियों से निपटने पर खर्च करने के बजाय पानी के प्रबंधन पर ध्यान दें.

कुमार कृष्णन

जल की असुरक्षा का मामला काफी गंभीर रूप ले चुका है. ग्रामीण एवं शहरी, दोनों इलाकों के करोड़ों लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है. आर्द्र भूमियों एवं भूमिगत जलधाराओं का कुप्रबंधन, वर्षा जल संचय करने वाले इलाकों का क्षरण, बार–बार सूखा, आबादी का अति संकेंद्रन, सतही एवं भूमिगत जलस्रोतों का प्रदूषण आदि इसके प्रमुख कारण हैं. इन समस्याओं के मूल में नीतियों की विफलता सबसे प्रमुख है. प्रबंधन, प्रदूषण एवं पानी के मूल्य से संबंधित नीतियों के अलावा जल संसाधनों पर महाकाय कॉरपोरेशनों और अभिजात्य तबके का कब्जा भी प्रमुख कारण है. भूमिगत पानी एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है. खेती, उद्योगों एवं शहरी ज़रूरतों के लिए पानी का दोहन देश के कई भागों में इस स्तर तक पहुंच चुका है कि भूमिगत जलधाराएं तेजी से सूखती जा रही हैं. ग्रामीण भारत में आधी से ज़्यादा भूमिगत जलराशियों की भरपाई उतनी तेजी से नहीं हो रही है, जितनी तेजी से उनका दोहन हो रहा है. संसद के एक सवाल के जवाब में सरकार ने भी कहा था कि देश के एक तिहाई ज़िलों में भूमिगत पानी पीने के लायक नहीं है, क्योंकि उसमें लोहे, फ्लोराइड, आर्सेनिक और खारेपन की मात्रा बहुत ज़्यादा है.

देश के 20 राज्यों के 2.5 करोड़ लोग फ्लोरोसिस एवं अन्य जल विषाक्तता से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोराइड और उससे होने वाली बीमारियों की गंभीरता की जानकारी सामने आए सात–आठ दशक बीत जाने के बावजूद न तो कोई प्रभावी कार्यवाही दिख रही है और न उसके निदान के लिए कोई ठोस कार्यक्रम लागू किए गए हैं. ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम बीमारियों से निपटने पर खर्च करने के बजाय पानी के प्रबंधन पर ध्यान दें. फ्लोराइड नॉलेज एंड एक्शन नेटवर्क एवं इंडिया वाटर पोर्टल की रिपोर्ट में जल में फ्लोराइड विषाक्तता से निपटने के लिए सुदूर इलाकों पर केंद्रित नीति पर ठोस कार्यक्रम बनाकर ज़मीनी स्तर पर उसे क्रियान्वित करने की ज़रूरत बताई गई है. झाबुआ एवं अन्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शोध करने वाले प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार सिकरवार ने बताया कि हाल के वर्षों में यह देखने में आया है कि फ्लोराइड की अधिक मात्रा गुर्दे के साथ ही कई प्रकार के उत्तकों एवं एंजाइम की क्रिया–विधि को भी प्रभावित करने लगी है. सबसे दु:खद बात यह है कि फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले सात से 12 वर्ष के बच्चे हैं, जो दांत संबंधी फ्लोरोसिस से ग्रस्त हैं.

रिपोर्ट में विशेषज्ञों मीनाक्षी अरोड़ा एवं केसर ने कहा कि आज से तीन–चार दशक पहले तक पानी का बंटवारा कम से कम कृषि जल, पेयजल, कच्चा पानी जैसे विभिन्न रूपों में नहीं होता था. कुओं, तालाबों, झीलों एवं नदियों में कचरा डालकर उन्हें गंदा करने का काम किया गया. पिछले तीस–चालीस वर्षों में हमारी निर्भरता भूजल पर हो चली है, जिसने भूतल स्थित लवण पेयजल में ला दिए हैं. आज भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, आयरन एवं नाइट्रेट आदि काफी मात्रा में पाए जा रहे हैं. इन तत्वों से युक्त पानी ही बच्चों में होने वाली अधिकतर बीमारियों का कारण है. ग़रीब और विकासशील देशों में 80 फ़ीसद से ज़्यादा रोग जलजनित हैं. एक शोध में पाया गया है कि झाबुआ एवं उससे लगे क्षेत्रों में फ्लोराइड की मात्रा 1.24 पीपीएम से 7.38 पीपीएम तक पाई गई है, जो सामान्य स्तर 1.5 पीपीएमी से बहुत ज़्यादा है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवं इंडियन स्टैंडर्ड आदि ने पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा 1.5 पीपीएम निर्धारित की है.

जल से जुड़े विषयों पर काम करने वाले एन देवराज रेड्डी ने कहा कि जब पीने के पानी में 1.5 से तीन पीपीएम तक फ्लोराइड की मात्रा होती है, तो उससे डेंटल फ्लोरोसिस होता है. यह पीले धब्बों में परिवर्तित होने लगता है. अंत में दांतों का टूटना शुरू हो जाता है. पीने के पानी में तीन से 10 पीपीएम तक की मात्रा में फ्लोराइड होने और कई वर्षों तक उसका निरंतर सेवन करने से स्केलेटल फ्लोरोसिस या अस्थि फ्लोरोसिस हो जाता है. इसके कारण शरीर के अंग साधारण तरीके से मोड़े नहीं जा सकते और रोगी स्वयं चल–फिर भी नहीं सकता. सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरराजन कृष्णन के अनुसार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार समेत कई राज्यों में फ्लोरोसिस से लोगों के शरीर पर घातक प्रभाव पड़ रहा है. इससे बच्चों एवं बुजुर्गों की हड्डियां और दांत कमज़ोर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे क़दम कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि संबंधित नीतियां और कार्यक्रम ज़मीनी हक़ीक़त को ध्यान में रखकर नहीं तैयार किए जा रहे हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आर्सेनिक और देश के विभिन्न राज्यों के भूजल में फ्लोरिन–नाइट्रेट की बहुतायत है. अत: इस दिशा में समुचित प्रयास करने की ज़रूरत है. भारत में पानी का इस्तेमाल लगभग 750 अरब घनमीटर है, जो उपलब्ध जल भंडारों से लगभग 1969 अरब घनमीटर कम है. लेकिन, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक हमारे जल भंडार और पानी की हमारी ज़रूरत, दोनों बराबर हो जाएंगे तथा वर्ष 2050 तक पानी का इस्तेमाल उपलब्ध पानी की मात्रा से ऊपर जा चुका होगा. यह स्थिति तब है, जब हम पानी के केवल मानवीय उपयोग की बात करते हैं. यदि हम इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र और दूसरी प्रजातियों के लिए पानी की ज़रूरतों का हिसाब जोड़ दें, तो हम पहले ही संकट में पहुंच चुके हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

इलाहबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले से एक लाख 75 हज़ार शिक्षा–मित्रों की ज़िंदगी अधर में फंस गई है. इससे आहत क़रीब दर्जन भर शिक्षा–मित्रों की अलग–अलग जगहों पर मौत हो गई. इनमें कुछ शिक्षा–मित्रों की सदमे से मौत हुई, तो कुछ ने आत्महत्या कर ली. बरेली और सीतापुर समेत कई ज़िलों के हज़ारों शिक्षा–मित्रों ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इच्छा–मृत्यु की इजाजत देने की मांग की है. गाजीपुर में शिक्षा–मित्र ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली, तो लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ ब्लॉक के शिक्षा–मित्र ने ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली.

नाराज़ शिक्षा-मित्र जबरन बंद करा रहे स्कूल, क़ानून व्यवस्था का संकट गहराया

सरकार लड़ेगी शिक्षा-मित्रों की लड़ाई

उत्तर प्रदेश में शिक्षा-मित्रों की नौकरी पर क़ानून की कुल्हाड़ी भीषण बेरोज़गारी दूर करने के प्रयासों पर भारी पड़ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबसे शिक्षा-मित्रों को सरकारी शिक्षक मानने से इंकार किया है, तबसे प्रदेश में बेसिक शिक्षा ठप्प है. स्कूल बंद पड़े हैं. शिक्षा-मित्रों का संघर्ष सड़क पर है. अदालत के फ़ैसले से क्षोभ इतना है कि आत्महत्याएं हो रही हैं या सदमे से शिक्षा-मित्रों की मौत हो रही है. ऐसी तक़रीबन दर्जन भर मौतों से चिंतित उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शिक्षा-मित्रों को सांत्वना देने और उनके पक्ष में आगे की क़ानूनी लड़ाई लड़ने की घोषणा की है.

प्रभात रंजन दीन

बीते 12 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक लाख 75 हज़ार शिक्षा–मित्रों को प्राथमिक विद्यालयों का अध्यापक बनाए जाने का सरकारी आदेश खारिज करने का फ़ैसला सुनाया. अदालत ने निर्धारित योग्यता न होने और बिना संस्तुति वाले पदों के आधार पर इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया. अधिवक्ता हिमांशु राघव और अन्य की याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की तीन सदस्यीय पीठ ने एक लाख 75 हज़ार शिक्षा–मित्रों का समायोजन निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा कि सरकार की तरफ़ से नियमों में किया गया संशोधन असंवैधानिक था. पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को समायोजन करने का अधिकार नहीं है. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर नियुक्त एक लाख 75 हज़ार शिक्षा–मित्रों को प्रशिक्षण के बाद प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनाने के प्रस्ताव को पिछले साल मंजूरी दी थी. मंत्रिमंडल की बैठक के दो दिनों बाद ही बेसिक शिक्षा निदेशालय को नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया और महज तीन हज़ार पांच सौ रुपये मासिक मानदेय पर काम करने वाले शिक्षा–मित्र बाकायदा निर्धारित वेतनमान पर सहायक शिक्षक बना दिए गए. इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह भी कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में कोई भी ढील देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल 19 जून को शिक्षक नियमावली 1981 में संशोधन कर शिक्षा–मित्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करने का शासनादेश जारी किया था. सरकार ने शिक्षा–मित्रों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर की थी. नियमों के तहत सहायक शिक्षक को कम से कम स्नातक एवं बीटीसी होना आवश्यक है, लेकिन शिक्षा–मित्र केवल 12वीं पास हैं. उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 में शिक्षा–मित्र योजना शुरू की गई थी. इसके तहत इंटर पास युवक–युवतियों को उनके गांव या पास के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था. समाजवादी पार्टी ने 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा–पत्र में शिक्षा–मित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने का वादा किया था. हाईकोर्ट के फ़ैसले से एक लाख 75 हज़ार शिक्षा–मित्रों की ज़िंदगी अधर में फंस गई है. इससे आहत क़रीब दर्जन भर शिक्षा–मित्रों की अलग–अलग जगहों पर मौत हो गई. इनमें कुछ शिक्षा–मित्रों की सदमे से मौत हुई, तो कुछ ने आत्महत्या कर ली. बरेली और सीतापुर समेत कई ज़िलों के हज़ारों शिक्षा–मित्रों ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इच्छा–मृत्यु की इजाजत देने की मांग की है. गाजीपुर में शिक्षा–मित्र ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली, तो लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ ब्लॉक के शिक्षा–मित्र ने ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली.

इसी तरह बस्ती ज़िले के भानपुर में एक शिक्षा–मित्र की मौत सदमे के कारण दिमाग की नस फटने से हो गई. एटा में समायोजित शिक्षक महिपाल सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. कन्नौज में जनखत स्थित प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षा–मित्र बाबू सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मिर्जापुर में भी शिक्षा–मित्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बहराइच में चित्तौरा के जानीजोत गांव में शिक्षा–मित्र पूनम देवी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. शाहजहांपुर में महिला शिक्षा–मित्र निर्मला को हाईकोर्ट का फ़ैसला सुनते ही दिल का दौरा पड़ा, उनकी हालत गंभीर है. अलग–अलग स्थानों से ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही हैं. शिक्षा–मित्रों की मौतों से चिंतित राज्य सरकार के हवाले से प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी को ऐलान करना पड़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ है और वह हाईकोर्ट के निर्णय के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. बेसिक शिक्षा मंत्री ने हताश शिक्षा–मित्रों से अपील की है कि वे धैर्य एवं सूझबूझ से काम लें और कोई ऐसा अनुचित क़दम न उठाएं, जिससे उन्हें और उनके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़े. हाईकोर्ट के फ़ैसले के 24 घंटे के दरम्यान ही प्रदेश में सात शिक्षा–मित्रों ने जान दे दी थी. राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने घोषणा की कि शिक्षा–मित्रों की अस्वाभाविक मौतों के मामले में सरकार पीड़ित परिवारों को पांच–पांच लाख रुपये का मुआवज़ा देगी. सभी ज़िलों के डीएम से कहा गया कि इन मामलों की जांच कर मुआवज़ा दें.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है. हाईकोर्ट के फ़ैसले से नाराज़ शिक्षा–मित्र प्रदेश में जगह–जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूलों को बंद करा रहे हैं. शिक्षा–मित्रों के विरोध के कारण प्रदेश के 70 फ़ीसद स्कूल जबरन बंद करा दिए गए. रायबरेली, बरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशांबी, प्रतापगढ़, सीतापुर, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, वाराणसी, अमेठी, हरदोई समेत कई ज़िलों में शिक्षा–मित्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और वहां स्कूल बंद कराए जा रहे हैं. कई ज़िलों में सैकड़ों स्कूलों में ताले नहीं खुले, तो लखनऊ, बस्ती, बरेली, अंबेडकरनगर में शिक्षा–मित्रों ने स्कूल पहुंच कर कक्षाओं में ताले डाल दिए और बच्चों को घर भेज दिया. ज़्यादातर ज़िलों में मिड डे मील नहीं बंटा. वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के बाहर घंटों प्रदर्शन हुआ और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 23 अगस्त, 2010 के पैरा चार में संशोधन की मांग उठाई गई है. शिक्षा–मित्रों ने ऐलान किया है कि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को बरेली में घुसने नहीं दिया जाएगा. ज़िलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ज़रिये शिक्षा–मित्रों के संगठनों से बातचीत करके उनके द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों के बजाय उन्हें क़ानूनी विकल्पों पर भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है.

शिक्षा–मित्र उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरी तैयारी से केस की पैरवी न करने का आरोप लगा रहे हैं. केंद्र सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है. लखनऊ में राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी नई शिक्षा नीति पर आयोजित बैठक में शरीक होने आईं, तो वहां भी शिक्षा–मित्रों ने प्रदर्शन किया. बाद में शिक्षा–मित्रों के तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से स्मृति ने अकेले में बातचीत की. लखनऊ शिक्षा–मित्र संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार यादव ने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आदेश की प्रति मिलने के बाद अदालत की आपत्तियां दूर करने की कोशिश की जाएगी और मामले का जल्द ही समाधान निकाला जाएगा. ■

भेदभाव का आरोप

उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि शिक्षा–मित्रों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश से भेदभाव किया जा रहा है. केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उत्तराखंड में बिना टीईटी परीक्षा दिए लोग शिक्षक बन गए. मौजूदा सरकार में ही महाराष्ट्र में बिना टीईटी किए लोग शिक्षक बन गए. यह भेदभाव ठीक नहीं है. हमने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. चौधरी ने शिक्षा–मित्रों से कहा, मैं आपका मुख्य अभिभावक हूं और आपके हितों की रक्षा के लिए जब हमने आगे क़दम बढ़ाए हैं, तो आपको धैर्यपूर्वक न्याय प्राप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए. हमारी परिषदीय शिक्षा में आपके बहुमूल्य योगदान को सरकार समझती है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने यह फ़ैसला किया है कि शिक्षा–मित्रों के हित में सरकार हर क़दम उठाएगी. ■

शिक्षा–मित्रों को सपा का समर्थन

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले से शिक्षा–मित्रों में आक्रोश और निराशा है. शिक्षा–मित्रों के साथ समाजवादी पार्टी की पूरी सहानुभूति है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उनके निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की जाएगी. शिक्षा–मित्रों को न्याय दिलाने में समाजवादी पार्टी और सरकार कतई पीछे नहीं रहेगी. समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र 2012 में शिक्षा शीर्षक के तहत स्पष्ट वादा किया है कि प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा–मित्रों को नियमित करते हुए उन्हें समायोजित कर दिया जाएगा. समाजवादी पार्टी ने शिक्षा–मित्रों को जो भरोसा दिलाया है, उसे अवश्य पूरा किया जाएगा. ■

भाजपा सांसद ने सरकार को दोषी ठहराया

मोहनलालगंज से भाजपा के सांसद एवं पारख महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर ने शिक्षा–मित्रों की सेवा समाप्ति के फ़ैसले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यदि शिक्षा–मित्रों को सहायक अध्यापक घोषित न करके सहायक अध्यापकों के बराबर वेतनमान देने एवं नियमित करने का निर्णय किया होता, तो उन्हें हार का मुंह न देखना पड़ता. अभी भी समय है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा–मित्रों को नियमित करके सहायक अध्यापक का पद न देकर उनके बराबर वेतनमान देने का अध्यादेश जारी कर दे, तो शिक्षा–मित्रों की पीड़ा ख़त्म की जा सकती है. भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सरकार ने जानबूझ कर ऐसी स्थिति पैदा की है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट को शिक्षा–मित्रों के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ा. शिक्षा–मित्रों की इस दुर्दशा के पीछे समाजवादी पार्टी की सुनियोजित राजनीति है, जिसे समझने और समझाने की ज़रूरत है. ■

368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन!

भीषण बेरोज़गारी के मौजूदा दौर में हाईकोर्ट शिक्षा–मित्रों की नौकरी पर कुल्हाड़ी चला रही है, वहीं दूसरी तरफ़ स्थिति यह है कि चपरासी के पद के लिए पीएचडी धारक और इंजीनियर बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश सचिवालय में चपरासियों के लिए निकाली गई 368 रिक्तियों पर 23 लाख आवेदन आए. इन आवेदनों से उत्तर प्रदेश सरकार मुसीबत में फंस गई है. बड़ी मुश्किल यह भी है कि चपरासी के इन 368 पदों के लिए आए 23 लाख आवेदनों में से 255 आवेदक पीएचडी, 25 हज़ार आवेदक एमएससी, एमकॉम एवं एमए हैं, वहीं डेढ़ लाख से ज़्यादा आवेदक बीटेक, बीएससी एवं बीकॉम हैं. मुश्किल यह है कि इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू अगर एक अक्टूबर से भी शुरू होता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास केवल 532 दिन बचेंगे. जबकि प्रत्येक आवेदक को थोड़ा–थोड़ा समय भी मिला, तो इंटरव्यू की औपचारिकता पूरी होने में 12 साल लग जाएंगे. सपा के पिछले कार्यकाल में भी सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हुई थी. तब सवा लाख आवेदन निपटाने के लिए चार बोर्ड बनाए गए थे. क़रीब आठ महीने तक इंटरव्यू चला, तब जाकर रिजल्ट निकाला जा सका था. उस आधिकारिक ब्यौरे को बतौर उदाहरण सामने रखें, तो इन 23 लाख आवेदनों को निपटाने में कितना समय लगेगा, इसकी कल्पना सहज की जा सकती है. सरकार को आवेदनों के निपटारे की क़ानूनी प्रक्रिया का भी ख्याल रखना होगा. इस प्रक्रिया का उल्लंघन किए जाने के कारण ही लाखों शिक्षा–मित्रों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. सचिवालय प्रशासन के सचिव प्रभात मित्तल ने कहा भी कि आवेदन काफी ज़्यादा आए हैं. इस पर विचार किया जाएगा कि इंटरव्यू के लिए कितने पैनल बनाए जाएं और उसे कैसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

अदालत के इस आदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं. लखनऊ की सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मुक़दमा दर्ज करने और अदालत को इस केस की कार्रवाई की जानकारी देने का आदेश दिया है. अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लोकायुक्त के यहां शिकायत की थी. अमिताभ ठाकुर का आरोप है कि उसके बाद से ही उन्हें फोन पर धमकियां मिलने लगी थीं. 10 जुलाई, 2015 को शाम 4.43 बजे आए फोन पर मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सुधर जाने की हिदायत दी और कहा था, जसराना वाली घटना भूल गए?

आईपीएस अधिकारी को फोन पर धमकी देने का मामला

मुलायम के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने का आदेश

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में अदालत ने मुलायम सिंह यादव के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. 16 सितंबर को लखनऊ की सीजीएम अदालत से जारी इस आदेश से अचानक प्रदेश और देश की सियासत गरमा गई है. मुलायम पर मुक़दमा दर्ज करने का अदालती आदेश आते ही सक्रिय हुई अखिलेश सरकार ने सतर्कता जांच प्रकरण में अमिताभ पर भी मुक़दमा ठोंक दिया. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव द्वारा 10 जुलाई, 2015 को आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने का मामला लगातार सुर्खियों में रहा. 11 जुलाई को अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाया था. अमिताभ ठाकुर का आरोप था कि मुलायम सिंह ने उन्हें फोन पर सुधर जाने की धमकी दी. दोनों के बीच बातचीत का वॉयस रिकॉर्ड उनकी पत्नी ने जारी किया था. इस मामले में सरकार ने सख्ती और नरमी यानी दोनों तरीके इस्तेमाल कर मामला निपटाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी.

आख़िरकार सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने अमिताभ ठाकुर के परिवाद पर प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए हजरतगंज के इंस्पेक्टर को समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया. उन्होंने मामले की विवेचना कर प्रगति से अदालत को अवगत कराने के आदेश भी दिए हैं. इससे पूर्व अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अखिलेश कुमार अवस्थी ने तथ्य रखते हुए फिरोजाबाद में ठाकुर के एसपी रहने के समय जसराना में उनके साथ विधायक रामवीर सिंह द्वारा की गई मारपीट से संबंधित एफआईआर और आरोप-पत्र की प्रति साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की. अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने के लिए 11 जुलाई को हजरतगंज के इंस्पेक्टर विजयमल सिंह यादव को तहरीर दी थी. एफआईआर दर्ज न किए जाने पर 23 जुलाई को लखनऊ के एसएसपी राजेश पांडेय को प्रार्थना-पत्र भेजा गया था. हजरतगंज के इंस्पेक्टर ने 17 जुलाई को पत्र लिखकर ठाकुर को सूचित किया था कि उनकी शिकायत की जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. ठाकुर ने उस जांच को विधि विरुद्ध बताते हुए 31 जुलाई को सीजेएम के समक्ष एफआईआर दर्ज करने हेतु आवेदन किया था, जिस पर हजरतगंज के इंस्पेक्टर ने यह आख्या दी थी कि ठाकुर ख्याति पाने के लिए यह आरोप लगा रहे हैं.

अदालत के इस आदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं. लखनऊ की सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मुक़दमा दर्ज करने और अदालत को इस केस की कार्रवाई की जानकारी देने का आदेश दिया है. अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लोकायुक्त के यहां शिकायत की थी. अमिताभ ठाकुर का आरोप है कि उसके बाद से ही उन्हें फोन पर धमकियां मिलने लगी थीं. 10 जुलाई, 2015 को शाम 4.43 बजे आए फोन पर मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सुधर जाने की हिदायत दी और कहा था, जसराना वाली घटना भूल गए? उल्लेखनीय है कि जसराना का मामला वर्ष 2006 में हुआ था, जब अमिताभ फ़िरोज़ाबाद में एसपी थे. सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ धमकी का मामला बनता है. उन्होंने ललित कुमारी बनाम यूपी सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उक्त केस में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने कहा था कि अगर संज्ञेय अपराध बनता है, तो पुलिस को मामला दर्ज करना ही होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार ने भी अमिताभ पर ठोंक दिया मुक़दमा

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के ख़िलाफ़ सीधा मोर्चा खोलने वाले निलंबित आईजी अमिताभ ठाकुर के ख़िलाफ़ सतर्कता अधिष्ठान ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में भ्रष्टाचार का मुक़दमा दर्ज कराया. ठाकुर पर आय से 83 प्रतिशत अधिक व्यय का आरोप है. शासन के निर्देश के बाद सतर्कता अधिष्ठान ने यह कार्रवाई की है. सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक महेश सिंह ने 16 सितंबर को ही गोमती नगर थाने में अमिताभ ठाकुर के ख़िलाफ़ तहरीर दी. तहरीर के आधार पर ठाकुर के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आय से अधिक संपत्ति के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया. ठाकुर पर आरोप है कि उनकी आय के जो भी ज्ञात स्रोत हैं, उसके सापेक्ष जांच की गई अवधि में उनकी 98 लाख 12 हज़ार 164 रुपये अवैध आय मिली है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के लिए निर्धारित अवधि में अमिताभ और उनके आश्रित परिवारीजनों ने वैध स्रोत से एक करोड़ 17 लाख 99 हज़ार 465 रुपये की आय अर्जित की, जबकि इसके सापेक्ष दो करोड़ 16 लाख 11 हज़ार 629 रुपये व्यय किए. अमिताभ पर आरोप है कि पर्याप्त अवसर देने के बावजूद उन्होंने इस संदर्भ में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया. वर्ष 1992 बैच के आईपीएस अमिताभ ठाकुर के ख़िलाफ़ सतर्कता अधिष्ठान के संयुक्त निदेशक ने खुली जांच पूरी कर शासन को चार सितंबर को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था. इस रिपोर्ट पर विचार के बाद शासन के सतर्कता विभाग के उपसचिव एसपी सिंह ने सतर्कता अधिष्ठान के निदेशक भानु प्रताप सिंह को पत्र लिखकर अन्वेषण (मुक़दमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने) की आख्या उपलब्ध कराने को कहा था. निदेशक भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर मुक़दमा दर्ज कराया गया. उल्लेखनीय है कि अमिताभ ठाकुर के ख़िलाफ़ लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने भी पिछले माह जांच की सिफारिश की थी.

अमिताभ ठाकुर का कहना है कि यह जांच निष्पक्ष नहीं है. उनके परिवार वालों की संपत्ति को उनकी निजी संपत्ति बताया गया है. जांच एजेंसी ने उन्हें एक बार भी नहीं बताया कि उन पर कौन-सी संपत्ति रखने का आरोप है और उसका आधार क्या है? अमिताभ ने कहा, मैं सतर्कता अधिष्ठान द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर का स्वागत करता हूं और यह मानता हूं कि किसी अधिकारी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत मिलने पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से यह पूरी जांच एकपक्षीय तरीके से हमारी बात सुने बगैर की गई और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई, वह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप की गई कार्रवाई दिखती है, जो मेरी दृष्टि में नितांत दुःखद है. ■

राव धीरज सिंह जेल कैसे पहुंचे-२

पैसा हड़पने के लिए फर्जी मुक़दमा

नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया

आरके पुरम क्राइम ब्रांच पहुंचने के बाद राव धीरज सिंह ने देखा कि वहां शैलेंद्र सिंह की कार खड़ी है. पुलिस, राव धीरज सिंह को एक कमरे में ले गई, जहां शैलेंद्र सिंह दो पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ था और का इंतज़ार कर रहा था. दो घंटे लंबी पूछताछ के बाद पुलिस वाले सिंह को दूसरे कमरे में ले गए, जहां नीरा, करुणा और करण बैठे हुए थे. करुणा ने सिंह से कहा कि वे लोग इस बात को भूल जाना चाहते हैं, अगर सिंह समझौते के लिए तैयार हो जाएं. सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह के सेटलमेंट की बात ये लोग कर रहे हैं, आख़िर उसे क्यों परेशान किया जा रहा है और वह भी तब, जबकि उसने नीरा के कहने पर करण को समझाने की कोशिश की थी?

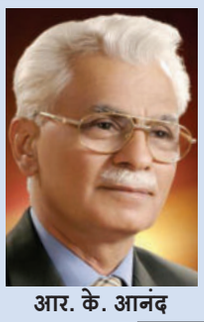

आर. के. आनंद

चार अप्रैल, 2003 को राव धीरज सिंह के चचेरे भाई (कजन) चेतन, जो करण के साथ रह रहा था, ने सिंह से कहा कि नीरा और करुणा उनसे अपने फार्म हाउस पर मिलना चाहती हैं, लेकिन सिंह ने मिलने से मना कर दिया. वह दोबारा करण से मिलना नहीं चाहते थे. इसके बजाय सिंह ने उन सभी लोगों को अपने घर पर आमंत्रित किया, लेकिन करण के बिना. मतलब वह करण से दोबारा किसी भी क़ीमत पर मिलने के लिए तैयार नहीं थे. अगले दिन सुबह साढ़े पांच बजे सिंह के घर की डोरबेल बजी. जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो सामने चार व्यक्तियों को देखा. उनके साथ चेतन भी था. उनमें से एक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस का कार्ड दिखाया और खुद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बख्शी बताया. उस पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें करण से एक शिकायत मिली है कि सिंह ने उसके साथ मारपीट की है. इसलिए सिंह को उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा और जांच में सहयोग करना होगा.

आरके पुरम क्राइम ब्रांच पहुंचने के बाद राव धीरज सिंह ने देखा कि वहां शैलेंद्र सिंह की कार खड़ी है. पुलिस सिंह को एक कमरे में ले गई, जहां शैलेंद्र सिंह दो पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ था और सिंह का इंतज़ार कर रहा था. दो घंटे लंबी पूछताछ के बाद पुलिस वाले सिंह को दूसरे कमरे में ले गए, जहां नीरा, करुणा और करण बैठे हुए थे. करुणा ने सिंह से कहा कि वे लोग इस बात को भूल जाना चाहते हैं, अगर सिंह समझौते के लिए तैयार हो जाएं. सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह के सेटलमेंट की बात ये लोग कर रहे हैं, आख़िर उसे क्यों परेशान किया जा रहा है और वह भी तब, जबकि उसने नीरा के कहने पर करण को समझाने की कोशिश की थी?

करुणा ने सेटलमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था. इसका मतलब था कि सिंह वे सारी फाइलें नीरा को सुपुर्द कर दें, जो एक साथ काम करने के दौरान सिंह के पास रह गई थीं. असल में सिंह के पास उन सभी कामों के कान्ट्रैक्ट पेपर्स थे, जो उन्होंने साथ किए थे. इसके अलावा करुणा ने यह भी कहा कि सिंह उन सारे लंबित भुगतानों को भूल जाएं, जो उन्हें नीरा से लेने हैं. सिंह बिल्कुल भौचक्के रह गए, लेकिन वह डिगे नहीं. नीरा और करण जब जाने लगे, तो अंतिम बात उन्होंने यह कही कि अब इस केस में भुगतो. इस पूरी घटना के दौरान एक पुलिस वाला सिंह के हाथ बांधे रहा. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. पुलिस वालों ने सिंह के ऑफिस की तलाशी ली और वे कार्टून भर-भर के पेपर्स ले गए. 28 अप्रैल, 2003 को सिंह को जेल भेज दिया गया. उन पर करण का अपहरण करके उसकी मां से फिरौती लेने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया. यह केस सेक्शन 364-ए, 365, 307, 120-बी/34 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया, जिसके आधार पर सिंह क़रीब डेढ़ साल तक जेल में रहे और जमानत दिलाने में मेरी मदद के बाद वह रिहा हो सके. नीरा के प्रतिशोध का यह चरम था. उसने इसमें अपनी तमाम राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक ताकत और संपर्क का इस्तेमाल किया.

क्योंकि सिंह सब जानते थे

सिंह, जो नीरा के सबसे क़रीबी सहयोगी थे, उनके साथ नीरा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने अपने परिवार के साथ मिलकर सिंह के ख़िलाफ़ एक झूठा मुक़दमा किया? कई बार उसने सिंह को अपने पति के तौर पर पेश किया था, उसकी पत्नी बनकर दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए थे. फिर ऐसा क्यों हुआ?

असल में नीरा सिंह को सबक सिखाना चाहती थी. दोनों में मतभेद थे. वजह, 1990 से 2003 के बीच जो भी डील दोनों ने मिलकर कराईं, उनमें से सिंह अपना हिस्सा मांग रहे थे. यह मांग ग़लत नहीं थी. सिंह अपना हक़ मांग रहे थे. लेकिन, नीरा की ज़िंदगी में मानवीय संबंधों से अधिक पैसे का महत्व था.

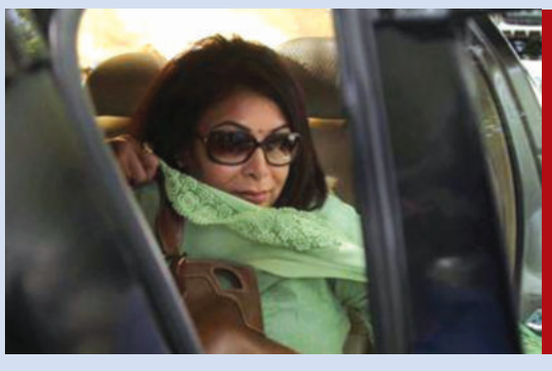

नीरा को अनंत कुमार से कैबिनेट मीटिंग के विवरण और अन्य निर्णय पहले ही मिल जाते थे और वह उन्हें बेचती थी. सिंह ने इसका विरोध किया था. नीरा ऐसे पेपर्स इच्छुक पार्टियों को दिखाकर डील के लिए तैयार करती थी या फिर विदेशी कंपनियों को दिखाकर यह जताती थी कि उसकी सरकार में कितनी पहुंच है.

यह उसने कई बार साबित किया था. मैं यहां कुछ ऐसे बिंदुओं की चर्चा करूंगा, जो बताएंगे कि आख़िर दोनों अलग क्यों हुए? दोनों के बीच ऐसी नौबत क्यों आई?

1- राडिया की अनंत कुमार के साथ हुई डीलिंग में सिंह को अलग रखा गया. यह पर्सनल और सीक्रेट डील थी.

2- नीरा सहारा एयरलाइंस के वरिष्ठ स्टाफर्स को तोड़ने की कोशिश कर रही थी. सिंह उसके ख़िलाफ़ थे. सिंह मानते थे कि यह काम ठीक नहीं होगा, क्योंकि सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय ने हमेशा उनकी मदद की और खासकर तब, जब नीरा और सिंह का काम सही नहीं चल रहा था.

3- नीरा को अनंत कुमार से कैबिनेट मीटिंग के विवरण और अन्य निर्णय पहले ही मिल जाते थे और वह उन्हें बेचती थी. सिंह ने इसका विरोध किया था. नीरा ऐसे पेपर्स इच्छुक पार्टियों को दिखाकर डील के लिए तैयार करती थी या फिर विदेशी कंपनियों को दिखाकर यह जताती थी कि उसकी सरकार में कितनी पहुंच है.

4- सिंह को संदेह तो था, लेकिन वर्ष 2000 में यह यकीन हो गया कि नीरा और अनंत कुमार के संबंध घनिष्ठ हो चुके हैं. भावनात्मक रूप से नीरा अब सिंह से दूरी बनाने लगी थी.

5- सिंह ने अपनी बिजनेस डीलिंग नीरा से अलग करने का फ़ैसला किया. सिंह ने नीरा के उस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था कि वह नाम के लिए उससे शादी कर लें, ताकि नीरा दुनिया को और खासकर, तेजस्विनी (अनंत कुमार की पत्नी) को दिखा सके कि वह एक शादीशुदा महिला है और अनंत कुमार में उसकी दिलचस्पी सिर्फ़ प्रोफेशनल कारणों से है.

6-मार्च, 2002 में सिंह ने गगन नामक महिला से शादी कर ली. नीरा ने झूठा ही सही, लेकिन खुद को सिंह की दोस्त दिखाते रहने की कोशिश की. उसने सिंह और उनकी पत्नी को अपने घर पर पार्टी में भी बुलाया. सिंह के ज़ोर देने पर नीरा ने उन्हें उनके हिस्से के बिजनेस शेयर देने का फ़ैसला किया. यह पैसा चार किस्तों में देना तय हुआ था.

7- लेकिन सिंह पहली किस्त मिलने से पहले ही तिहाड़ पहुंच चुके थे.

जारी...

(मशहूर वकील आर. के. आनंद क्लोज एनकाउंटर्स विद नीरा राडिया के लेखक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

1. दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के छात्र अपनी डिग्री को मान्यता दिलाने के लिए धरना देते हुए. 2. खुद को परेशान किए जाने के ख़िलाफ़ सीएम हाउस के पास पंजाब से आए अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करती हुईं अमनदीप कौर. 3. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में मतदान के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करती छात्राएं. 4. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विजयी उम्मीदवार अपनी जीत का जश्न मनाते हुए. 5. नई दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद बाहर निकलते बीएसएफ महानिदेशक डीके पाठक और पाकिस्तानी रेंजर्स (पंजाब) के महानिदेशक उमर फारूक बुर्की. 6. 1965 के भारत-पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के मौक़े पर लगाई गई विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन करते रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वित्त मंत्री अरुण जेटली और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद. 7.मुंबई में गणेश चतुर्थी की धूम.

शेखावाटी

हाईटेक खेती ने जीवन में बिखेरे खुशियों के रंग

मोरारका फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खेती करने का तरीक़ा बताकर उन्हें नया जीवन दिया है. वास्तव में किसानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उनके खेत में अधिक से अधिक अनाज पैदा हो और ज़मीन की उर्वरता पर भी उसका कोई असर न पड़े. रासायनिक खेती का सबसे बड़ा नुक़सान यही था कि कुछ समय तक पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन ज़मीन की उर्वरता तेज़ी से घटने लगती थी, लेकिन अब जैविक खेती के ज़रिये किसानों को इस परेशानी से छुटकारा मिल चुका है. मोरारका फाउंडेशन हाईटेक विधि सिखा कर किसानों को स्वावलंबी एवं आधुनिक बनाने का कार्य कर रहा है. शेखावाटी की नवलगढ़ तहसील के खिरोड़ गांव निवासी किसान अभिषेक शर्मा ने अमेरिका के थंडरबर्ड स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट से एमबीए करने के बाद खेती को बतौर करियर चुना और पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन में सफलता हासिल की. एमबीए करने के दौरान अमेरिका में जैविक खेती के कई हाईटेक फार्म देखने के बाद हाईटेक खेती का विचार उनके मन में आया.

आदित्य नारायण पांडेय

देश के ज़्यादातर किसान अब भी पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं, जो अक्सर घाटे का सौदा साबित होती है. यही वजह है कि देश में किसान आत्महत्या की समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. सन् 1960-70 के दशक में भारत में खाद्य पूर्ति के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई. हरित क्रांति से तात्पर्य था कि कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन करना, लेकिन इसके लिए अंधाधुंध रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया. नतीजतन, शुरुआत में पैदावार तो बढ़ी, लेकिन धीरे-धीरे खेतों की उर्वरा शक्ति कम होती गई. आज हालत यह है कि किसान कर्ज लेकर अपने खेतों में जमकर खाद एवं रासायनिक कीटनाशक डालते तो हैं, लेकिन उन्हें उतनी उपज भी नहीं मिलती, जिससे मुनाफ़ा हो सके.

लेकिन कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है, बशर्ते चाह होनी चाहिए. राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में मोरारका फाउंडेशन ने जैविक खेती के रूप में किसानों को नया जीवन और नई दिशा देने का काम किया है. जैविक खेती के चलते यहां के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और अब देश के दूसरे क्षेत्रों के किसान भी मोरारका फाउंडेशन के संपर्क में आकर अपने यहां जैविक और हाईटेक खेती की शुरुआत कर रहे हैं. मोरारका फाउंडेशन के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं सिक्किम जैसे कई राज्यों में जैविक खेती का आग़ाज़ हो चुका है. यही नहीं, बहुत-से शिक्षित युवा भी अब जैविक खेती में अपना भविष्य तलाश करने लगे हैं. मोरारका फाउंडेशन ने जैविक खेती की शुरुआत राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से की. राजस्थान के लोग देश के दूसरे हिस्सों के मुक़ाबले पानी के अभाव से ज़्यादा दो-चार हैं. किसानों को अगर समय पर पानी नहीं मिलेगा, तो वे भला खेती कैसे करेंगे? मोरारका रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिक राजस्थान के किसानों को यह प्रशिक्षण देने में जुटे हैं कि पानी का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक फसलें कैसे उगाई जाएं. वे हाईटेक तकनीक एवं अल्ट्रा पॉली हाउस द्वारा किसानों को खेती करना सिखा रहे हैं, जिनमें पानी का कम से कम प्रयोग होता है.

मोरारका फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खेती करने का तरीक़ा बताकर उन्हें नया जीवन दिया है. वास्तव में किसानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उनके खेत में अधिक से अधिक अनाज पैदा हो और ज़मीन की उर्वरता पर भी उसका कोई असर न पड़े. रासायनिक खेती का सबसे बड़ा नुक़सान यही था कि कुछ समय तक पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन ज़मीन की उर्वरता तेज़ी से घटने लगती थी, लेकिन अब जैविक खेती के ज़रिये किसानों को इस परेशानी से छुटकारा मिल चुका है. मोरारका फाउंडेशन हाईटेक विधि सिखा कर किसानों को स्वावलंबी एवं आधुनिक बनाने का कार्य कर रहा है. शेखावाटी की नवलगढ़ तहसील के खिरोड़ गांव निवासी किसान अभिषेक शर्मा ने अमेरिका के थंडरबर्ड स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट से एमबीए करने के बाद खेती को बतौर करियर चुना और पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन में सफलता हासिल की. एमबीए करने के दौरान अमेरिका में जैविक खेती के कई हाईटेक फार्म देखने के बाद हाईटेक खेती का विचार उनके मन में आया. पढ़ाई पूरी करने के बाद वह जयपुर स्थित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रोफेसर सत्य नारायण चौधरी एवं लक्ष्मी नारायण कुमावत से मिले और उनसे हाईटेक तरीके से होने वाली खेती, उसके लाभ और खर्चों की जानकारी ली. उन्हें पता चला कि सरकार द्वारा पॉली हाउस लगाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान भी मिलता है. फिर उनकी मुलाकात किसान खेमाराम चौधरी से हुई, जो पहले से पॉली हाउस में सब्जी की खेती कर रहे थे.

अभिषेक ने उनसे पॉली हाउस में होने वाली खेती के बारे में जाना और हाईटेक विधि अच्छी तरह समझने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने खेत में एक पॉली हाउस लगाएंगे. उन्होंने बताया कि पॉली हाउस लगाने में उन्हें दो महीने का वक्त लगा और उन्होंने पहली फसल खीरे की ली. खीरे की फसल तैयार होने में 140 दिन लगते हैं. पौधारोपण के 40 दिनों बाद खीरे की तुड़ाई शुरू हो जाती है. खीरे की पूरी फसल में 60 से 70 बार तुड़ाई होती है. यानी हर दूसरे दिन तुड़ाई होती है. शुरुआती दौर में उत्पादन 500 किलो से 800 किलो तक हो जाता है. आज अभिषेक शर्मा अल्ट्रा मॉर्डन पॉली हाउस खेती करके खुश हैं और वह अपने क्षेत्र के किसानों को भी मोरारका फाउंडेशन से जुड़कर जैविक और अल्ट्रा मॉर्डन पॉली हाउस खेती करने के तरीके सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. अभिषेक शर्मा का मानना है कि अब परंपरागत तरीके से होने वाली खेती से किसानों का जीवनयापन संभव नहीं है. इसलिए देश के हर किसान को समय से पहले हाईटेक विधि अपना कर स्वावलंबी एवं आधुनिक बनना चाहिए.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

पॉली हाउस और उसकी संरचना

ढांचे की बनावट के आधार पर पॉली हाउस कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुंबदाकार, गुफानुमा, रूपांतरित गुफानुमा, झोपड़ीनुमा आदि. ढांचे के लिए आम तौर पर जीआई पाइप या एंगिल आयरन का प्रयोग किया जाता है, जो मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं. अस्थायी तौर पर बांस के ढांचे पर भी पॉली हाउस निर्मित होते हैं, जो सस्ते पड़ते हैं. आवरण के लिए 600-800 गेज की मोटी पैराबैगनी प्रकाश प्रतिरोधी प्लास्टिक शीट का प्रयोग किया जाता है. इनका आकार 30-100 वर्गमीटर रखना सुविधाजनक रहता है. निर्माण लागत और वातावरण पर नियंत्रण की सुविधा के आधार पर पॉली हाउस तीन प्रकार के होते हैं:-

लो कास्ट या साधारण पॉली हाउस: इसमें यंत्रों द्वारा किसी प्रकार का कृत्रिम नियंत्रण वातावरण पर नहीं किया जाता.

मीडियम कास्ट पॉली हाउस: इसमें कृत्रिम नियंत्रण के लिए (ठंडा या गर्म करने के लिए) साधारण उपकरणों का ही प्रयोग करते हैं.

हाई कास्ट पॉली हाउस: इसमें आवश्यकतानुसार तापक्रम, आर्द्रता, प्रकाश, वायु संचार आदि को घटा-बढ़ा सकते हैं और मनचाही फसल किसी भी मौसम में ले सकते हैं.

पॉली हाउस में बेमौसम उत्पादन के लिए वही सब्जियां उपयुक्त होती हैं, जिनकी बाज़ार में मांग अधिक हो और वे अच्छी क़ीमत पर बिक सकें. पर्वतीय क्षेत्रों में जाड़े में मटर, फूलगोभी, पातगोभी, फ्रेंचबीन, शिमला मिर्च, टमाटर, मिर्च, मूली, पालक और गर्मी-बरसात में फूलगोभी, भिंडी, बैंगन, मिर्च एवं लौकी आदि सब्जियां ली जा सकती हैं. फसलों का चयन क्षेत्र की ऊंचाई के आधार पर कुछ भिन्न हो सकता है. वर्षा से होने वाली हानि से बचाव के लिए फूलगोभी, टमाटर एवं मिर्च आदि के पौधे भी पॉली हाउस में डाले जा सकते हैं. इसी तरह गर्मी के मौसम में शीघ्र फसल लेने के लिए लौकीवर्गीय सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं शिमला मिर्च के पौधे भी जनवरी में पॉली हाउस में तैयार किए जा सकते हैं.

बुवाई और रोपण की दूरी: टमाटर-60 गुणा 50 सेमी (डंडों के सहारे पौधों को साधना, शाखाओं की कटाई न करने पर), 50 गुणा 15-20 सेमी (प्रत्येक पौधे के केवल मुख्य तनों को रस्सी के सहारे साधने पर). शिमला मिर्च-15 गुणा 50 सेमी, खीरा-100 गुणा 50 सेमी.

खाद और उर्वरक: प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ग मीटर तीन किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में मिलाएं. इसके अलावा उपरोक्त फसलों में 12-15 ग्राम नत्रजन, छह से नौ ग्राम फास्फोरस और छह से नौ ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में डालें.

पौधों की काट-छांट और सहारा देना: टमाटर के सघन रोपण में केवल मुख्य तने को पतली रस्सी के सहारे बढ़ने दिया जाता है. शाखाओं को समय-समय पर छांटते रहना चाहिए. प्रत्येक बेल वाली सब्जी को डंडे एवं सुतली के सहारे साधना आवश्यक है.

तापक्रम पर नियंत्रण: साधारण पॉली हाउस में ठंड के समय रात में खिड़की-दरवाजे बंद रखे जाते हैं, जबकि गर्मी के मौसम में तापक्रम न बढ़ने देने के लिए दिन-रात खुला रखने की आवश्यकता पड़ती है.

उन्नत किस्में: टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, मिर्च, मटर, फ्रेंचबीन, भिंडी, खीरा, लौकी एवं करेला.■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

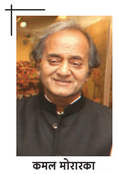

कमल मोरारका

देश में फेडरलिज्म (संघवाद) है. आप इस तरह से कैसे फेडरलिज्म व्यवस्था चला पाएंगे ? इस तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चलती. इसके बजाय तो अच्छा यह होगा कि सभी राज्यों को भंग करके केंद्र सरकार पूरे देश पर राज करे. लेकिन यदि राज्य हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टी सत्ता में हो सकती है. ज़ाहिर है, केंद्र की भाजपा सरकार के लिए यह शर्मनाक है कि ठीक नाक के नीचे दिल्ली विधानसभा में उसके तीन विधायक हैं. केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह कम दु:खद बात नहीं है. मैं समझता हूं कि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी राज्य में किसी एक पार्टी के सांसदों की संख्या उसके विधायकों की संख्या से ज़्यादा है. यह सचमुच एक हास्यास्पद आंकड़ा है.

युवा पीढ़ी अर्थहीन सरकारी प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं करती

डेंगू मच्छर का अचानक इतना आतंक हो जाना चिंता की बात है. किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि डेंगू फिर से इतने आक्रामक रूप से दिल्ली में पैर पसारेगा. मच्छर से संबंधित यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है. डेंगू का मामला इसलिए भी अधिक चिंताजनक है, क्योंकि इसका मच्छर साफ़ पानी में पनपता है. यह मलेरिया के मच्छर की तरह गंदे पानी में नहीं पैदा होता. इससे मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. हालांकि, मुख्य समस्या स्वास्थ्य प्रणाली, अस्पतालों और सामान्य साफ़-सफ़ाई का है, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार को इसका जवाब देना है. भाजपा के दिल्ली चुनाव न जीत सकने के बाद से दिल्ली सरकार के प्रति केंद्र सरकार का रवैया कैसा है, यह सब जानते हैं. न सिर्फ़ स्वास्थ्य सेवाओं, बल्कि पुलिस या क़ानून-व्यवस्था और नैतिक मूल्यों की राह में भी एक गंभीर बाधा है.

देश में फेडरलिज्म (संघवाद) है. आप इस तरह से कैसे फेडरलिज्म व्यवस्था चला पाएंगे? इस तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चलती. इसके बजाय तो अच्छा यह होगा कि सभी राज्यों को भंग करके केंद्र सरकार पूरे देश पर राज करे. लेकिन यदि राज्य हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टी सत्ता में हो सकती है. ज़ाहिर है, केंद्र की भाजपा सरकार के लिए यह शर्मनाक है कि ठीक नाक के नीचे दिल्ली विधानसभा में उसके तीन विधायक हैं. केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह कम दु:खद बात नहीं है. मैं समझता हूं कि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी राज्य में किसी एक पार्टी के सांसदों की संख्या उसके विधायकों की संख्या से ज़्यादा है. यह सचमुच एक हास्यास्पद आंकड़ा है.

लेकिन, मोदी को इन सब बातों से ऊपर उठना चाहिए. आख़िरकार वह देश के प्रधानमंत्री हैं और वह इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं. इसलिए उन्हें अपनी पार्टी के क्षुद्र राजनीतिक खिलाड़ियों को प्रशासन और जनसमस्याओं के साथ खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. मुझे यकीन है कि यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले को अपने हाथ में ले लेता है, तो इसे सुधारा जा सकता है. यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को एक नोटिस भेजा है और जवाब के लिए एक महीने का समय दिया है. यह दु:ख की बात है. एक महीने क्यों? जवाब तो 24 घंटे के भीतर आना चाहिए. एक महीने में कई और लोगों की मृत्यु हो जाएगी. कुल मिलाकर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. अपर्याप्त और मज़ाक़ जैसी स्थिति है. इसमें प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की ज़रूरत है.

मुंबई, जहां मैं रहता हूं, वहां से एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है. वहां जिन लोगों ने भाजपा को वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया था, अब उनका मोहभंग हो रहा है. लोग अपने दैनिक जीवन में रोज़-रोज़ के हस्तक्षेप से परेशान हो गए हैं. भाजपा को वोट देने वाले एक युवा मराठी लड़के ने मुझे एसएमएस भेजा. उस एसएमएस का अर्थ यही था कि मैंने बदलाव की बड़ी उम्मीदों के साथ भाजपा को वोट दिया था, लेकिन अपने जीवन में होने वाले हस्तक्षेप देखकर मैं निराश हूं. मैं अपनी सरकार चुनने, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इस सबका निर्णय करने में सक्षम हूं. दुर्भाग्य से ये लोग जनता की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप कर रहे हैं. अब मैं अपनी जिज्ञासा का हल पा रहा हूं कि कैसे कांग्रेस सभी भ्रष्टाचार के बावजूद 60 वर्षों तक शासन कर सकी. वजह, उसने कभी लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया.

अब एक चरम प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यह प्रतिक्रिया युवाओं की ओर से होगी. मैं 30 वर्ष या उससे कम उम्र के लोगों की बात कर रहा हूं. यह ठीक है कि 282 सीटों वाली अपनी खुद की सरकार के साथ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) स्वाभाविक रूप से अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकार को यह सब समझना चाहिए. आरएसएस में भी युवा हैं. उन्हें एक सर्वे करना चाहिए कि अगली पीढ़ी क्या चाहती है. वहां तक कि आरएसएस समर्थक कट्टर हिंदू भी अपने जीवन में हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं. हां, यदि कोई किसी को गोमांस खाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप आपत्ति कर सकते हैं.

आपने मांस पर प्रतिबंध लगा दिया. यदि जैनियों का उत्सव है और कोई उस सोसायटी में मांस लाता है, तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी मांस खाने पर प्रतिबंध क्यों, जिनका जैनियों से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है? इन चीजों को युवा पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगी. युवा पीढ़ी जियो और जीने दो में यकीन रखती है. वह इस तरह का प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार नहीं है. यदि मैं आपको प्रभावित नहीं कर रहा हूं, तो आप मुझ पर क्यों प्रतिबंध लगाएंगे? यह एक दु:खद स्थिति है. बांम्बे को-ऑपरेटिव सोसायटी ने मांसाहारी भोजन पर आपत्ति के ख़िलाफ़ अदालत का रुख किया है, लेकिन अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए. सोसायटी तो सोसायटी है. अगर वह एक प्रस्ताव पास करती है कि हमारे यहां केवल शाकाहारी लोग ही रहेंगे, तो आप उस पर आपत्ति नहीं कर सकते. लेकिन, आप यही नियम दूसरी बिल्डिंग्स के लिए या गली के हॉकर्स के लिए लागू नहीं कर सकते. आप अपनी सोच अन्य क्षेत्रों के लोगों के खाने, पहनावे या संगीत पर नहीं थोप सकते.

सरकार पांच या कहें कि साढ़े तीन वर्षों के लिए ही है. मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए, जो हिंदुत्व की कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में व्याख्या करे और बताए कि हिंदू संस्कृति क्या है? शाकाहार हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा कभी नहीं था. 97 फ़ीसद हिंदू मांसाहारी हैं. बाकी के लोग भी ऐसे नहीं हैं, जो आदतन शाकाहारी हैं. हो सकता है कि वे मांसाहार का खर्च उठाने में सक्षम न हों. आदतन केवल राजस्थान के शेखावाटी, गुजरात और कुछ तमिल ब्राह्मण ही शाकाहारी हैं. कई राज्यों में तो ब्राह्मण भी हार्डकोर मांसाहारी हैं. इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह का प्रतिबंध कैसे काम करेगा? कई विदेशी यात्रियों, जो भारत आए और जिन्होंने यहां के पांच सितारा होटल में बीफ़ खाया, ने मुझे बताया कि बेशक वह बीफ़ पश्चिम से आयातित था, लेकिन जिस तरह से उसे बनाया गया, उसका स्वाद पश्चिम से बेहतर था. आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चाहते हैं, विदेशियों को बुलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ़ दकियानूसी प्रतिबंध लगाते हैं. ऐसे कैसे काम चलेगा?

अब स्मार्ट सिटी की बात. सबसे पहले तो यह कि किसे नहीं मालूम कि यह स्मार्ट सिटी है क्या? लेकिन, आम तौर पर लोग यह समझ रहे हैं कि यहां पर सब कुछ बेहतर होगा. वाई-फाई होगा, तकनीक होगी. मेरे ख्याल से सरकार ने बहुत सारे शहरों का चयन कर लिया है. शुरुआत दस शहरों से करनी चाहिए थी. वह भी उन राज्यों के शहरों से, जो पहले से अच्छा कर रहे हैं. 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाना मुश्किल काम है. अभी तक ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं आया है, जिससे पता चले कि इसके लिए क्या आप ज़मीन का अधिग्रहण करेंगे या मौजूदा शहरों का ही विकास करेंगे. यह सब किसी को नहीं मालूम है. लेकिन, यदि सरकार इस सबको सफल करना चाहती है, तो उसके लिए विशेषज्ञों की ज़रूरत होगी. चार्ल्स कोरिया दुर्भाग्य से नहीं रहे, अन्यथा वह एक बेहतरीन टाउन प्लानर थे. वह बता सकते थे कि कैसे आगे जाना है. आपको उन्हीं के जैसा कोई और आदमी ढूंढना चाहिए, जो यह बता सके कि स्मार्ट सिटी का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए. स्मार्ट शहरों को 12 या 18 महीने में विकसित नहीं किया जा सकता है. इसमें समय लगेगा, कई साल लग सकते हैं. यदि काम की दिशा स्पष्ट हो, टाउन प्लानिंग स्पष्ट हो, तो यह वास्तविकता भी बन सकती है. मैं समझता हूं कि सरकार ने अपने हाथ में बहुत सारे काम ले लिए हैं, जैसे गंगा की सफ़ाई, स्मार्ट शहर और स्वच्छ भारत वगैरह-वगैरह. मुझे लगता है कि पर्याप्त योजना, सोच या पर्याप्त मानव संसाधन के बगैर उन्होंने बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर दिए हैं. जितनी जल्दी वह इसे ठीक कर लें, परिणाम उतना ही अच्छा होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सबको शिक्षा और समान अवसर मिलना चाहिए

सामान्य श्रेणी के लोगों में काफी दिनों से परेशानी है. उनका तर्क यह है कि हमसे कमज़ोर तबके को आरक्षण की वजह से आईएएस में आ जाते हैं या अन्य सरकारी नौकरियों में चले जाते हैं और हमें उसमें मौक़ा नहीं मिलता. उनका यह भी कहना है कि अब अगर प्रोन्नति में भी आरक्षण आ जाएगा, तो यह देश में बड़े पैमाने पर परेशानी पैदा करेगा. इसलिए आवश्यक है कि जो लोग आरक्षण के दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी आरक्षण मिले और बहुत सारी जगहों पर सवर्ण जातियों ने भी आरक्षण की मांग शुरू कर दी है. आज यह मांग मज़ाक लगती है, लेकिन कल यह मांग गंभीर रूप से सामने आकर खड़ी हो सकती है. इसलिए समाज का बदलना आवश्यक है.

मुझे एक ओबीसी समर्थक ने एक आंकड़ा दिया, कुछ नाम दिए और कुछ दर्द के साथ कहा कि क्या इसी ओबीसी की हिस्सेदारी की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? दरअसल, इस शख़्स की चिंता बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ज़्यादा थी, जहां ओबीसी के सवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है.

इस शख़्स ने मुझसे कहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ब्राह्मण हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनिया हैं यानी व्यवसायी हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह क्षत्रिय हैं और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ब्राह्मण हैं.

इसके बाद यह शख़्स कहता है कि सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ब्राह्मण हैं, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ब्राह्मण हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ब्राह्मण हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ब्राह्मण हैं, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ब्राह्मण हैं और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा ब्राह्मण हैं.

यह शख़्स एक और कहानी कहता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में 53 में से एक भी अधिकारी ओबीसी नहीं है. 83 केंद्रीय सचिवों में से एक भी ओबीसी नहीं है. इतना ही नहीं, 27 केंद्रीय मंत्रियों में से 20 केवल सवर्ण हैं, सुप्रीम कोर्ट के सभी 23 न्यायाधीश सवर्ण हैं, एक भी ओबीसी नहीं है. इसके आगे यह शख़्स कहता है कि 4,500 आईएएस में से 3,450 केवल सवर्ण हैं. इस शख़्स का यह भी कहना है कि 85 वर्षों से ओबीसी की जनगणना नहीं हुई और 27 प्रतिशत ओबीसी की जगह उसका केवल चार प्रतिशत हिस्सा ही भरा गया है. ओबीसी को उसका 27 प्रतिशत हिस्सा मिले, इसके लिए आरक्षण दिया गया, परंतु हालत अब यह है कि ओबीसी के लोगों की नासमझी के कारण देश में आरक्षण समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है.

ओबीसी के लोगों का तर्क है कि पहले ओबीसी का पूरा कोटा भरिए, फिर आरक्षण के ऊपर बहस कीजिए. लेकिन, जो ओबीसी में नहीं आते हैं, उनका यह कहना है कि ओबीसी में जिन जातियों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, वे अपने ही वर्ग की अपने से कमज़ोर जातियों को इसका फ़ायदा लेने नहीं दे रही हैं. इसलिए जिन्हें आरक्षण का फ़ायदा मिल गया, उन्हें अब आरक्षण पर से अपना हक़ छोड़ देना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता साफ़ करना चाहिए. इस पक्ष में देश में एक बहस तो होनी ही चाहिए. और, बहस इस बात को लेकर हो सकती है कि जिस परिवार में दो पीढ़ियों को आरक्षण का फ़ायदा मिला है, उसके बाद अगर उन्हें उस प्रक्रिया में जाना है, तो वे सामान्य श्रेणी में जाएं, आरक्षित श्रेणी में न जाएं. आरक्षित श्रेणी में वे जाएं, जिन्हें अब तक इसका फ़ायदा नहीं मिला है.

लेकिन, सामान्य श्रेणी के लोगों में काफी दिनों से परेशानी है. उनका तर्क यह है कि हमसे कमज़ोर लड़के आरक्षण की वजह से आईएएस में आ जाते हैं या अन्य सरकारी नौकरियों में चले जाते हैं और हमें उसमें मौक़ा नहीं मिलता. उनका यह भी कहना है कि अब अगर प्रोन्नति में भी आरक्षण आ जाएगा, तो यह देश में बड़े पैमाने पर परेशानी पैदा करेगा. इसलिए आवश्यक है कि जो लोग आरक्षण के दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी आरक्षण मिले और बहुत सारी जगहों पर सवर्ण जातियों ने भी आरक्षण की मांग शुरू कर दी है. आज यह मांग मज़ाक लगती है, लेकिन कल यह मांग गंभीर रूप से सामने आकर खड़ी हो सकती है. इसलिए समाज का बदलना आवश्यक है. पर क्या यह संभव नहीं कि सरकार बजाय निजी स्कूलों को बढ़ाने या बजाय पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर बड़े-बड़े स्कूलों को बढ़ावा देने के हमारे गांवों में शिक्षा का एक मजबूत जाल फैलाए और उसके लिए खुद पैसा खर्च करे? देश पैसा देने में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकता है. सरकार संपूर्ण शिक्षा का जाल सुदृढ़ करे और सबको इंटरमीडिएट तक शिक्षा मुहैया कराए.

यह सत्य है कि हमारे देश में जिस तरह का समाज है, जिस तरीके की असुविधाएं हैं, जिस तरह के अभाव हैं, जिस तरीके की संभावनाएं हैं, उनमें आरक्षण अति आवश्यक है, पर क्या यह संभव नहीं कि सरकार बजाय निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के हमारे गांवों में शिक्षा का एक मजबूत जाल फैलाए और उसके लिए खुद पैसा खर्च करे? देश पैसा देने में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकता है. सरकार संपूर्ण शिक्षा का जाल सुदृढ़ करे और सबको इंटरमीडिएट तक शिक्षा मुहैया कराए.

स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री हैं और वह कहती हैं कि नवंबर में नई शिक्षा प्रणाली का मसौदा देश के सामने रखा जाएगा. हमें शंका है कि उस शिक्षा प्रणाली में बुनियादी शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा को सुधारने की जगह धार्मिक या वैचारिक आधार पर शिक्षा को मोड़ देने की कोशिश होगी. नई शिक्षा व्यवस्था का मतलब यह होना चाहिए कि जो शिक्षा नहीं पा रहा है, उसे शिक्षा कैसे मिले और देश में हर एक को समान अवसर मिले. अगर यह मतलब नई शिक्षा व्यवस्था का नहीं निकलता है, तो नई शिक्षा नीति बेकार है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कमाल का फ़ैसला दिया, जिसके तहत उसने कहा कि अधिकारियों, नेताओं और न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें. नेताओं से मतलब विधायक एवं सांसद या जितने भी चुने हुए या नॉमिनेटेड पद हैं, उन पर काबिज लोगों के बच्चे सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ें. अगर इन घरों पर आसीन लोग अपने बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, तो उन्हें निजी स्कूलों में खर्च की जाने वाली धनराशि सरकारी खजाने में जमा करनी चाहिए. इसे लेकर बहुत चिल्ल-पों हुई और इसे मौलिक अधिकार के विपरीत माना गया. यह कहा जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मजबूती के साथ केस लड़ा जाए और इसे ख़ारिज कराया जाए. इस देश में न्याय व्यवस्था है, होशियार वकील हैं, रास्ता निकाल सकते हैं और इसे ख़ारिज भी करा सकते हैं. लेकिन, जिस बात को देश की सरकार न सोचे, उसे देश का एक उच्च न्यायालय सोच रहा है, यह एक शुभ लक्षण है. मेरा मानना है कि माध्यमिक शिक्षा तक कोई भी वैचारिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए. इस देश का इतिहास, भूगोल, आज़ादी की लड़ाई आदि सब चीजों के ऊपर विचार करके सर्वसुलभ शिक्षा का ताना-बाना बुना जाना चाहिए और शिक्षा में सबको समान सुविधाएं देकर एक खुली प्रतियोगिता के लिए छोड़ देना चाहिए. अगले दस सालों में सरकारें इसे पूरा करें और दस साल के बाद देश में सारे लोग किसी भी प्रतियोगिता के लिए समान रूप से बैठें. अगर इस योजना पर काम नहीं होता, तो इस देश में न आरक्षण का फ़ायदा सबको मिलेगा, न शिक्षा का फ़ायदा सबको मिलेगा. और, हमारा समाज उसी तरह निकृष्ट से निकृष्टतम होने के रास्ते पर चल पड़ेगा, जैसे हम आज चल रहे हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

जब एक स्त्री डाकू बदला लेने पहुंचती है-6

फूलन देवी का संपादक के नाम पत्र

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

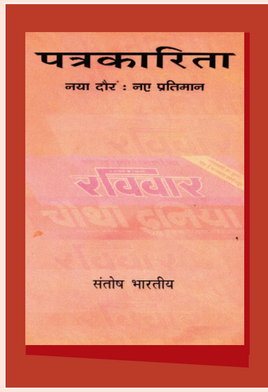

विक्रम की मौत के बाद उसकी हत्या का बदला लेने की उत्तेजना के साथ-साथ फूलन के लिए क्षेत्र में बहैसियत एक डाकू सरदार अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी कोई भयानक कार्रवाई करना ज़रूरी हो गया था. विक्रम के मारे जाने से उसका गिरोह तो छिन्न-भिन्न हुआ ही था, इलाके भर में उसे और उसके साथियों को शरण देने वालों का मनोबल भी टूट गया था. फूलन को एक तरफ़ तो अपने बिखरे गिरोह को समेटना था और दूसरी तरफ़ अपने संरक्षकों में अपनी खोई साख जमानी थी. किसी भी डाकू सरदार को अधिक समय तक जीवन जीने के लिए एक ऐसा तंत्र तैयार करना पड़ता है, जो उसे क्षेत्र में सुरक्षित रखे और जिसकी मदद से डकैतियां डालने का काम जारी रह सके. इस सबकी व्यवस्था करने में हर डाकू खासा राजनीतिक हो जाता है. इसलिए यदि बेहमई में ठाकुरों की सामूहिक हत्याएं करने के पीछे फूलन के दिमाग में ऐसी ही कोई योजना रही हो, तो कोई आश्चर्य नहीं. यह एक तथ्य है कि बेहमई कांड से पुन: बहैसियत डाकू सरदार फूलन की साख फिर जग गई है तथा साथ ही क्षेत्र की विशेष जातीय पृष्ठभूमि में उससे सहानुभूति रखने वालों की तादाद भी बढ़ी है.

कानपुर से प्रकाशित एक दैनिक ने 27 फरवरी को धूम-धड़ाके से फूलन देवी का संपादक के नाम एक पत्र छापा, जिसकी सत्यता के बारे में स्वयं उक्त पत्र के संपादक महोदय ही संतुष्ट नहीं हैं. फूलन की राजनीतिक सजगता ज़ाहिर करने वाले उस पत्र का मज़मून है, मैं यह पत्र बाबा मुस्तकीम व राम औतार द्वारा लिखवा रही हूं, क्योंकि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं, किंतु कही ज़्यादा हूं. मेरा व बाबा मुस्तकीम का आईजी व डीआईजी से कहना है कि अगर आतंक समाप्त कराना है, तो आप इसका समझौता अखबार द्वारा करा दें. मेरी दुश्मनी लालाराम और श्रीराम को छोड़कर किसी से भी नहीं है. मुझे पता चला है कि एक मीटिंग में ठाकुरों ने कहा कि थाना सिकंदरा की पुलिस उनकी जाति की हो, तो वे मदद करेंगे. अगर ये लोग जातिवाद चलाएंगे, तो मैं भी चलाऊंगी. सभी लोगों से मेरा कहना है कि जातिवाद किसने चलाया है? यह सभी भाइयों को मालूम है कि ग्राम पाल, थाना चरखी, ज़िला जालौन में श्रीराम ने क्या किया था? जलती हुई आग में मल्लाहों को डाला था और जब वे बेचारे मल्लाह आग से बाहर निकलने की कोशिश करते थे, तो बंदूक की नालों से ठेलकर अंदर कर दिया जाता था. इस तरह उन बेचारों की ज़िंदगी गई. हे ईश्वर! मुझसे देखा न गया! जब मुझे पता चला, तो सुनते ही आतंक हो गया, लेकिन फिर मैंने भी टाल दिया. बच्चों सहित लोग घर खाली कर गए. जरा-जरा से बच्चे तड़पते हुए भाग गए. किसी पुलिस ने कोई ख्वाहिश नहीं की. दोबारा भी उस गांव के लोगों को धमकाया-पीटा गया. किसी गवर्नमेंट ने एक पैसा नहीं दिया. क्या वे इंसान नहीं थे, जिन्हें जला-जलाकर मारा गया? ठाकुरों का कहना है कि मल्लाहों को बीन-बीनकर मारेंगे. अगर एक भी मल्लाह मार दिया, तो सौ ठाकुर न मारे, तो मेरा नाम फूलन देवी न कहना, भंगिन समझना. ■

29 मार्च, 1982

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

राजतिलक, जिसे रोक दिया गया

राहुल यदि बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो उन्हें लालू से अलग ही रखा जाएगा. बिहार चुनाव में उनका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है. पिछले चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया था, जिसके नतीजे में वह बुरी तरह से नाकाम हो गए थे. शायद इसलिए सोनिया गांधी का नर्म रवैया कांग्रेस के लिए बेहतर है. बिहार चुनाव भाजपा की परीक्षा से बढ़कर कांग्रेस की परीक्षा है. पार्टी मई 2014 के बाद से दिल्ली (जहां उसका खाता भी नहीं खुला), महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर चुनाव हार चुकी है.

क्वीन एलिज़ाबेथ ने अभी हाल में क्वीन विक्टोरिया का सबसे लंबे समय तक रानी बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है. ब्रिटेन में राजशाही का विरोध करने वाले एक शख़्स ने लिखा कि वह इस उत्सव में इसलिए शामिल हुआ, क्योंकि एलिज़ाबेथ की वजह से प्रिंस चार्ल्स अभी तक राजा नहीं बन पाए हैं. इधर भारत में सोनिया गांधी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष बन गई हैं. यह उनकी अध्यक्षता का रिकॉर्ड 18वां साल है. बेशक, वह इस पद पर बने रहने की योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने ही 1998 में पार्टी को पूरी तरह से तबाह होने से बचाया था. एक बार फिर कांग्रेस का अस्तित्व सवालों के घेरे में आ गया है. अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अपने वर्तमान संकट से उबर पाएगी? लिहाज़ा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एहतियातन पार्टी के उत्तराधिकारी की ताजपोशी का मामला फ़िलहाल टाल दिया है. राहुल गांधी को ज़हर का प्याला पीने के लिए फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा.

विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है. यह कहना ग़लत नहीं होगा कि पार्टी अपनी ताक़त से अधिक शोर मचा रही है. लगातार संसद की कार्रवाई बाधित करने की उसकी गुरिल्ला नीति ने फ़िलहाल भाजपा के विधायी कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे मोर्चों पर कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है. मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस के साथ गठबंधन में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है. उनके हिसाब से कांग्रेस एक हारी हुई पार्टी है. लिहाज़ा वह बिहार के सेक्युलर गठबंधन से बहार हो गए. उन्हें याद आया होगा कि जनता आंदोलन, जिसे जय प्रकाश नारायण ने शुरू किया था, पूरी तरह से कांग्रेस के विरोध में था. यही वजह थी कि जदयू को एनडीए का हिस्सा बनने में कोई खास परेशानी नहीं हुई. हालांकि, नरेंद्र मोदी के सवाल पर नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से अलग हो गए थे. जहां तक जदयू और राजद का साथ है, तो वह भी बेमेल की शादी ही लगता है. मुलायम का गठबंधन से अलग होना नीतीश के सेक्युलर चरित्र को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा करता है.

दरअसल, कांग्रेस को यह एहसास हो गया कि अगर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो लालू यादव को वह दिन ज़रूर याद आ जाएगा, जब उन्होंने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में उस अध्यादेश को फाड़ दिया था, जो लालू यादव की लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए तैयार किया गया था. राहुल यदि बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो उन्हें लालू से अलग ही रखा जाएगा. बिहार चुनाव में उनका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है. पिछले चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया था, जिसके नतीजे में वह बुरी तरह से नाकाम हो गए थे. शायद इसलिए सोनिया गांधी का नर्म रवैया कांग्रेस के लिए बेहतर है. बिहार चुनाव भाजपा की परीक्षा से बढ़कर कांग्रेस की परीक्षा है. पार्टी मई 2014 के बाद से दिल्ली (जहां उसका खाता भी नहीं खुला), महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर चुनाव हार चुकी है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो राहुल गांधी के भविष्य की रणनीति का हिस्सा हैं, के स्थानीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस के व्यापमं और मोदीगेट के ऊपर संसद में हंगामे के बावजूद भाजपा जीत गई. अगर बिहार चुनाव में उसे धक्का लगता है या कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाती या कम सीटें जीत पाती है, तो उसके भविष्य पर सवाल उठना लाज़िमी हो जाएगा. कांग्रेस का वजूद उससे अलग हुए घटकों यानी एनसीपी, टीएमसी, आरएलडी इत्यादि की शक्ल में ज़रूर बचा रहेगा. अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि बिहार में कौन जीतेगा. ज़्यादा से ज़्यादा यह कहा जा सकता है कि मुक़ाबला कांटे का है. उत्तर प्रदेश और बिहार जातिवादी राजनीति के दो आख़िरी किले बचे हुए हैं. यहां हर जाति के वोट बैंक का हिसाब लगाया जाएगा और उस पर डोरे डालने की कोशिश की जाएगी. कांग्रेस ब्राह्मण वोट लेने की कोशिश करेगी, तो भाजपा भी ब्राह्मणों को अपने पाले में लेने की कोशिश करेगी. दूसरी तरफ दलित एवं महादलित की लड़ाई कांग्रेस, पासवान और मांझी के बीच होगी. यादव वोट सपा के अलग होने से पहले पूरी तरह से राजद के साथ था. लेकिन यह सच्चाई है कि बिहार में जो भी जीते, जातिवाद बना रहेगा. यह सबसे बड़ी त्रासदी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जीवन का ज्ञान

> भारत में अगस्त पंजाब, बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडू तथा अण्डमान द्वीप समूह में पाया जाता है. इसके कोमल पत्र, पुष्प और फलियों का शाक बनाकर खाया जाता है. अगस्त पुष्प–पित्तशामक, कफशामक, चातुर्थिक ज्वरनाशक, शीतल, रूक्ष, तिक्त, वातकारक तथा प्रतिश्याय में हितकर है. यह शीतवीर्य, मधुर, कड़वा, कसैला, विपाक में चरपरा तथा रतौंधी, पीनस रोग और वातरक्त नाशक है.

बहुपयोगी है अगस्त

अगस्त के वृक्ष सर्वत्र मिलते हैं. जहां जल की प्रचुरता तथा वायुमण्डल उष्ण प्रधानशील है, वहां यह खूब फलता–फूलता है. भारत में यह पंजाब, बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडू तथा अण्डमान द्वीप समूह में पाया जाता है. इसके कोमल पत्र, पुष्प और फलियों का शाक बनाकर खाया जाता है.

वाह्य स्वरूप

अगस्त के वृक्ष अल्पायु तथा शीघ्र वर्धनशील लगभग 3–5 मीटर तक ऊंचे होते हैं. इसमें घनी, छोटी, पतली, पीत–हरित वर्ण की बहुत सी शाखाएं होती हैं.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

1. अगस्त पुष्प–पित्तशामक, कफशामक, चातुर्थिक ज्वरनाशक, शीतल, रूक्ष, तिक्त, वातकारक तथा प्रतिश्याय में हितकर है. यह शीतवीर्य, मधुर, कड़वा, कसैला, विपाक में चरपरा तथा रतौंधी, पीनस रोग और वातरक्त नाशक है.
2. अगस्त पत्र– कटु, तिक्त, किंचित उष्ण, विपाक में मधुर, गुरु तथा कृमि, कंडू, रक्त पित्त, विष तथा प्रतिश्याय को दूर करने वाला है.
3. अगस्त की फली विपाक में मधुर, तिक्त, लघु, सर, रुचिकारक बुद्धिदायक, स्मरणशक्तिवर्धक तथा त्रिदोषज शूल, पांडु, विष, शोथ और गुल्म–नाशक है.
4. इसकी पक्व फली रूक्ष और पित्तकारक होती है.
5. इसकी छाल संकोचक,कटु, पौष्टिक, पाचक और शक्ति–वर्धक है.
6. इसका पत्र सत्त आक्षेपरोधी तथा चिन्ताहर क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.
7. इसके त्वक के मेथनॉल सत्त एल्बीनो चूहों में सार्थक व्रणरोपण क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.
8. इसका ऐथेनॉल सत्त स्विस ऐल्बिनो चूहों के ऐरलिच जलोदर कर्कटार्बुद के प्रति कर्कटार्बुदरोधी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग :

1. सूर्यवर्त तथा शिर:शूल–अगस्त पत्र–स्वरस की 4–6 बूंदें प्रात: खाली पेट नाक में डालने से सूर्यावर्त्त में लाभ होता है.

2.आधाशीशी–जिस तरफ के मस्तिष्क में वेदना हो, उसके दूसरी ओर के नथुने में अगस्त के पत्तों या फूलों के रस की 2–3 बूंदे टपकाने से तुरंत लाभ होता है. इससे नासिका की पीड़ा भी शांत हो जाती है.

नेत्र रोग :

1. नक्तान्ध्य (रतौंधी)– अगस्त्य पत्र के कल्क एवं काढ़े से पकाए हुए घृत को 2–5 ग्राम की मात्रा में लंबे समय तक सेवन करने से नक्तान्धता (रतौंधी) में लाभ होता है.

2. मक्खन के साथ 2–3 अगस्त पुष्प का सेवन करने से तथा पुष्प स्वरस की बूंदों से नेत्रों में आश्च्योतन करने से नक्तान्ध्य में लाभप्रद है.

3. रतौंधी–अगस्त पुष्प स्वरस को 2–2 बूंद नेत्रों में डालने से रतौंधी में लाभ होता है.

4. अगस्त के पुष्पों की सब्जी या शाक बनाकर कुछ समय तक सुबह–शाम खाने से रतौंधी में लाभ होता है.

5. अगस्त के 250 ग्राम पत्रों को पीसकर एक किग्रा गोघृत में पकाकर, 5–10 ग्राम घृत को सुबह–शाम सेवन करने से रतौंधी में लाभ होता है.

6. इसके पुष्प मधु को आंखों में डालने से नेत्र विकारों का शमन होता है. (पुष्प को तोड़ने से भीतर से 2–3 बूंद मधु निकलता है.)

7. अगस्त के पत्तों को घी में भूनकर खाने से और घी का सेवन करने से दृष्टिमांद्य या मोतियाबिन्द में लाभ होता है.

8. तिमिर–घी में भुने हुये अगस्त के पत्रों का सेवन तथा अगस्त पुष्प मधु से आश्च्योतन करना तिमिर (काला मोतिया) रोग में लाभप्रद है.

नासा रोग :

1. प्रतिश्याय–जुकाम के वेग से सिर बहुत भारी हो तथा दुखता हो तो अगस्त पत्र रस की दो–चार बूंद नाक में टपकाने से तथा 10–20 मिली मूल स्वरस में शहद मिलाकर दिन में 3–4 बार चाटने से जुकाम में लाभ होता है.

कण्ठ रोग :

1. स्वरभंग–अगस्त की पत्तियों के क्वाथ का गंडूष धारण करने से शुष्क कास, जीभ का फटना, गले में खराश तथा रक्तवमन (कफ के साथ रुधिर निकलना) में लाभ होता है.

उदर रोग :

1. उदरशूल–अगस्त की छाल (5–10 ग्राम) का काढ़ा बनाकर 30–40 मिली क्वाथ में थोड़ा सेंधानमक और भुनी हुई 2 नग लौंग मिलाकर सुबह–शाम पीने से जीर्ण उदरविकारों में लाभ होता है तथा उदरशूल का शमन होता है.

2. अगस्त छाल के क्वाथ (20–40 मिली) अथवा स्वरस (5–10 मिली) में सैन्धव लवण और हिंगु मिलाकर सेवन करने से उदरशूल (पेटदर्द) का शमन होता है.

3. अतिसार/प्रवाहिका–20–40 मिली अगस्त छाल क्वाथ को पीने से अतिसार तथा प्रवाहिका में लाभ होता है.

4. विबन्ध–प्रतिदिन 20–40 मिली त्वक क्वाथ का सेवन करने से कब्ज में लाभ होता है.

प्रजनन संस्थान रोग :

1. श्वेत–प्रदर–अगस्त त्वक् स्वरस के पिचु को योनि में धारण करने से श्वेत–प्रदर एवं योनिकण्डु (योनि की खुजली) में लाभ होता है.

2. 10 मिली अगस्त पत्र–स्वरस में थोड़ा शहद मिलाकर सेवन करने से प्रदर रोग में लाभ होता है.

3. अगस्त के फूलों की पकौड़ी बनाकर सेवन करने से प्रदर तथा प्रदरजन्य दौर्बल्य में लाभ होता है.

4. अगस्त के पुष्पों को सुखाकर पाउडर कर 2–3 ग्राम की मात्रा में दूध या शहद के साथ प्रतिदिन प्राय: एवं सायं सेवन करने से प्रदर व प्रमेह में लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग:

1. गठिया–धतूरे की जड़ और अगस्त की जड़ दोनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और पुल्टिस जैसा बनाकर वेदनायुक्त भाग पर बांधने से वेदना तथा शोथ का शमन होती है.

त्वचा रोग:

1. खाज–अगस्त पुष्प के 100 ग्राम चूर्ण को एक लीटर दूध में डालकर दही जमा दें. दूसरे दिन मक्खन निकाल कर मालिश करें. इस मक्खन की मालिश खाज पर करने से भी लाभ होता है.

2.फोड़ा–अगस्त के पत्रों को गर्म कर (यदि पुटपाक–विधि से गर्म करें तो अच्छा है) फोड़े के स्थान पर बांधने से फोड़ा फूट कर बह जाता है.

मानस रोग:

1.मिर्गी–अगस्त पत्र चूर्ण और काली मिर्च चूर्ण को समान भाग में लेकर गोमूत्र के साथ बारीक पीसकर मिर्गी के रोगी को सुंघाने से लाभ होता है.

2.यदि बालक छोटा हो तो अगस्त के दो पत्तों का रस और उसमें आधी मात्रा में काली मिर्च मिलाकर उसमें रूई का फाहा तरकर उसे नासारन्ध्र के पास रखने से ही मिर्गी शांत हो जाती है.

3. चित्तविभ्रम–अगस्त पत्र रस में पीपर (पिप्पली)और गुड़ समभाग मिलाकर, छानकर 1–2 बूंद नाक में डालने से लाभ होता है.

4.मूर्च्छा–केवल पत्र–स्वरस की चार–चार बूंदें दोनों नाक में टपका देने से ही बेहोशी दूर हो जाती है.

5.बुद्धिवर्धनार्थ–1–2 ग्राम अगस्त बीज चूर्ण को गाय के 250 मिली धारोष्ण दूध के साथ प्राय: एवं सायं कुछ दिन तक खाने से स्मरण–शक्ति तीव्र हो जाती है.

सर्वशरीर रोग:

1.ज्वर– अगस्त के फूलों या पत्तों का रस सुंघाने से चातुर्थिक ज्वर और जुकाम में लाभ होता है.

2. दो या तीन चम्मच अगस्त पत्र–स्वरस में आधा चम्मच शहद मिलाकर प्राय: एवं सायं सेवन करने से चातुर्थिक ज्वर का शमन होता है. इसका प्रयोग लगातार 15 दिन तक करना चाहिए.

3. फेफड़ों के शोथ एवं कफज कास–श्वास के साथ यदि ज्वर हो तो अगस्त मूल छाल अथवा पत्र या पंचाग के 10 या 20 मिली स्वरस में बराबर में शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से अत्यन्त लाभ होता है.

4. 2 ग्राम अगस्त मूल छाल चूर्ण को 2–3 मिली पान स्वरस के साथ दिन में 3 बार सेवन कराने से भी कफज कास, श्वास तथा ज्वर में लाभ होता है.

5. अगस्त छाल से बनाए हिम या फाण्ट को 20 मिली मात्रा में पिलाने से शीतला तथा बुखार के कारण उत्पन्न फुन्सियों में लाभ होता है.

6. रक्तस्राव–अगस्त के फूलों का शाक खाने से रक्तस्राव का स्तम्भ होता है.

प्रयोज्यांग : मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, एवं फल
मात्रा: पत्र–स्वरस 10–20 मिली. क्वाथ 20–40 मिली. चूर्ण 2–4 ग्राम. बीज चूर्ण 1–3 ग्राम

आचार्य बालकृष्ण

सूचना का अधिकार – जानने का अधिकार जीने का अधिकार – चौथी दुनिया की पहल

अस्पतालों में दवाइयों के बारे में ऐसे पाएं जानकारी

अगर आपके मरीज का ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है, अगर आप दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं, अगर आपके आसपास किसी को गंभीर बीमारी है और उसे समय पर दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, अगर आप समय रहते दवाइयों की खुद के लिए या दूसरों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं और दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं तो आप आरटीआई आवेदन के माध्यम से दवाइयों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और समय रहते खुद की या अपने मरीज की काफी हद तक मदद कर सकते हैं. इस अंक में हम अस्पताल में दवाइयों की कमी से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के जरिये संपर्क कर सकते हैं.

आवेदन का प्रारूप

(अस्पताल में दवाइयों की कमी)
सेवा में, दिनांक
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)
विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.
महोदय,

.... स्थित .... अस्पताल के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. दिनांक .... से .... के बीच अस्पताल के लिए कुल कितनी रकम की दवाइयां खरीदी गईं. दवाइयों के खरीदने व उन्हें अस्पताल/ चिकित्सा केन्द्र के स्टॉक में रखे जाने से संबंधित रजिस्टर की पिछले.............महीने की प्रति उपलब्ध कराएं.

2. उपरोक्त समय के बीच कुल कितनी रकम की दवाइयां यहां आने वाले मरीज़ों को नि:शुल्क बांटी गई. नि:शुल्क दवाइयां प्राप्त करने वाले मरीज़ों की संख्या बताएं तथा उनके नाम, पते आदि जिस रजिस्टर में लिखे जातें हैं, उस रजिस्टर की पिछले...........महीने की प्रति उपलब्ध कराएं?

3. अस्पताल के लिए दवाइयां खरीदने तथा वितरण के लिए नियुक्त अधिकारियों के नाम, पद तथा संपर्क का पता उपलब्ध कराएं?

4. इस दौरान जिन एजेंसियों से दवाइयां खरीदी गई, उन एजेंसियों का पूरा विवरण उनके नाम तथा पते के साथ उपलब्ध कराएं?

5. इस अस्पताल में मुख्य रूप से किन–किन रोगों से संबंधित दवाइयां नि:शुल्क वितरित की जाती हैं?

6. अस्पताल द्वारा दवाइयों का नि:शुल्क वितरण किस आधार पर किया जाता है?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपया अलग से जमा कर रहा /रही हूं.

या

मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..............है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो) ■

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई–मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है–

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल: rti@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

भारत–इजराइल ड्रोन सौदा का फायदा यह होगा कि ज्यादा रिस्क वाले एरिया में पायलट भेजने की बजाय आर्म्ड ड्रोन का प्रयोग किया जा सकेगा. इस सिस्टम का इस्तेमाल चोरी–छिपे अचानक हमला करने में भी हो सकता है. सेल्फ–डिस्ट्रक्टिंग सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से दुश्मन के राडार की पोजीशन पता करने में किया जाता है. भारतीय वायु सेना के पास इजराइल से लिया गया हर्पी यूएवी का बेड़ा है, जो स्व–विध्वंसक प्रणाली है. यह मुख्य रूप से दुश्मन के रडार की स्थितियों को बताता है. अभी तक भारत निगरानी और खुफ़िया सूचनाएं जुटाने के लिए बिना हथियार वाले ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है.

भारत–इजराइल ड्रोन सौदा

आतंक के ख़िलाफ़ कारगर हथियार

भारत सबसे ज्यादा सीमा पार की आतंकी गतिविधियों से परेशान है. कभी पाकिस्तान, तो कभी बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा पार की अशांति भारत को चैन से सोने नहीं देती. लेकिन भारत ने अब सीमा पार के ऐसे किसी भी नापाक मंसूबों का सटीक जवाब देने के लिए कमर कस ली है, उसी का परिणाम है इजराइल से सशस्त्र ड्रोन सौदा. यह ड्रोन न सिर्फ दुश्मन को तबाह कर सकता है, बल्कि इससे जान-माल की क्षति भी न के बराबर होगी. अब तक जवाबी कार्रवाइयों से पहले सबसे बड़ी चिंता बहुत बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की होती थी, लेकिन इजराइली ड्रोन के अब तक के प्रदर्शन के रिकॉर्ड बताते हैं कि यह सीमा पार से परोसी जाने वाली आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाकर भारत के लिए वरदान साबित होने वाला है.

राजीव रंजन

भारत ने इजराइल से 40 करोड़ डॉलर (करीब 2600 करोड़ रुपये) में 10 हेरॉन टीपी ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में ड्रोन का नया बेड़ा काम आ सकता है, क्योंकि आए दिन सीमा पार से पाकिस्तान सहित अन्य देशों द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारतीय जान–माल की काफी क्षति हो रही है. मणिपुर में जून में हुए आतंकी हमले में सेना के 18 जवानों के शहीद होने के बाद सीमा पार के आतंकवादी शिविरों को टारगेट करने की जरूरत महसूस की गई थी. इजराइल से सशस्त्र ड्रोन सौदा इसी का परिणाम है. यह ड्रोन भारतीय वायुसेना के लिए हासिल किए जा रहे हैं. इस सौदे को अमलीजामा पहनाने के लिए इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अधिकारियों ने हाल ही में भारत का दौरा किया. इन अधिकारियों ने साझा उपक्रम में ड्रोन के उत्पादन की संभावना पर भी विचार किया. इन ड्रोन को भारतीय वायुसेना ऑपरेट करेगी. ड्रोन की एक साल के अंदर सेना में तैनाती हो सकती है. यह ड्रोन 1000 किलो से ज्यादा का पेलोड ले जा सकते हैं. इनमें हवा से जमीन पर मार कर सकने वाली मिसाइल लगी होगी. हथियारों से लैस ड्रोन खरीदने का प्लान आर्म्ड फोर्सेज ने गोपनीय प्रोजेक्ट के तहत 2011 में बनाया था, लेकिन राजनीतिक बंदिशों के कारण उस समय इस सौदे पर विचार नहीं किया जा सका. हालांकि हाल के दिनों में सीमा पार से जिस तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उस पर काबू पाना देश की जरूरत बन गई. यह डील बहुत संवेदनशील थी, यही कारण है कि इस डील को सात परदों में छिपाकर रखे जाने की बात कही जा रही है. भारत के पास बिना हथियारों वाले हेरॉन पहले से ही हैं, जो निगरानी और गोपनीय सूचनाएं जमा करते हैं. लेकिन इस नये ड्रोन की डील से भारत की सामरिक शक्ति काफी बढ़ जाएगी. इससे वह दुश्मन के इलाके में बड़ी आसानी से आतंकी शिविरों, यहां तक की किसी शख्स को भी कम से कम रिस्क में टारगेट बना सकेगा.

भारत और इजराइली ड्रोन

भारत ने पहली बार 1998 में इजराइल से ड्रोन खरीदा था. एसआईपीआरआई के मुताबिक, भारत ने ड्रोन की अधिकतर खरीदारी इजरायल से की है. देश में आयातित 176 ड्रोनों में से 108 खोजी ड्रोन हैं और 68 हेरॉन ड्रोन हैं. ड्रोन के वैश्विक निर्यात में इजरायल का योगदान सर्वाधिक 60.7 फीसदी और अमेरिका का 23.9 फीसदी है. कनाडा का 6.4 फीसदी है. इजरायल ने 1980 से अब तक 783 ड्रोनों का निर्यात किया है. 1985 से 2014 तक यूएवी के वैश्विक आयात में भारत 22.5 फीसदी हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है. इसके बाद क्रमश: ब्रिटेन और फ्रांस रहे हैं. ड्रोन या यूएवी आकाश में उड़ने वाला एक पायलटरहित वाहन है. इसका उपयोग टोही गतिविधियों में होता है. ■

हेरॉन टीपी ड्रोन

- इजराइल का हेरॉन ड्रोन टोही, युद्धक और समर्थन भूमिकाओं में सक्षम प्रीडेटर–मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) के जैसा ही है.
- इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मारक स्टाइल कम से कम क्षति पहुंचाती है. यहां तक कि इससे किसी एक व्यक्ति को भी लक्ष्य किया जा सकता है.
- ज्यादा रिस्क वाले क्षेत्रों में आर्म्ड ड्रोन का बेहतरीन प्रयोग किया जा सकता है.
- इस सिस्टम का इस्तेमाल चोरी–छिपे अचानक हमला करने में हो सकता है.
- इसका उपयोग मुख्य रूप से दुश्मन के राडार की पोजीशन पता करने में किया जाता है.
- ये हवा से जमीन पर वार करने वाले मिसाइलों से लैस हैं.
- ये दुश्मन देश के इलाके में छुपे लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें भेद सकते हैं.
- हेरॉन ड्रोन्स 1000 किलोग्राम से अधिक वजन के पेलोड ले जा सकते हैं.
- इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित हेरॉन ड्रोन मध्यम उंचाई स्तरों पर लगातार 52 घंटों की उड़ान भर सकता है.
- फिलहाल भारत असैन्य हेरॉन और खोजी यूएवी के बेड़े का संचालन निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए करता है. ■

एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख वीपी नाइक भी स्वीकार करते हैं कि इस डील से भारत की ताकत में इजाफा होगा. वीपी नाइक का कहना है कि ज्यादा रिस्क वाले एरिया में पायलट भेजने की बजाय आर्म्ड ड्रोन का प्रयोग करना सबसे अच्छा होगा. इस सिस्टम का इस्तेमाल चोरी–छिपे अचानक हमला करने में हो सकता है. दूसरी बात कि इस सेल्फ–डिस्ट्रक्टिंग सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से दुश्मन के राडार की पोजीशन पता करने में किया जाता है. भारतीय वायु सेना के पास इजराइल से लिया गया हर्पी यूएवी का बेड़ा है, जो स्व–विध्वंसक प्रणाली है. यह मुख्य रूप से दुश्मन के रडार की स्थितियों को बताता है. अभी तक भारत निगरानी और खुफ़िया सूचनाएं जुटाने के लिए बिना हथियार वाले ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सशस्त्र ड्रोन आने से सीमा पार के परिदृश्य में बढ़त मिलेगी. इस ड्रोन को हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल के साथ फिट किया जा सकता है. ये ड्रोन ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, जहां से जवानों की जान को खतरा होता है. अगर भारत इस ड्रोन ताकत से लैस हो जाता है तो खासतौर पर चीन और पाकिस्तान की सीमा पार गतिविधियों पर बिना किसी रिस्क के नजर रखी जा सकती है. दूसरी तरफ आए दिन सुनने को मिलता है कि किसी आतंकी संगठन का सरगना भारत–पाकिस्तान बॉर्डर पर देखा गया, ऐसे सरगनाओं को भी चुपके से सटीक निशाना लगाकर ड्रोन से खत्म किया जा सकता है. इतना ही नहीं, भारत खुद के मानवरहित ड्रोन बनाने के कार्यक्रम पर भी निवेश कर रहा है.

दुनिया भर में इजराइली ड्रोन का कोई जवाब नहीं है. 2008–09 के गाजा ऑपरेशन के समय हेरॉन द्वारा किए गए प्रदर्शन का रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है. हेरॉन की इसी सफलता को देखते हुए सिंगापुर, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, अजरबैजान, इक्वाडोर, मोरक्को, कोरिया, ब्राजील, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हेरॉन का उपयोग करते रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

महिलाओं के खून का प्यासा

गैरी लियोन रिजवे एक ऐसा खौफनाक सीरियल किलर है, जो ग्रीन रीवर हत्यारा के नाम से जाना जाता था और जिसने अमेरिका में मौत का तांडव मचा रखा था. वह औरतों को बहला-फुसला कर अपने घर लाता था और उनका गला घोंट कर उन्हें मौत की नींद सुला देता था. 2001 में गैरी लियोन को पकड़े जाने से पूर्व वह अपनी खौफनाक मानसिकता के चलते 75-80 से भी ज्यादा महिलाओं को मार चुका था. 18 फरवरी, 1949 को उटाह के सॉल्ट लेक शहर में गैरी लियोन का जन्म हुआ और वहींउसका बचपन गुजरा, लेकिन कौन जानता था कि यही गैरी लियोन आगे चलकर मशहूर होगा और वो भी कुख्यात सीरियल किलर के नाम से. गैरी की खतरनाक मानसिकता का बड़ा रूप तब आया, जब1982 में उसने एक वैश्या को घिनौने तरीके से गला घोंट कर मार डाला और इस घटना के बाद से ही शुरू हो गया गैरी के हाथों वैश्याओं की हत्याओं का दौर. 2001 में रिजवे पुलिस की गिरफ्त में तब आया, जब डीएनए जांच ने उसके अपराध में होने की पुष्टि की. आगे चलकर रिजवे ने जाचंकर्ताओं के सामने यह खुलासा भी किया कि दक्षिण किंग काउंटी 99 मार्ग पर उसने 75 महिलाओं को अपना शिकार बनाया और बेरहमी से उनकी हत्याएं कर दी थी. शुरुआत से ही रिजवे का बचपन गरीबी के साये में गुजरा. उटाह में अपनी उच्च शिक्षा लेने के बाद वह वियतनाम चला गया. जब रिजवे वियतनाम से वॉशिंगटन में वापस आया तो उसे केनवर्थ ट्रक कारखाना में ट्रक पेंट करने का काम मिला. उसने ट्रक पेंट करने को ही अपनी रोजी-रोटी का साधन बनाया और 30 सालों तक यही काम किया . रिजवे बचपन से ही धर्म के प्रति कट्टर प्रवृत्ति का था. वैसे तो वह तीन बार शादी कर चुका था, लेकिन वैश्यागमन उसकी आदत थी. 1982 में जब रिजवे ने अपने खतरनाक मानसिकता का खेल खेलना शुरू किया, तो धीरे-धीरे दक्षिण किंग काउंटी 99 मार्ग पर महिलायें, जो वैश्यावृत्ति का काम करती थीं, वो गायब होने लगीं. रिजवे वैश्याओं को अपने घर ले जाता और दर्दनाक तरीके से उनका गला घोंट कर अपनी खतरनाक मानसिकता को अंजाम देता. रिजवे महिलाओं के मृत शरीर को सुनसान इलाके, जंगलो और ग्रीन नदी के पास ले जाता और वहीं उसे ठिकाने लगा देता. यही कारण था कि गैरी लियोन रिजवे को कुख्यात ग्रीन रीवर किलर के नाम से भी लोग जानने लगे थे. 2001 तक रिजवे कानून के आंखों में धूल झोंकने में लगा रहा, लेकिन जल्द ही रिजवे की असलियत दुनिया के सामने आ गई. किंग काउंटी शेरिफ दवे रीचर्ट, जिन्हें इस केस को सुलझाने की कमान सौंपी गई थी, उन्होंने इस केस को दोबारा जांचा और इस केस में डीएनए जांच की मदद ली. डीएनए जांच में रिजवे और मारी गई महिलाओं की जांच के लिये गए नमूने मिल गये, जिससे रिजवे के ऊपर 4 लोगों की हत्याएं करने का आरोप लगा. कानूनी कार्रवाई के दौरान रिजवे ने जांचकर्ताओं को यह बताया कि कहां-कहां उसने महिलाओं के मृत शरीर छुपाये थे, जो कि उस समय तक पुलिस को नहीं मिले थे. 2003 में कानून ने रिजवे द्वारा किये गए अपराध के लिये उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी. रिजवे अमेरिकी इतिहास में पहला और एक ऐसा सीरियल किलर था, जिसने बाकी सीरियल किलर के मुकाबले सबसे ज्यादा हत्याएं की थीं. अपने घिनौने अपराधों के लिये आज भी गैरी लियोन रिजवे जेल में सजा काट रहा है. ■

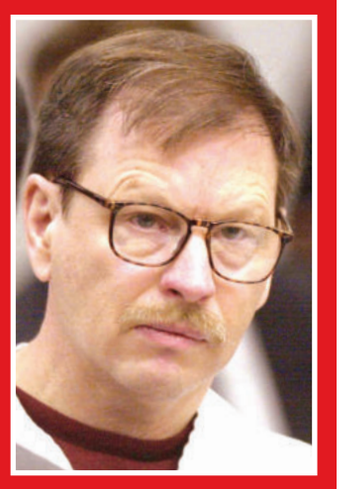

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त खबर

ओबामा को लगता है डर

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपनी ही धरती पर अपने ही देश में डर लग रहा है. करीब दो हफ्ते बाद अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक है. दुनिया भर से नेता इस बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं. मगर ओबामा जिस होटल में ठहरने वाले थे, उसे बदल दिया गया है. दरअसल, ओबामा को अपनी जासूसी का डर सता रहा है. सवाल ये है कि आखिर अपने ही देश में ओबामा की जासूसी कौन कर सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को हर पल ये डर सता रहा है कि कहीं कोई उनकी जासूसी तो नहीं करा रहा है. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहटन के वाल्डोर्फ–एस्टोरिया होटल में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ठहरने वाले थे. मगर खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि ये होटल सुरक्षित नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, इस आलीशान होटल में जिस वक्त ओबामा ठहरने वाले थे, उस दौरान उनकी जासूसी की तैयारी हो रही थी. परंपरा के मुताबिक पिछले कई साल से अमेरिकी राष्ट्रपति इसी होटल में ठहरते आए हैं. इसी होटल के भीतर कई अहम योजनाएं बनीं और कई अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन ओबामा के लिए ये परंपरा तोड़ दी गई. दरअसल, ये होटल है तो अमेरिका में, लेकिन इसका मालिकाना हक चीन के एक ग्रुप के पास है. जब इस होटल को खरीदा गया था तो उस समय इसकी कीमत लगाई गई थी 11 हजार करोड़ रुपये. ये दुनिया की अब तक की सबसे महंगी होटल डील है. इतने महंगे होटल में भी ओबामा सुरक्षित नहीं हैं. अमेरिका को ये डर है कि कहीं चीन उसके राष्ट्रपति की जासूसी न कर ले. जासूसी के डर से ही ओबामा का होटल बदलकर न्यूयॉर्क पैलेस कर दिया गया है. अब ओबामा और उनका प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क पैलेस में ही रुकेगा ■

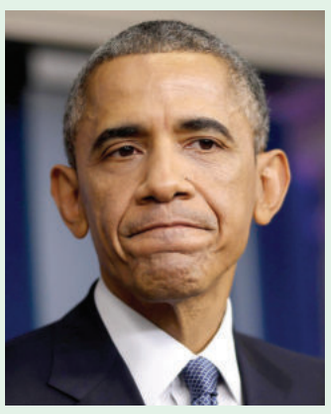

चीन के कोर्ट में जजों को मारा चाकू

चीन के चार न्यायाधीशों को एक साथ एक व्यक्ति ने चाकू मार दिया है. चीन के हुबेई प्रांत में श्रम संबंधी एक विवाद में अपने खिलाफ फैसला आने से एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर कोर्ट के अंदर चार न्यायाधीशों को चाकू मार दिया. शियान स्थित अदालत में हमलावर ने सुनवाई में फैसला आने के बाद परिसर में ही चार न्यायाधीशों को चाकू मार दिया. जानकारी के मुताबिक, हमलावर ने चाकू अखबार में लपेट कर छिपाया हुआ था, जैसे ही न्यायाधीशों ने केस का फैसला सुनाया, उसी वक्त मौका देखकर मुजरिम ने हमले को अंजाम दिया. अभी यह पता नहीं चल पाया है कि सुरक्षा जांच के बावजूद वह चाकू अंदर कैसे ले गया. एक दैनिक अखबार की खबर के मुताबिक, फिलहाल तो पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया. जिन चार न्यायाधीशों को चाकू मारा गया, उन्हें आनन–फानन में अस्पताल ले जाया गया. एक न्यायाधीश की हालत खबर लिखे जाने तक गंभीर थी. तीन अन्य न्यायाधीशों की सर्जरी की गई. सवाल उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा में कोई मुज़रिम इस तरह के हमले को बिना किसी की मदद लिये कैसे अंजाम दे सकता है? ■

सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़ाया

अफगानिस्तान में आतंकवादियों का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. तालिबान आतंकवादियों ने पिछले दिनों गजनी प्रांत में एक जेल पर हमला कर 350 से ज्यादा कैदियों को मुक्त करा लिया. समाचारपत्र डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, गजनी के उप प्रांतीय गर्वनर मोहम्म अली अहमदी ने बताया कि सुबह–सुबह किए गए इस हमले में चार पुलिसकर्मियों की जान चली गई और सात अन्य घायल हो गए. वहीं, तीन आतंकवादी भी मारे गए हैं. सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी सेना की ड्रेस में जेल में घुसे थे. आतंकवादियों ने कैदियों को मुक्त कराने के लिए नियोजित तरीके से हमला किया और करीब 350 कैदी फरार हो गए. अहमदी के मुताबिक, हमले की शुरुआत एक आत्मघाती हमलावर द्वारा स्वयं को उड़ाने से हुई, जिसके बाद अन्य आतंकवादी कारागार परिसर के अंदर घुस आए और सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे और इसी बीच 350 कैदियों को भी मुक्त करा लिया. तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मीडिया को ई–मेल भेज कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

योग-पद्धति का संपूर्ण विवरण महर्षि पातंजलि द्वारा लिखित योग-सूत्र ग्रंथ में मिलता है. लोग कभी-कभी योग क्रिया को प्राणायाम के साथ भी जोड़ देते हैं. कुछ लोग ध्यान करते समय पद्मासन तथा सिद्धासन जैसे आसन में बैठते हैं. परंतु श्री शिरडी साईं बाबा ने अपने किसी भी भक्त को इन योग-क्रियाओं के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया था. पर योग-क्रिया के विरुद्ध भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है.

साईं वंदना

बाबा के बताए रास्ते पर चलना चाहिए

ज्ञान मार्ग में लोग कितना भी पढ़ें, जब तक इस स्थूल ज्ञान में भक्ति का रस न जुड़े, तब तक उस सुक्ष्म रूप को नहीं पाया जा सकता. भक्ति-मार्ग की अपनी महत्ता है. जैसे-जैसे भाव का, भक्ति का सोपान उच्चतर होता जाता है, वैसे ही बुद्धि का, ज्ञान का सोपान भी स्वत: उच्चतर होता जाएगा. पर विपरीत रूप में यह संभव नहीं है.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

साईं-धुन

मन में साईं-धुन हमेशा क्यों नहीं चलती रहती और इसे सदा चलाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए?

अजपाजप हमारी सांस को कहते हैं, जो हमारे अंदर निरन्तर चलती रहती है. हम जपते नहीं हैं पर सांस अपनी गति से चलती है. सांस के साथ नाम को मिलाकर चलने से असर होता है. यह गृहस्थ आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बाकी कार्यों में मन लगाना पड़ता है. अच्छा यही है कि इस अजपाजप के साथ साईं-साईं को जोड़कर, हर समय न बोलकर बाबा की भावना को मन में रखें. हर कर्म और भावना से उनकी भावना को जोड़ते रहें. यही उनका मानसिक जप होगा. जब समय मिले तो साईं नाम लीजिए. बैठकर अपनी हर सांस के साथ साईं-नाम लेकर जप करें.

अनोखी योग शिक्षा

क्या बाबा ने अपने भक्तों को योग-शिक्षा दी थी? आजकल प्रचलित जैसी योग-शिक्षा दी जा रही है, उस प्रकार की योग-शिक्षा के बारे में आपकी अवधारणा क्या है?

लोग योग को साधारणत: एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम समझते हैं, जो कि मुद्रा और आसन के साथ किया जाता है. योग-पद्धति का संपूर्ण विवरण महर्षि पातंजलि द्वारा लिखित योग-सूत्र ग्रंथ में मिलता है. लोग कभी-कभी योग क्रिया को प्राणायाम के साथ भी जोड़ देते हैं. कुछ लोग ध्यान करते समय पद्मासन तथा सिद्धासन जैसे आसन में बैठते हैं. परंतु श्री शिरडी साईं बाबा ने अपने किसी भी भक्त को इन योग-क्रियाओं के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया था. पर योग-क्रिया के विरुद्ध भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है. श्री उपासनी बाबा जैसे बाबा के कुछ महान भक्त बाबा से मिलने से पहले संपूर्ण योग-क्रिया के बारे में अभ्यास कर चुके थे. श्री उपासनी महाराज बाबा के आदेशानुसार खंडोबा मंदिर में तीन वर्ष से अधिक अवधि तक रहे, पर बाबा ने उनको कभी भी इस प्रकार योग-क्रिया करने के लिए नहीं कहा था. भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाबा के द्वारा किया गया पथ-प्रदर्शन मानसिक शुद्धिकरण, मानसिक नियंत्रण और मानसिक उन्नयन पर आधारित था. इस विषय में बाबा ने इस प्रकार किसी कभी भी किसी मुद्रा में बैठने के लिए नहीं कहा था. वे शारीरिक नियंत्रण की अपेक्षा मानसिक नियंत्रण पर अधिक बल देते थे.

बाबा का रास्ता : भक्तिमार्ग

बाबा को पाने के लिए ज्ञान-प्रधान मार्ग से चलना चाहिए या भक्ति प्रधान मार्ग से? क्योंकि कई बुद्धिजीवी ज्ञान-मार्ग को अधिक श्रेयस्कर समझते हैं.

आजकल बाबा के बारे में लोग बहुत सी किताबें पढ़कर अपने को सिद्ध समझते हैं. इस संबंध में बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, लोग उन्हें पढ़ते हैं. ज्ञान मार्ग में लोग कितना भी पढ़ें, जब तक इस स्थूल ज्ञान में भक्ति का रस न जुड़े, तब तक उस सुक्ष्म रूप को नहीं पाया जा सकता. भक्ति-मार्ग की अपनी महत्ता है. जैसे-जैसे भाव का, भक्ति का सोपान उच्चतर होता जाता है, वैसे ही बुद्धि का, ज्ञान का सोपान भी स्वत: उच्चतर होता जाएगा. पर विपरीत रूप में यह संभव नहीं है. अर्थात भक्ति द्वारा ज्ञान को पाया जा सकता है, परंतु बुद्धि द्वारा उस भक्ति-भाव को नहीं पाया जा सकता. भक्त कहेगा-

ङ्गहे ईश्वर! जो ज्ञान तुम हमें दे रहे हो, वह ज्ञान का अनुभव मेरा नहीं है, वह तो तुम्ही से मिला है.फ्फ

किन्तु ज्ञान मार्ग पर चलने वाला अपने को श्रेष्ठ समझता है. भक्ति से उत्तपन्न ज्ञान निरहंकार करता है, पर बुद्धि से जो ज्ञान होता है, वह अहंकार उत्पन्न करता है.

शुद्ध अंतर्मन से साईं-भक्ति

बाबा से पाक मोहब्बत हम करना चाहते हैं पर उसके रास्ते से अनजान हैं, आपसे हमें मदद चाहिए. एक व्यक्ति अच्छा साईं भक्त कब और कैसे बन सकता है?

बाबा से पाक मोहब्बत करने का अर्थ है-बाबा के द्वारा कहे हुए और बताए हुए रास्ते पर पूर्ण रूप से चलना. पहले तो खुद को साफ करने की आवश्यकता है, जिसमें कई वर्ष या जन्म लग सकते हैं. फिर भी प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए. अपने अन्दर ईश्वरीय गुण-जैसे दया, क्षमा, अंहिसा, सेवा आदि जगाने से सद्गुरू साथ चलने लगते हैं. ङ्गश्री साईं सच्चरित्रफ्फ पढ़ने से पता चलने लगता है कि वे लोग बाबा के करीब थे, जो उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके थे. बाहर की पूजा अर्चना आदि अंतर्मन को साफ करने का माध्यम ही है. फिर भी मात्र पूजा पाठ कर लेने से पूर्ण साईं-भक्ति नहीं मिल सकती, जब तक अंर्तमन साफ न हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

धर्म

आस्था का केंद्र हैं नंदा देवी

नंदा देवी हिमालय की पुत्री हैं. नंदा देवी को नवदुर्गा एक रूप बताया गया है. भविष्य पुराण जिन नौ दुर्गा का उल्लेख है उसमें नंदा देवी का भी नाम है. भाद्र मास की पंचमी से नंदा देवी का मेला आरंभ होता है. इसकी शुरुआत राजा बाज बहादुर चंद्र (सन १६३८-७८) के शासन काल से हुई थी.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड में आदिशक्ति नंदादेवी का पवित्र धाम है और नंदा देवी शक्ति के रुप पूरे हिमालय में पूजी जाती हैं. अलमोड़ा शहर के माल रोड पर नंदा देवी का मंदिर स्थित है. चमोली के घाट ब्लॉक में स्थित कुरड़ गांव को नंदादेवी का मायका और थराली ब्लॉक में स्थित देवराडा को उनका ससुराल कहा जाता है. नंदादेवी 6 महीने ससुराल और 6 महीने मायके में रहती हैं. नंदा देवी हिमालय की पुत्री हैं. नंदा देवी को नवदुर्गा एक रूप बताया गया है. भविष्य पुराण जिन नौ दुर्गा का उल्लेख है उसमें नंदा देवी का भी नाम है. भाद्र मास की पंचमी से नंदा देवी का मेला आरंभ होता है. इसकी शुरुआत राजा बाज बहादुर चंद्र (सन 1638-78) के शासन काल से हुई थी. पंचमी तिथि को जागर के माध्यम से मां नंदा-सुनंदा का आह्वान किया जाता है. इसी दिन गणेश पूजन कर कार्य के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की जाती है. षष्टी तिथि को मां नंदा-सुनंदा की मूर्ति निर्माण को कदली वृक्षों को निमंत्रण दिया जाता है. अगले दिन सप्तमी तिथि को इन कदली वृक्षों को प्रात:काल ढोल-नगाड़ों के साथ नंदादेवी मंदिर परिसर में लाया जाता है. बाद में दोपरहर के समय राजाओं के वंशजों द्वारा इन कदली वृक्षों का पूजन किया जाता है. रात्रि में इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में बकरे की भी बली दी जाती है. इसके अगले दिन नंदाष्टमी को दिन में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा मां नंदा-सुनंदा की पूजा-अर्चना की जाती है तथा रात्रि में पूजा-अर्चना की जाती है. यह पूजा तांत्रिक विधि से होती है. अष्टमी को विशेष पूजा-अर्चना के बाद मां नंदा-सुनंदा की मूर्तियों की नगर परिक्रमा कराकर उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है. गढ़वाल के पंवार राजाओं की भांति कुमांऊ के राजाओं की कुलदेवी भी नंदा देवी मानी जाती हैं, इसलिए दोनों ही मंडलो के लोग नंदा देवी के उपासक हैं. हर वर्ष होने वाली नंदा देवी की इस डोली को छोटी नंदा राजजात भी कहते हैं और नंदा महा राजजात हर 12 साल में आयोजित होती है. मां नंदा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तथा सुख-शांति का अनुभव करता है. ■

प्रेरक कहानी

अमृतत्व की किरण

एक राजा अपने वज़ीर से नाराज हो गया और उसे एक बहुत बड़ी मीनार के ऊपर कैद कर दिया. उस गगनचुम्बी मीनार से कूदकर उसके भागने की कोई संभावना थी. जब उसे पकड़कर मीनार पर ले जाया गया, तब वह जरा भी चिंतित और दुखी नहीं था उल्टे सदा की भांति आनंदित और प्रसन्न था. उसकी पत्नी ने रोते हुए पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? उसने कहा, यदि रेशम का एक बहुत पतला सूत भी मिल जाए तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा. क्या इतना-सा काम भी तुम नहीं कर सकोगी? उसकी पत्नी को समझ में नही आ रहा था कि ऊंची मीनार पर रेशम का पतला धागा कैसे पहुंचाया जाए. तब उसने एक फकीर से पूछा. फकीर ने कहा, भृंग नाम के कीड़े को पकड़ो. उसके पैर में रेशम के धागे को बांध दो और उसकी मूंछों के बालों पर शहद की एक बूंद रखकर उसका मुंह चोटी की ओर करके मीनार पर छोड़ दो. उसी रात को ऐसा किया गया. वह कीड़ा सामने मधु की गंध पाकर, उसे पाने के लोभ में, धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगा और आखिर उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली. रेशम के धागे का एक छोर कैदी के हाथ में पहुंच गया. रेशम का यह पतला धागा उसकी मुक्ति और जीवन बन गया. उससे फिर सूत का धागा बांधकर ऊपर पहुंचाया गया, फिर सूत के धागे से डोरी और डोरी से मोटा रस्सा. उस रस्से के सहारे वह कैद से बाहर हो गया. सूर्य तक पहुंचने के लिए प्रकाश की एक किरण बहुत है. वह किरण किसी को पहुंचानी भी नहीं है. वह तो हर एक के पास मौजूद है. ■

पाठकों की दुनिया

पटेलों का आंदोलन अनुचित

पहले गुर्जर फिर जाट और अब गुजरात में पटेलों के आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा आन्दोलन हिंसक होता जा रहा है. आन्दोलन को धार देने के लिए ट्रेने रोकना व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है. आरक्षण एक फौरी राहत है. स्थायी सुविधा नहीं. अगर किसी रोगी को अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो स्वस्थ हो जाने पर उसे अस्पताल से जाना होगा. वह हमेशा अस्पताल में रहने का दावा नहीं कर सकता. वर्षों से आरक्षण का लाभ ले रहे लोग उसे छोड़ना तो दूर, आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं. कुछ पिछड़ी जातियां खुद को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने की मांग कर रही हैं. आश्चर्य है कि जो जाट और पटेल अपने को पिछड़ा कहने में अपमान का अनुभव करते थे, आज आरक्षण के लिए आन्दोलन कर रहे हैं.

-राज किशोर पाण्डेय(प्रहरी), लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

पाठ्यक्रम में सुधार जरूरी

देश भर के स्कूलों में समान पाठ्यक्रम सामाजिक समरसत्ता और समानता का व्यापक आधार तैयार करता है, लेकिन पता नहीं क्यों? आजादी के 68 साल बाद भी इसकी जरूरत नहीं समझी जा रही है. आज जब नई शिक्षा नीति तैयार हो रही है, समान पाठ्यक्रम के दायरे में निजी स्कूलों को भी लाना चाना चाहिए, जिससे देश की भावी पीढ़ी शिक्षित होने के साथ-साथ संस्कारित भी हो और यह इसलिए भी आवश्यक है कि आजादी मिलने के बाद सामाजिक सुधार के आंदोलन भी शिथिल पड़ गए. आज कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मुहिम चलाता हो, किसी दल के घोषणा पत्र में आज संस्कारवान व चरित्रवान पीढ़ी के निर्माण के लिए दो शब्द भी नहीं मिलते जिसके खतरनाक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं.

-सत्य प्रकाश (शिक्षक) लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

बिहार को सबने ठगा है

कवर स्टोरी-बिहार विधानसभा चुनाव, जनता में उत्साह नहीं है(4 सितंबर-20 सितंबर 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. मैं मनीष कुमार से सहमत हूं, कि बिहार में विकास की किरण तो दूर, विकास की परछाई भी कहीं नजर नहीं आती. बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां विकास का दावा कर रही हैं. बिहार की जनता को सभी सरकारों ने केवल धोखा दिया है. बिहार को सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस और राजद ने पहुंचाया है. लालू यादव का कार्यकाल को तो जगंलराज के नाम से प्रचलित है. सरकारें बिहार से पलायन रोकने में नाकामयाब रहीं हैं. बिहार के गांवों में जाने पर वहां के विकास की सच्चाई नजर आती है. बिहार में जब तक जातिवाद की राजनीति होगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि नेता लोगों को ऐसे जाति के नाम बेवकूफ बनाते रहेंगे और सत्ता का सुख भोगते रहेंगे. इसलिए इस विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता को जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए मतदान करना चाहिए.

-रविशंकर ओझा, बक्सर, बिहार.

प्रधानमंत्री जी, भरोसा न टूटने पाए

जब तोप मुकाबिल हो-अगर यह संपादकीय गलत है, तो हमें सच्चाई बताईए(4 सितंबर-20 सितंबर 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने बिल्कुल सही कहा है. इस संपादकीय में एक भी गलत बात नहीं है. यह बिल्कुल सही है कि रेल किराया से लेकर खाने पीने तक की सारी चीजें अब महंगी हो चुकी हैं. प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी, तो महंगाई सौ दिन में कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई कम होने की बात तो दूर और बढ़ गई है. दाल से लेकर प्याज तक के दाम आसमान छू रहे हैं. प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी ने जो वादा किया था, उसमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है. कालाधन को लेकर बड़ी-बड़ी बाते करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब चुप क्यों हैं? माना कि देश के प्रत्येक लोगों को 15 लाख रुपये देने का वादा जुमला था, लेकिन क्या सौ दिन में कालाधन लाने वाली बात(वादा) भी झूठी थी? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता जवाब चाहती है. प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी से भी अब देश के लोगों का भरोसा टूटने लगा है. प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा करिए और लोगों को भरोसा मत टूटने दीजिए.

-राकेश मौर्या, पटना, बिहार.

निर्भीक समाचार पत्र

मैं चौथी दुनिया समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित कवर स्टोरी सभी समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से बिल्कुल अलग होती है. कवर स्टोरी(4 सितंबर-20 सितंबर 2015) पढ़ा. बिहार विधानसभा चुनाव, जनता में उत्साह नहीं है. बहुत अच्छा लगा अभी तक किसी भी समाचार पत्र और पत्रिका ने बिहार के गांवों और बिहार के विकास की सच्चाई प्रकाशित नहीं की थी. इस कवर स्टोरी से बिहार के विकास की सच्चाई का पता चलता है. इस अंक में प्रकाशित सभी खबरें प्रभावित करने वाली थीं. पहले से भी अधिक और भी अच्छी खबरें समाचार पत्र में पढ़ने को मिल रही हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में व्यापमं पर सबसे अच्छी खबर पढ़ने को मिली. चौथी दुनिया एक निर्भीक समाचार पत्र है.

-विकास यादव, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

हास्यास्पद विरोध, लचर दलील

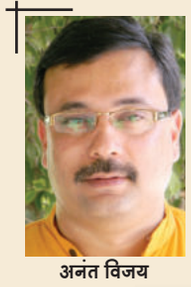
अनंत विजय

भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन खत्म हो गया. इस तरह के सम्मेलनों की सार्थकता को लेकर पिछले हफ्ते भर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं. एक ख़ास वर्ग और ख़ास विचारधारा के लेखकों के द्वारा. इन सवालों को विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के कथित बयान ने और हवा दे दी. ख़बरों के मुताबिक वीके सिंह ने कहा था कि इस बार का सम्मेलन पूर्व के सम्मेलनों से जुदा है. पहले साहित्यकार लोग आते थे, खाते–पीते थे और पर्चा पढ़कर चले जाते थे. उनके मुताबिक इस बार भाषा पर बात होनी थी साहित्य और साहित्यकारों पर कम, लिहाज़ा उनको नहीं बुलाया गया. बाद में उन्होंने अपने इस बयान का खंडन करते हुए मीडिया पर उसको तोड़–मरोड़कर पेश करने का आरोप जड़ दिया. खैर चाहे जो भी हो लेकिन जनरल वीके सिंह के उक्त बयान के बाद विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर विरोध तेज हो गया था, ख़ासकर सोशल मीडिया आदि पर सक्रिय लेखकों ने छाती कूटनी आरंभ कर दी थी. विरोध में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गईं, इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग किया जैसी शब्दावलियां इस्तेमाल करने के पहले जाहिलों और अनपढ़ों को भी हिचक होती है. फेसबुक पर भक्तों से भाषा की मर्यादा की अपेक्षा करनेवालों ने मर्यादा तार–तार कर दी. दरअसल यह एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी का चौबीसों घंटे विरोध करोगे तो उसके बहुत सारे गुण–अवगुण तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे. भक्तों के विरोधियों के साथ भी यही हुआ. वो वैसी ही भाषा बोलने–लिखने लग गए. इस बार अगर सरकार ने तय किया था कि विश्व हिंदी सम्मेलन में साहित्य पर कम भाषा पर ज्यादा बात होगी तो इसमें गलत क्या था? भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए तकनीक से जुड़ने पर विमर्श होने में बुराई क्या है? दरअसल ललबबुआओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने से दिक्कत थी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निजी हमले हुए. उनकी कविताओं को लेकर तंज कसे गए. यह सब सही है लेकिन यहां पर आग्रह सिर्फ इतना है कि किसी भी विरोध के पहले इतिहास बोध का ज्ञान होना आवश्यक है,अन्यथा विरोध खोखला लगता है या फिर वो व्यक्तिगत कुंठा की अभिव्यक्ति मात्र होकर रह जाती है. विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को लेकर हो–हल्ला मचानेवालों को यह याद दिलाना जरूरी है कि जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था तब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को 10 जनवरी 1975 को संबोधित किया था. इस बात का या तो मोदी का विरोध करनेवालों को ज्ञान नहीं है या फिर वो सुविधानुसार भुला देने का खेल खेल रहे हैं. दोनों ही स्थिति चिंताजनक है. अज्ञानता तो फिर भी कम ख़तरनाक है लेकिन अगर जानबूझकर लोगों को भरमाने के लिए तथ्य छिपाए जा रहे हैं तो यह अपेक्षाकृत ज्यादा खतरनाक है. दरअसल एक खास विचारधारा के लोगों कि यह खूबी है जिसमें वो तथ्यों को छिपाकर विरोध का खेल खेलते हैं. अश्वत्थामा हतो नरो के बाद शंख बजाकर द्रोणाचार्य पर हमला करने की नीति का अनुसरण करते हैं. उन्हें यह याद रखना चाहिए कि धर्मराज युधिष्ठिर के दामन पर सिर्फ वही एक दाग है.

विश्व हिंदी सम्मेलन के विरोधियों के पेट में इस बात को लेकर भी दर्द हो रहा है कि अमिताभ बच्चन को क्यों बुलाया गया? ये तो अच्छा हुआ कि अमिताभ बच्चन के दांत दर्द ने उनके विरोधियों के पेट दर्द को ठीक कर दिया. अमिताभ बच्चन को विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन में एक सत्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था. अंतिम समय में उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आ पाए. तबतक उनपर आरोपों की बौछार शुरू हो गई थी. ये कहा गया कि उनका हिंदी से क्या लेना देना? पिता की कविताओं को महफिलों में पढ़कर पैसे कमाने से लेकर भांड आदि तक कहा गया. सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय एक अध्यापक–लेखक ने कहा कि–हिंदी साहित्य में अभिनेता अमिताभ बच्चन के योगदान के बारे में गूगल से लेकर राष्ट्रीय पुस्तकालय तक पर कहीं कोई रचना नहीं मिलेगी. इसके बावजूद उनको मोदी सरकार ने दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन सत्र में आमंत्रित किया है. यह संकेत है कि मोदी जी की निष्ठा साहित्य में नहीं मुंबईया सिनेमा में है. अब इतने विद्वान लेखक को क्या बताया जाए कि ये विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन नहीं था. मैं यह मानकर चलता हूं कि उनको इतना तो ज्ञान होगा ही कि साहित्य और भाषा में थोड़ा फर्क तो है. रही बात अमिताभ बच्चन के हिंदी साहित्य में योगदान की. ना तो अमिताभ बच्चन ने और ना ही इस वक्त की सरकार ने कभी ये दावा कि बच्चन साहब बड़े साहित्यकार हैं, पर हिंदी के प्रचार–प्रसार को लेकर अमिताभ के प्रयास सराहनीय हैं. अमिताभ बच्चन का विरोध करनेवालों को मालूम होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन अब भी देवनागरी में ही फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जिसका चलन बॉलीवुड में अब खत्म हो गया है. सारी हिंदी फिल्मों के डॉयलॉग रोमन में लिखे जाते हैं और अभिनेता और अभिनेत्री उसको ही पढ़ते हैं. ऐसे माहौल में अमिताभ बच्चन का देवनागरी को अहमियत देना काबिले तारीफ है. दरअसल अमिताभ बच्चन को जिस सत्र में बोलना था उसका विषय था–अच्छी हिंदी कैसे बोलें. आज अमिताभ बच्चन के उच्चारण और कठिन से कठिन हिंदी शब्दों को सहजता के साथ बोलकर लोकप्रिय बना देने की कला का कोई सानी नहीं है. कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने हिंदी के उन लुप्तप्राय शब्दों को संजीवनी दे दी जिसका प्रयोग तो अब हिंदी के साहित्यकार भी नहीं करते हैं. पंचकोटि जैसा शब्द एक बार फिर से चलन में आ गया. अमिताभ बच्चन के विरोध को देखकर जोहानिसबर्ग में हुए नवें विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरीशस के कला और संस्कृति मंत्री मुकेश्वर चुन्नी का भाषण याद आ गया. मॉरीशस के कला और संस्कृति मंत्री मुकेश्वर चुन्नी ने ये माना था कि हिंदी के प्रचार प्रसार में बॉलीवुड फिल्में और टीवी पर चलने वाले सीरियल्स का बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी जो भी हिंदी है वो सिर्फ हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की बदौलत है. जब वो हिंदी में बोल रहे थे तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी जबरदस्त था, भारतीय राजनेताओं की तरह जबरदस्ती ओढ़े हुए गंभीरता के आवरण से एकदम अलग. चुन्नी ने अपने भाषण में कहा कि वो किसी और कार्यक्रम के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे और उन्हें विश्व हिंदी सम्मेलन में आना पड़ा. इस वजह से उनके अधिकारियों को उनका भाषण तैयार करने का मौका नहीं मिला पाया, लिहाज़ा वो हिंदी में बगैर किसी नोट्स के बोले थे. चुन्नी ने फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स की जमकर तारीफ की और कहा कि हिंदी के फैलाव में सबसे ज्यादा योगदान उनका ही है. जोहानिसबर्ग में तीन दिन तक कई अहिंदी भाषी लोगों से बातचीत के बाद मुझे भी यह लगा था कि हिंदी के प्रचार–प्रसार में फिल्मों का बहुत योगदान है. दरअसल फिल्मी कलाकारों को लेकर हिंदी के वामपंथी लेखक कभी संजीदा नहीं रहे. फिल्म वालों को बुर्जुआ संस्कृति का शोषक मानकर उनकी लगातार उपेक्षा की जाती रही. हिंदी फिल्मों के बड़े से बड़े गीतकार को हिंदी का कवि नहीं माना गया जबकि विचारधारा का झंडा उठाकर घूमनेवाले औसत कवियों को महान घोषित कर दिया गया. ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान समारोह में भी अमिताभ बच्चन को बुलाने को लेकर विरोध हुआ था लेकिन तब भी हिंदी समाज ने चंद लेखकों के विरोध को खारिज कर दिया था, अहमियत नहीं दी थी.

विश्व हिंदी सम्मेलन के विरोधियों के पेट में इस बात को लेकर भी दर्द हो रहा है कि अमिताभ बच्चन को क्यों बुलाया गया? ये तो अच्छा हुआ कि अमिताभ बच्चन के दांत दर्द ने उनके विरोधियों के पेट दर्द को ठीक कर दिया. अमिताभ बच्चन को विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन में एक सत्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था.

विश्व हिंदी सम्मेलन का विरोध करनेवाले इन्हीं छोटी चीजों में उलझकर रह गए. इस बात पर सवाल खड़े होने चाहिए कि सत्रों के वक्ताओं का चयन किस आधार पर हुआ. उन वक्ताओं की क्या विशेषता रही है. सवाल इस बात पर खड़े किए जाने चाहिए कि पिछले नौ सम्मेलनों में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उनका क्या हुआ. हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं. हिंदी के युनिवर्सल फांट आदि को लेकर सरकार क्या कर रही है. दरअसल तथ्यों के आधार पर विरोध करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है, गंभीर सवालों से मुठभेड़ के लिए गंभीरता से अध्ययन की भी आवश्यकता होती है. फेसबुक आदि पर जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी की अराजकता है उसमें तो बगैर तथ्यों के सिर्फ हवाबाजी के आधार पर विरोध होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है बल्कि उस तरह का विरोध हास्यास्पद हो जाता है. और विरोध जब हास्यास्पद होते हैं तो विरोध करनेवाले हास्य के पात्र बन जाते हैं. आग्रह यही है कि खुद को हास्यास्पद ना बनाएं. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

साहित्यकार

टी एस एलियट अंग्रेजी में आधुनिक काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों में शुमार किए जाते हैं. उनकी 1917 में प्रकाशित कविता द लव सॉन्ग ऑफ जे एलफ्रेड प्रूफॉक उस समय की प्रख्यात कृति है. इस कविता में एलियट ने मानवीय मनोभावों की विकृतियों, उथलेपन और आधुनिकता से उपजे अकेलेपन का सजीव चित्रण किया है. इसके अलावा फैमिली रियूनियन और मर्डर इन द कैथेड्रल जैसे बेहतरीन नाटक भी टीएस एलियट की देन हैं. उनकी लंबी कविता वेस्ट लैंड भी काफी प्रसिद्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

योगी का संघर्ष और व्यवस्था का सच

महेंद्र अवधेश

किसी ने सच कहा है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर–ए–खुदा होता है. योग, आयुर्वेद, स्वदेशी एवं वैदिक ज्ञान का अनमोल उपहार देश समेत पूरी दुनिया को बांटने वाले स्वामी रामदेव को न जाने किन–किन विषम हालात से जूझना पड़ा, न जाने कितने आरोप झेलने पड़े, अपमान–दमन सहना पड़ा. लेकिन, ईश्वरीय न्याय हमेशा अद्भुत होता है. आज सारी दुनिया स्वामी रामदेव के सच से वाकिफ है कि वह वाकई एक संत हैं और अपने संताचरण से जन–सामान्य, देश–दुनिया के कल्याण में लगे हुए हैं. पत्रकार संदीप देव की हालिया प्रकाशित पुस्तक स्वामी रामदेव: एक योगी–एक योद्धा इस सच को पूर्णत: प्रमाणित करती है.

बालक रामकृष्ण आख़िर कैसे बना स्वामी रामदेव, एक बालसखा: जिसने स्वामी रामदेव के स्वप्न को दिया मूर्त रूप, पतंजलि बना योग–आयुर्वेद–स्वदेशी एवं वैदिक ज्ञान परंपरा का केंद्र, भारत स्वाभिमान आंदोलन, चार जून 2011: भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस, मुक़दमों का मकड़जाल और राजनीतिक विकल्प की तैयारी जैसे अति महत्वपूर्ण अध्यायों में संदीप देव ने स्वामी रामदेव के अब तक के जीवन का विस्तृत एवं सारगर्भित वर्णन किया है. चार जून 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में स्वामी रामदेव के योग–प्राणायाम कार्यक्रम के लिए जुटे जन–सैलाब को जिस तरह पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा, वह किसी से छिपा नहीं है और न लोग उस घटना को जल्दी भूल सकेंगे. आज़ाद भारत में निद्रा में लीन महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों पर पुलिस द्वारा जिस तरह लाठियां भांजी गईं, उसने बताया कि सत्ता किसी को किस कद अंधा बना देती है कि वह सही–ग़लत का और उचित–अनुचित में भेद नहीं कर पाता.

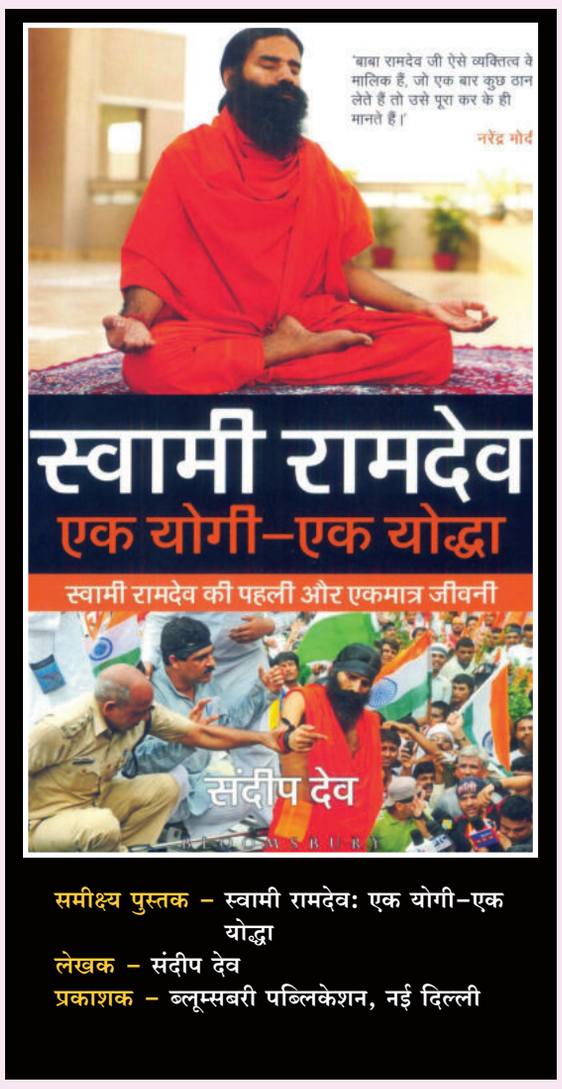

समीक्ष्य पुस्तक – स्वामी रामदेव: एक योगी–एक योद्धा
लेखक – संदीप देव
प्रकाशक – ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली

दस अध्यायों और लगभग 250 पृष्ठों वाली यह पुस्तक संदीप देव के असीम धैर्य, अथक परिश्रम और गहन शोध का परिणाम है. अपनी बात कहने के लिए संदीप ने किसी खास विशेषण, खास तौर–तरीके और किसी खास भाषा–शैली का प्रयोग करने से परहेज रखा, यह उनकी एक बड़ी लेखकीय कामयाबी है. स्वामी रामदेव की इस पहली और एकमात्र जीवनी में उल्लेखित प्रत्येक घटना, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक तथ्य–प्रमाण पर अपनी बात कहने और उसे पाठकों तक पहुंचाने के लिए संदीप ने सरल–सहज और आम भाषा का प्रयोग किया, जो उनके अंदर बैठे पत्रकार का प्रमाण है. एक पत्रकार का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह किसी घटना, किसी स्थिति, किसी फ़ैसले और किसी सूचना को पाठकों तक इस ढंग से पहुंचाए कि वे उसे अच्छी तरह समझ सकें. यह पुस्तक निश्चित तौर पर पाठकों को स्वामी रामदेव और उनके साथ–साथ आचार्य बालकृष्ण की अब तक की जीवन–यात्रा, कार्यों तथा देश–समाज के प्रति दोनों के सकारात्मक दृष्टिकोण से परिचित कराएगी. और, पाठक देश के राजनीतिक–सामाजिक वातावरण के उन तमाम अनछुए पहलुओं से भी दो–चार होंगे, जो बड़े पैमाने पर संचार क्रांति के बावजूद जन–सामान्य के बीच उजागर नहीं हो सके अथवा उन्हें उजागर नहीं होने दिया गया. ■

बालक रामकृष्ण आख़िर कैसे बना स्वामी रामदेव, एक बालसखा: जिसने स्वामी रामदेव के स्वप्न को दिया मूर्त रूप, पतंजलि बना योग-आयुर्वेद-स्वदेशी एवं वैदिक ज्ञान परंपरा का केंद्र, भारत स्वाभिमान आंदोलन, चार जून 2011: भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस, मुक़दमों का मकड़जाल और राजनीतिक विकल्प की तैयारी जैसे अति महत्वपूर्ण अध्यायों में संदीप देव ने स्वामी रामदेव के अब तक के जीवन का विस्तृत एवं सारगर्भित वर्णन किया है.

mahendra.awdhesh@gmail.com

कविता

गुलज़ार

रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है
रात ख़ामोश है रोती नहीं हंसती भी नहीं
कांच का नीला सा गुम्बद है, उड़ा जाता है
ख़ाली–ख़ाली कोई बजरा सा बहा जाता है
चांद की किरणों में वो रोज़ सा रेशम भी नहीं
चांद की चिकनी डली है कि घुली जाती है
और सन्नाटों की इक धूल सी उड़ी जाती है
काश इक बार कभी नींद से उठकर तुम भी
हिज्र की रातों में ये देखो तो क्या होता है.
.....
मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे
अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते
जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ
फिर से बांध के
और सिरा कोई जोड़ के उसमें
आगे बुनने लगते हो
तेरे इस ताने में लेकिन
इक भी गांठ गिरह बुन्तर की
देख नहीं सकता कोई
मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता
लेकिन उसकी सारी गिरहें
साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे
मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे.
.....
वो ख़त के पुरज़े उड़ा रहा था
हवाओं का रुख़ दिखा रहा था
कुछ और भी हो गया नुमायां
मैं अपना लिखा मिटा रहा था
उसी का इमान बदल गया है
कभी जो मेरा ख़ुदा रहा था
वो एक दिन एक अजनबी को
मेरी कहानी सुना रहा था
वो उम्र कम कर रहा था मेरी
मैं साल अपने बढ़ा रहा था.
.....
हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते
वक़्त की शाख़ से लम्हें नहीं तोड़ा करते

जिस की आवाज़ में सिलवट हो निगाहों में शिकन
ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते

शहद जीने का मिला करता है थोड़ा–थोड़ा
जाने वालों के लिये दिल नहीं थोड़ा करते

लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो
ऐसी दरिया का कभी रुख़ नहीं मोड़ा करते.

अरावली की पहाड़ियों से घिरे मानसून महल को 1884 में महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था, जिसे अब लोगों के लिए खोला गया है. धीमी बारिश के बाद मानसून महल पर चिड़ियों के झुंड की खूब आवाजाही होती है, यह दृश्य देखते ही बनता है.चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और आनंदित कर देनेवाली झीलें हैं.

सैर-सपाटा

झीलों का शहर उदयपुर

अपनी पुरानी राजधानी चित्तौड़गढ़ पर मुगलों के लगातार आक्रमण से परेशान होकर महाराणा उदय सिंह ने पिछौला झील के तट पर अपनी राजधानी बनाई, जिसे उदयपुर नाम दिया गया. शानदार बाग–बगीचे, झीलें, संगमरमर के महल, हवेलियां आदि इस शहर की शान में चार चांद लगाते हैं. अरावली की पहाड़ियों से घीरे और पांच मुख्य झीलों के इस शहर को देखने या घूमने–फिरने के लिए सबसे उत्तम समय सितंबर से अप्रैल के बीच है. इस शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो राजसी ठाठबाट का एहसास कराती हैं. यहां बेहद खूबसूरती से बनाई गई जगहें हैं, हवेलियां, गूंजते हुए रास्ते और खूबसूरत झीलें आप देख सकते हैं यहां. इस शहर में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं. यहां ठहरने के लिए सस्ते से लेकर महंगे हर तरह के होटल–रेस्तरां उपलब्ध हैं, जहां राजस्थानी व्यंजन परोसे जाते हैं. इसके साथ ही हाथ से बनी वस्तुओं की खरीदारी के लिए यहां के बाजार बेहद लोकप्रिय हैं. अरावली की पहाड़ियों से घिरे मानसून महल को 1884 में महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था, जिसे अब लोगों के लिए खोला गया है. धीमी बारिश के बाद मानसून महल पर चिड़ियों के झुंडों की खूब आवाजाही होती है, यह दृश्य देखते ही बनता है. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और आनंदित कर देनेवाली झीलें हैं.

इसके अतिरिक्त फतेह सागर झील, कृष्णा विलास, दूध तलाई, सज्जन निवास, गुलाब बाग, जग मंदिर, सज्जनगढ़ महल, कुंभागढ़ का किला, रनकपुर का जैन मंदिर और भारतीय लोक कला संग्रहालय देखने लायक हैं. उदयपुर में प्रमुख आकर्षण का केंद्र लेक पैलेस है, जो सन 1743–1746 के मध्य बनाया गया था. इसे देखकर लगता है, मानो यह महल पिछौला झील में तैर रहा है.

कैसे पहुंचें :

दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिये 11 घंटे की दूरी पर यह स्थित है और राजस्थान की राजधानी जयपुर से उदयपुर की दूरी लगभग 400 किमी है. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए हवाई मार्ग से लेकर सड़क और रेल जैसे किसी भी मार्ग से आने के कई विकल्प मौजूद हैं. ■

फैशन

गुवाहटी में 17वें सिग्नेचर अवॉर्ड में अपने जुल्फों का जलवा बिखेरती मॉडल्स.

अपनी पेनड्राइव को रैम बनाएं

श्याम सुन्दर प्रसाद

अगर पेनड्राइव का प्रयोग डाटा ट्रांसफर के अलावा कंप्यूटर की रैम के रूप में भी हो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज्यादा उसमें लगी रैम की क्षमता पर निर्भर करती है. कितना अच्छा होगा कि आप अपनी पेनड्राइव को रैम बनाना जान जायें. इससे आपका काम भी हो जाएगा और अतिरिक्त पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे.

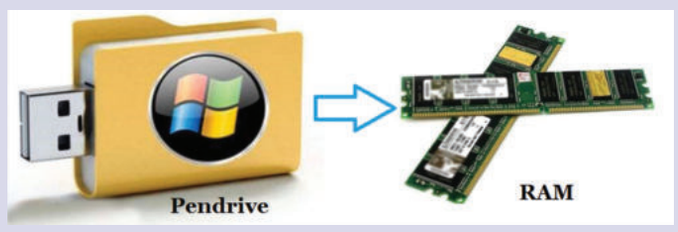

कैसे बनाएं पेनड्राइव को रैम

पेनड्राइव को रैम बनाने के लिए सबसे पहले पेन ड्राइव को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करें (पेनड्राइव कम से कम 2 जीबी या उससे ज्यादा की हो). फिर माय कंप्यूटर आइकॉन पर राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी, उसमें एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करें. अगर आप विंडोज एक्सपी का प्रयोग कर रहे हैं तो एडवांस्ड टैब पर क्लिक करें. फिर एडवांस्ड टैब पर क्लिक कर सेटिंग ऑप्शन कर क्लिक करें. फिर परफॉरमेंस ऑप्शन विंडो खुलेगी, जिसमें एडवांस्ड टैब पर क्लिक करें और वर्चुअल मेमोरी के अंदर दिए हुए चेंज बटन पर क्लिक करें. क्लिक करते एक विंडो ओपन होगा, जिसमें 'ऑटोमैटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर आल ड्राइव' पर चेक करें कि टिक (चैकमार्क) लगा हुआ है या नहीं. अगर लगा हुआ हो तो उसे अन चेक कर दें. फिर दी गयी लिस्ट में से अपने पेनड्राइव को सेलेक्ट करें. उसके बाद कस्टम साइज पर क्लिक करें और अपनी पेनड्राइव में मौजूद स्पेस के अनुसार वह वैल्यू भरें और सेट बटन पर क्लिक करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें. क्लिक करते ही पॉपअप में एक मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें ओके पर क्लिक करें. अब एक दूसरे पॉपअप में री–स्टार्ट नाउ का बटन दिखेगा. उस पर क्लिक कर अपने कंप्यूटर को री–स्टार्ट करें. कंप्यूटर जब री–स्टार्ट हो रहा हो, तो पेनड्राइव कंप्यूटर में लगी होनी चाहिए. अब आपका कंप्यूटर जब री–स्टार्ट होगा तो पेनड्राइव रैम की तरह काम करने लगेगी और कंप्यूटर के परफॉरमेंस और स्पीड में आपको परिवर्तन दिखेगा. ■

smart7973@gmail.com

खाना पीना

राजस्थान की मिठास है घेवर

घेवर एक राजस्थानी मिठाई है, यह गोल आकार की होती है, जो घी, मैदा और चाशनी से बनाई जाती है. घेवर में भी आपको कई प्रकार की वेराइटी मिल जाएगी. जैसे प्लेन, मावा और मलाई वाली घेवर. आइये जानते हैं इसे बनाने की सरल विधि.

विधि–सबसे पहले चीनी का सीरप तैयार कर के एक किनारे रख दें. उसके बाद एक बड़े कटोरे में घी डालें. फिर दूध, मैदा और 1 कप पानी डाल कर एक पतला घोल बनाएं. अब थोड़े से पानी में पीला रंग मिला लीजिये और उस पानी को मैदे के घोल में डाल दीजिये. जरूरत के हिसाब से घोल में और अधिक पानी मिलाएं, क्योंकि घोल पतला होना चाहिये. अब एक स्टील का बर्तन लें, जो कि सिलिंडर के आकार का लंबा हो. मतलब उसकी ऊंचाई 12 इंच और मोटाई 5 इंच की हो. इस बर्तन में आधे तक घी से भर दीजिये और गर्म कर दीजिये. घी जब गर्म हो जाए, तब 50 मिली गिलास भर के घोल लीजिये और उसे घी के किनारे किनारे डालिये और बीच में एक छेद बनाइये. घोल डालने के बाद उसे थोड़ा सा समय दीजिये, जिससे वह बैठ जाए. इसके बाद फिर से गिलास भर कर दोबारा वही विधि अपनाइये. जब घेवर एक बार बैठ जाए, तब उसे पकने दीजिये. आप देखेंगे कि घेवर भूरा होने लगा. इसके बाद एक लोहे की कलछुल को घेवर के बीच में जो छेद है, वहां पर उसे डाल कर सावधानी से निकाल लें. अब इसका अत्यधिक घी निकल जाने दें और इसे चाशनी में डुबो दें और थोड़ी देर के बाद इसे निकाल कर किनारे रख दें, जिससे इसका सीरप निकल जाए. जब यह हल्का ठंडा हो जाए, तब इस पर सिल्वर फॉयल लगा दें और केसर का दूध डालें. कटे हुए मेवे डाल कर इलायची पाउडर छिड़क दीजिये. आपका घेवर सर्व करने के लिये तैयार है.

सामग्री–3 कप मैदा, 1 कप घी, 3–4 आइस क्यूब्स, 4 कप पानी, 1/2 कप दूध, 1/4 चम्मच पीला रंग, 1 किलो घी

सीरप : 1/2 कप चीनी, 1 कप पानी सजावट के लिये, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच बादाम (कटे हुए), 1 चम्मच पिस्ता, 1 चम्मच दूध, 1/2 चम्मच दूध में भिगोया हुआ केसर सिल्वर फ्वॉइल ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

करियर

क्रिएटिव हैं तो सीखें ग्राफिक डिजाइनिंग

अगर आपको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है. ग्राफिक डिजाइन वह आर्ट है, जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक के द्वारा किसी मैसेज को लोगों तक इफेक्टिव तरीके से पहुंचाया जाता है. यह मैसेज ग्राफिक्स, लोगो, ब्रोशर, न्यूज लेटर, पोस्टर या फिर किसी भी रूप में हो सकता है. यह काम डिजाइनर कलर, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफ, एनिमेशन और अलग–अलग तरह के लेआउट्स के जरिए डिजाइन करता है. ग्राफिक डिजाइनर किसी पेज का ओवरऑल लेआउट बनाता है और फिर उसे अट्रैक्टिव लुक के साथ डिस्प्ले करता है, जिससे पढ़ने वाले को वह अच्छा लगे. प्रॉडक्ट को अलग पहचान दिलवाने में भी ग्राफिक डिजाइनर बेहद काम आता है.

करियर ऑप्शन

विज्ञापन–एजेंसी, पब्लिक रिलेशन, न्यूज पेपर, एडवरटाइजिंग एजेंसी, वेब पेज मैग्जीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे फील्ड में ग्राफिक डिजाइनर्स की बेहद डिमांड रहती है. खासतौर से फिल्म, विज्ञापन और एनिमेशन फील्ड में इनकी खूब डिमांड है. वहीं, पिछले कुछ सालों में फिल्मों में भी ग्राफिक डिजाइनर्स की मांग बढ़ी है. एनिमेशन और डॉक्युमेंट्री फिल्मों में ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. अगर पिछले कुछ सालों की फिल्मों पर नजर डालें, तो अवतार, टर्मिनेटर, कृष जैसी फिल्में अपने ग्राफिक्स के कारण ही पॉपुलर हुईं. ग्राफिक के जरिए इनमें स्पेशल इफेक्ट का खूब यूज किया गया. इसके अलावा विज्ञापनों में भी ग्राफिक डिजाइनर का खूब यूज किया जा रहा है.

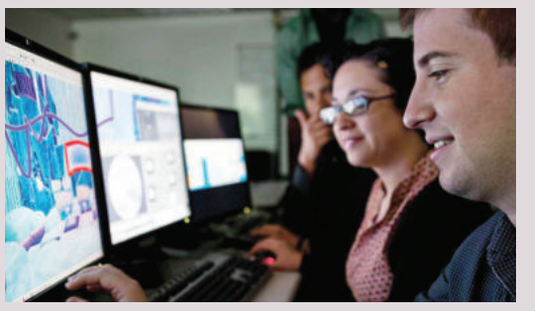

पैकेज

शुरू में इस फील्ड में 15 से 30 हजार रुपये आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन बाद में एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी सैलरी एक–डेढ़ लाख तक पहुंच जाएगी.

सिलेबस

ग्राफिक डिजाइनिंग के सिलेबस में कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, थ्री डी, क्वॉर्क वगैरह के अलावा कई सॉफ्टवेयर भी सिखाए जाते हैं. साथ ही डिजिटल, ऑडियो–वीडियो प्रॉडक्शन के अलावा ग्राफिक से जुड़ी कई टेक्निकल चीजें भी सीखाई जाती हैं.

कहां से करें कोर्स

– माया एकेडमी ऑफ अडवांस सिनेमेटिक्स (मैक) मुंबई
www.maacindia.com
– एरीना एनिमेशन, नोयडा
www.arena-multimedia.com
–नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन
www.nid.edu/

साल 1969 के बाद यह पहला मौका है जब मिश्रित युगल वर्ग में किसी एक जोड़ी ने एक साल में तीन ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं. महिला एकल वर्ग में इटली की फ्लाविया पैनेटा ने हमवतन रॉबर्टा विंची को 7-6(4),6-2 के अंतर से सीधे सेटों में हराकर 49 वें प्रयास में करियर का पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता. 33 वर्षीय पैनेटा ने इसके तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया. वहीं पुरुषों के एकल फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्विटजरलैड के रोजर फेडरर को 6-4,5-7,6-4,6-4 के अंतर से हराकर साल का तीसरा और करियर का 10वां ग्रैंडस्लैम खिताब अपने नाम किया.

यूएस ओपन

भारत की दोहरी सफलता

**लिएंडर पेस और मार्टीना हिंगिस की जोड़ी ने मिक्सड डबल्स के खिताबी मुक़ाबले में अमेरिका के बेथानी मैंटेक सैंड्स और सैम क्वेरी की जोड़ी को तीन सेटों तक चले मुक़ाबले में 6-4, 3-6 और 10-7 के अंतर से मात दी. यह इस जोड़ी का इस साल का तीसरा ग्रैंडस्लैम खिताब है. इस जीत के साथ ही पेस यूएस ओपन में मिश्रित युगल का खिताब सर्वाधिक बार जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. लिएंडर पेस के करियर का यह 17 वां ग्रैंडस्लैम खिताब है. इस जीत के साथ ही इस इंडो-स्विस जोड़ी ने एक नया इतिहास भी रच दिया है. साल 1969 के बाद यह पहला मौका है जब मिश्रित युगल वर्ग में किसी एक जोड़ी ने एक साल में तीन ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं. महिला एकल वर्ग में इटली की फ्लाविया पैनेटा ने हमवतन रॉबर्टा विंची को 7-6(4),6-2 के अंतर से सीधे सेटों में हराकर अपने 49वें प्रयास में करियर का पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता. 33 वर्षीय पैनेटा जीते के तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया. वहीं पुरुषों के एकल फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्विटजरलैंड के रोजर फेडरर को 6-4,5-7,6-4,6-4 के अंतर से हराकर साल का तीसरा और करियर का 10वां ग्रैंडस्लैम खिताब अपने नाम किया. फेडरर ने आखिरी बार साल 2012 में विबंल्डन के रूप में कोई ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था, इस बार भी वह जीत से महरूम रह गये. यदि 34 वर्षीय फेडरर 45 साल में यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाते. ■

साल के आखिरी ग्रैंडस्लैम यूएस ओपन से भारत के लिए अच्छी खबरें आईं. भारत की सानिया मिर्ज़ा और लिएंडर पेस अपनी जोड़ीदार स्विटजरलैंड की मार्टीना हिंगिस के साथ महिला युगल और मिक्स डबल्स का खिताब जीतने में सफल रही. सानिया-हिंगिस की जोड़ी ने महिला युगल के फाइनल मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलिया की केसी डेलाक्वा और कज़ाखिस्तान की यारोस्लावा श्वोदोवा की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से हराकर ख़िताब अपने नाम किया. यह सानिया के करियर का पांचवा ग्रैंड स्लैम ख़िताब है. इसके साथ ही यह इन दोनों की जोड़ी का लगातार दूसरा ग्रैंडस्लैम खिताब है. इससे पहले इन दोनों ने इस साल के विंबल्डन विमेंस डबल्स का ख़िताब भी अपने नाम किया था. दूसरी तरफ लिएंडर पेस और हिंगिस की जोड़ी ने मिक्सड डबल्स के ख़िताबी मुक़ाबले में अमेरिका के बेथानी मैंटेक सैंड्स और सैम क्वेरी की जोड़ी को तीन सेटों तक चले फाइनल मुक़ाबले में 6-4, 3-6 और 10-7 के अंतर से मात दी. यह इस जोड़ी का इस साल का तीसरा ग्रैंडस्लैम खिताब है. इस जीत के साथ ही पेस यूएस ओपन में मिश्रित युगल का खिताब सर्वाधिक बार जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. लिएंडर पेस के करियर का यह 17 वां ग्रैंडस्लैम खिताब है. इस जीत के साथ ही इस इंडो-स्विस जोड़ी ने एक नया इतिहास भी रच

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भुला न पाएंगे...

पूर्व भारतीय क्रिकेटर माधव मंत्री

मुंबई की ओर से खेलने वाले माधव मंत्री ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में 95 मैच खेले और 33.86 की औसत से 4402 रन बनाये. जबकि बतौर विकेटकीपर 136 कैच और 56 स्टम्प किये. 1950 के दशक में मुंबई ने तीन रणजी खिताब जीते. वह उस टीम के सदस्य थे.

माधव कृष्णाजी मंत्री भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज थे. साल 1921 में जन्में माधव मंत्री ने साल 1951 से 1955 के बीच भारतीय टीम की ओर से चार टेस्ट मैच खेले. विकेटकीपिंग के साथ-साथ वह ओपनिंग बल्लेबाजी भी करते थे. उन्होंने 1951 में विजय हजारे की कप्तानी में टेस्ट पदार्पण किया था. उन्होंने अपना पहला मैच निजेल हॉवड्र्स की एमसीसी टीम के खिलाफ मुंबई के ब्राबॉर्न स्टेडियम में खेला था. उन्होंने अपने करियर का आखिरी टेस्ट साल 1955 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. 4 टेस्ट मैचों में वह महज 67 रन बना सके. मुंबई की ओर से खेलने वाले माधव मंत्री ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में 95 मैचों खेले और 33.86 की औसत से 4402 रन बनाये. जबकि बतौर विकेटकीपर उन्होंने 136 कैच और 56 स्टम्प किये. 1950 के दशक में मुंबई ने तीन रणजी खिताब जीते.वह इस टीम के सदस्य थे. उन्होंने उस दौर के युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया. उनसे जुड़ी सबसे खास बात यह है कि वह भारत के सर्वकालिक महानतम ओपनिंग बल्लेबाज सुनील गावस्कर के मामा थे. वह जीवनभर अविवाहित रहे. क्रिकेट करियर को अलविदा कहने के बाद वह खेल प्रशासन से जुड़े और बतौर कोच, सेलेक्टर, मैनेजर अपनी सेवायें दीं. अस्सी के दशक के आखिर में वह मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी बने. साल 2014 में 92 वर्ष की उम्र में उनका मुंबई में निधन हो गया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एक खेल ऐसा भी...

सगोल कांगजई

आधुनिक पोलो की तरह का घुड़सवारीयुक्त यह खेल पूर्वोत्तर के सुदूर राज्य मणिपुर का पारंपरिक खेल है. यह मणिपुर का राजकीय खेल भी है. इसे सगोल कांगजई कहा जाता है. सगोल (घोड़ा), कांगजई (बांस की बनी हॉकीनुमा स्टिक) से खेला जाने वाला खेल है. मुस्लिम शासक इसी तरह का खेल खेलते थे जिसे चौगान कहा जाता था. सगोल कांगजई मुख्य रूप से मणिपुर का खेल है इसे मणिपुरी पोलो के नाम से भी जाना जाता है. अंग्रेजों ने यह खेल पूर्वी भारत के चाय बागान-वासियों से सीखा और बाद में उसके अलग नियम बनाकर 19वीं शताब्दी में इसे पोलो के नाम से यूरोपीय देशों में प्रचारित किया. इस खेल में दोनों टीमों में सात-सात खिलाड़ी होते है. जो घुटने तक धोती पहनकर घुड़सवारी करते हुए गेंद को गोल तक पहुंचाते हैं. सभी खिलाड़ी सिर पर पगड़ी पहनते हैं साथ ही जूतेनुमा गार्ड पैर पर पहनते हैं. खेल में जिस स्टिक का उपयोग होता है उसकी लंबाई 4.5 फुट होती है. इस खेल की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती है. कई बार खेल दूसरे दिन तक जारी रहता है. खेल में खिलाड़ियों को बदलने का कोई नियम नहीं होता है. आम तौर पर मणिपुरी पोलो (कांगजई)अक्टूबर से जून महीने के बीच खेला जाता है. ■

चीन करेगा एशियाई खेल-2022 की मेज़बानी

एक बार फिर चीन एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा. साल 2022 में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चीन के शहर हांग्जू को चुना गया है. तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबत में आयोजित बैठक में 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी चीन को सौंपी गई. इससे पहले साल 2010 मे चीन के शहर ग्वांग्जू ने एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था. इस बार मेजबानी की दौड़ में चीन अकेला देश था. चीन इससे पहले ओलंपिक, एशियन गेम्स और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है. इस सभी के सफल आयोजन से सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ चुका है. एक बार फिर एशियाई खेलों की मेजबानी हासिल करने को चीन की एक और बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है. साल 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन चीन में होना है, इस तरह वह एक ही साल में दो बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा. चीन के पूर्व में स्थित हांग्जू को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है. हर साल यहां हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं. खेल आयोजनों की वजह से बढ़ रहे प्रदूषण और कई अन्य मामलों की वजह से चीन को अपने ही देश में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है, बावजूद इसके इसे खेलों के सफल आयोजन के लिए अबतक तारीफ मिलती रही है.■

मनप्रीत को मिला ओलंपिक का टिकट

कोलकाता में आयोजित हुई राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 55 वें संस्करण में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करते हुए महिला शॉटपुट खिलाड़ी मनप्रीत कौर ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया. मनप्रीत ने 17.96 मीटर दूरी तक गोला फेंकते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया. उन्होंने साल 1997 में हरबंश कौर द्वारा स्थापित 17.43 मीटर के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद मनप्रीत ने कहा कि मेरे दिमाग में ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने का लक्ष्य था, इसलिए मैं बेहतर प्रदर्शन करना चाहती थी. उन्होंने कहा कि 17.96 मीटर की दूरी कोई बड़ी बात नहीं है. मैं इससे बेहतर कर सकती हूं. मैंने अभ्यास के दौरान 18.60 मीटर की दूरी भी हासिल की है. अब मेरा अगला लक्ष्य 19 मीटर के नजदीक पहुंचना है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनप्रीत ने आखिरी बार राष्ट्रमंडल खेल-2010 में हिस्सा लिया था. इसके अलावा पिछली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था. पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल अकादमी (एनआईएस) में प्रशिक्षण ले रहीं मनप्रीत ने कहा कि वह और अधिक मेहनत करेंगी और रियो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी. ■

ज्वाला-अश्विनी की जोड़ी टॉप्स में शामिल

ग्लास्गो कॉमनवेल्थ खेल में रजत पदक जीतने वाली ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को लंबे विवाद के बाद आखिरकार भारत सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम(टॉप्स) में शामिल कर लिया गया है. अब इन दोनों खिलाड़ियों को भी 2016 रियो ओलिंपिक की तैयारी के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलेगी. इसके साथ ही उन विवादों पर भी विराम लग गया जो ज्वाला-अश्विनी द्वारा मंत्रालय और कोच पुलेला गोपीचंद के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाने के बाद शुरू हुआ था. ज्वाला और अश्विनी के अलावा सुमित रेड्डी और मनु अत्री की भारतीय पुरुष डबल्स बैडमिंटन जोड़ी को भी इस स्कीम का हिस्सा बनाया गया है. खेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा, पोनप्पा, रेड्डी और अत्री को टॉप्स स्कीम में शामिल कर लिया गया है. सायना नेहवाल, पीवी सिंधु, पी. कश्यप, कादंबी श्रीकांत, गुरुसाई दत्त और एचएस प्रणय को पहले ही टॉप्स में शामिल किया जा चुका है. अब इस स्कीम के तहत शामिल बैडमिंटन खिलाड़ियों की संख्या 11 हो गई है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कॉमेडी की जान रज़्ज़ाक़ ख़ान

हंसना बेहद आसान है लेकिन लोगों को हंसाना बेहद कठिन, लेकिन कुछ लोग हंसाने की कला में माहिर होते हैं, ऐसे ही एक हास्य अभिनेता हैं रज़्ज़ाक़ ख़ान. रज़्ज़ाक़ खान अपनी टपोरी की भूमिका और डॉयलाग डिलिवरी के लिए पहचाने जाते हैं, कुछ ऐसे ही अंदाज में वह एक बार फिर फिल्म *होगया दिमाग़ का दही* में नज़र आयेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो

हंसी–मज़ाक के बिना ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है. हंसी–मज़ाक ही जीवन में आई बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है. हंसना बेहद आसान है लेकिन लोगों को हंसाना बेहद कठिन, लेकिन कुछ लोग हंसाने की कला में माहिर होते हैं, ऐसे ही एक हास्य अभिनेता हैं रज़्ज़ाक़ ख़ान. टपोरी की भूमिका और डॉयलाग डिलिवरी के अनोखे अंदाज की वजह से उन्की फिल्म जगत में एक अलग पहचान है. कुछ ऐसे ही अंदाज में वह एक बार फिर फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** में नज़र आयेंगे. इस फिल्म में उनके किरदार का नाम तीली भाई है. उनका कॉमेडी का अंदाज लोगों को सिनेमाघर तक आने के लिए मजबूर कर देता है. यही उन्हें औरों से अलग खड़ा करता है. अपने फिल्मी करियर में रज़्ज़ाक़ तकरीबन 100 फिल्मों मे काम कर चुके हैं. उन्होंने रूप की रानी–चोरों का राजा, हम हैं कमाल के, दिल तेरा आशिक, मोहरा, हम दोनों, सनम, लोहा, कोयला, इश्क, गुलाम, बादशाह, बड़े मियां–छोटे मियां, हसीना मान जाएगी, क्या कूल हैं हम, नो एंट्री, फिर हेरा–फेरी, जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.

बचपन से ही उनका रुझान अभिनय की ओर था, वह अभिनेता बनना चाहते थे. अगर आज दर्शक उन्हें जानते हैं और

अपने फिल्मी करियर में रज़्ज़ाक़ तकरीबन 100 फिल्मों मे काम कर चुके हैं. उन्होंने रूप की रानी-चोरों का राजा, हम हैं कमाल के, दिल तेरा आशिक, मोहरा, हम दोनों, सनम, लोहा, कोयला, इश्क, गुलाम, बादशाह, बड़े मियां-छोटे मियां, हसीना मान जाएगी, क्या कूल हैं हम, नो एंट्री, फिर हेरा-फेरी, जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. बचपन से ही उनका रुझान अभिनय की ओर था, वह अभिनेता बनना चाहते थे. अगर आज दर्शक उन्हें जानते हैं, पसंद करते हैं तो उनके अलग अंदाज, हाव-भाव और बेहतरीन अभिनय की वजह से.

पसंद करते हैं तो उनके अलग अंदाज, हाव–भाव और बेहतरीन अभिनय की वजह से. फिल्म ***होगया दिमाग का दही*** में वह बॉलीवुड के कॉमेडी के बादशाह क़ादर खान, ओमपुरी, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, विजय पाटकर और सुभाष यादव जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ कॉमेडी की जुगलबंदी करते दिखाई

देंगे. फिल्म *होगया दिमाग़ का दही* में अपने रोल के बारे में रज्जाक खान कहते हैं कि उन्हें नए निर्देशक पर बहुत भरोसा है. युवा फिल्मकार फौजिया अर्शी ने बड़ी मजेदार फिल्म बनाई है. यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ दर्शकों को हंसाने के लिए बनी है. आज जीवन में हम हंसना भूल गए हैं. यह फिल्म लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर देगी. अब तक यू–ट्यूब पर फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** का ट्रेलर लाखों लोग देख चुके हैं और तीली भाई से रू–ब–रू होने की तैयारी कर रहे हैं.■

कार्टून बने मीका

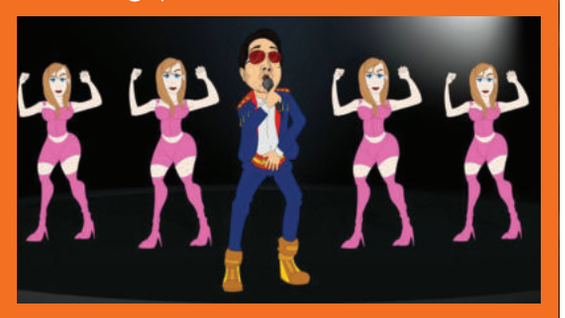

मीका सिंह देश के पहले गायक बन गए हैं जिनका एनिमेटेड अवतार किसी फिल्म के गीत में नज़र आयेगा. फ़ौज़िया अर्शी केनिर्देशन में बनी फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** का गीत ***बाप होना पाप...*** मीका सिंह के कार्टून के साथ फिल्माया गया है. फिल्म की निर्देशक और संगीतकार फ़ौज़िया अर्शी बताती हैं कि इस गाने को एनिमेटेड रूप देना संयोग की ही बात है. जब हम बाप होना पाप... गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तब से ही मेरी इच्छा थी कि इस गाने शूटिंग मीका को मुख्य भूमिका में रखकर करूं, लेकिन इसी दौरान जब उन्हें अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों न इस गाने को ऐनिमेटेड रुप दिया जाये और मीका को एनीमेटेड अवतार में पेश कर उन्हें ही आश्चर्यचकित किया जाये. इसके बाद फ़ौज़िया अर्शी बताती हैं कि मीका ने जब पहली बार अपने कार्टून अवतार को देखा तो वह हैरान और चकित रह गये. उन्हें अपने कार्टून से प्यार हो गया. इसके बाद एकमत से इसे फिल्म में रखने का निर्णय किया गया. हिन्दी सिनेमा का यह पहला गीत है,जिसमें गायक को एनिमेटेड रूप में दर्शाया गया है. मीका सिंह अपने हर गीत में मस्ती में झूमते–गाते नज़र आते है. इस गाने में मीका सिंह का कार्टून फिल्म के कलाकारों के कार्टून्स के साथ नाचते–गाते दिखाई देंगे. यह फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज होगी.■

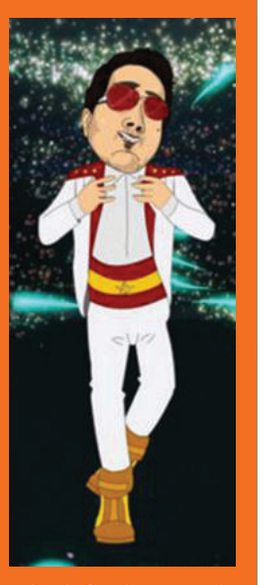

बाघा-बॉर्डर पर होगया दिमाग़ का दही

आजकल भारत–पाकिस्तान की सीमा पर एक नया नज़ारा दिखाई पड़ रहा है. आमतौर पर बाघा–बॉर्डर जाने वाले लोगों की उत्सुक्ता का केंद्र दोनों देशों के सैनिकों की देशभक्ति से लबरेज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है. लेकिन आजकल यहां फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** के होर्डिंग्स अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. जिस किसी की नज़र फिल्म के पोस्टर–होर्डिंग पर पड़ती है, कुछ पल के लिए उसकी नज़रें ठहर जाती हैं. कॉमेडी किंग क़ादर खान की फिल्मों में 10 साल बाद हो रही वापसी की वजह से यह फिल्म पहले से सुर्खियों में हैं. 16 अक्टूबर को ओमपुरी, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, रज्जाक खान और क़ादर ख़ान एक साथ मिलकर दर्शकों के दिमाग़ का दही करेंगे. इन सभी की जुगलबंदी दोनों देशों के लोगों को ठहाके लगाने को मजबूर कर देगी. जिससे दोनों देशों की आवाम कुछ पलों के लिए आपसी रंजिश को भूल जायेगी.■

होगया दिमाग़ का दही के गीतों की धूम

16 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही फिल्म ***होगया दिमाग का दही*** के गीत मुंबई में लॉन्च हुए. म्यूजिक लॉन्च होते ही यू-ट्यूब और अन्य वेबसाइट्स से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इस फिल्म केगीतों को डाउनलोड कर रहे हैं. फिल्म में पांच गीत हैं. जिनमें से मीका द्वारा गाया गीत ***बाप होना पाप...*** कैलाश खेर की रूहानी आवाज से सजा गीत ***मौला-मौला...***और फौजिया अर्शी द्वारा गाया गीत ***कभी तो सुन गौर से...***सबसे ज्यादा पसंद किये जा रहे हैं. फिल्म में संगीत निर्देशक फौजिया अर्शी ने ही दिया है, जबकि गीत शब्बीर अहमद ने लिखे हैं. फिल्म के टाइटल ट्रैक ***दिमाग़ का दही...***को कुनाल गांजावाला ने अपनी आवाज दी है. कुल मिलाकर फिल्म के सभी गीत अच्छे हैं और अलग-अलग मूड के हैं. इस वजह से हर वर्ग और उम्र के लोग इस फिल्म के गीतों को पसंद कर रहे हैं.■

सवाल नंबर–3

फिल्म हो गया दिमाग़ का दही की स्क्रिप्ट किसने लिखी है?

A. संतोष भारतीय
B. फौजिया अर्शी
C. ओमपुरी
D. संजय मिश्रा

अपना जवाब मेल आईडी dailymultimedia1@gmail.com पर मेल करें सबजेक्ट Hogaya Dimaagh Ka Dahi QUIZTHREE (ऑप्शन A/B/C/D) शहर का नाम लिखें या मोबाइल नंबर पर **072104-38230** QUIZTHREE(स्पेस) (ऑप्शन A/B/C/D) जवाब मैसेज करें.

नोट

1. पुरस्कार दो लकी विजेताओं को मिलेगा.
2. दो से ज्यादा सही जबाब मिलने पर विजेता का फैसला लकी ड्रॉ द्वारा निकाला जायेगा.
3. फिल्म का टिकट आपके नजदीकी पीवीआर/ फन सिनेमा का दिया जाएगा.
4. आपके जवाब हमें 04 अक्टूबर,2015 को रात 12 बजे से पहले मिल जाने चाहिए.

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

28 सितंबर–04 अक्टूबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

आर्थिक विकास की दौड़ में शामिल होने से क्यों कतरा रहा है यूपी!

लापरवाही के चलते भागीदारी से वंचित

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आर्थिक विकास के ग्रोथ-इंजन के रूप में काम करने वाले आईटी सेक्टर की विशाल संभावनाओं के प्रति उत्तर भारतीय राज्य और खास कर उत्तर प्रदेश आंख मूंदे हुए है.

अजेय सिंह
रिजनल हेड, सीएमसी लिमिटेड (टाटा समूह)

लखनऊ में आईटी हब और आईटी सिटी की स्थापना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बात तो खूब बना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खूब शोर-शराबे के साथ आईटी सिटी का शिलान्यास भी किया था. उसमें आईटी नीति, बायो-टेक्नोलॉजी नीति, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण संबंधी नीतियों की घोषणा करते हुए उद्योगपतियों और नव-उद्योगपतियों के फायदे की तमाम आकर्षक योजनाओं का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ये सारी घोषणाएं और वायदे मंचीय और कागजी ही साबित हुए. सालभर से अधिक होने को आया, लेकिन आईटी सिटी की योजना कुछ भी ठोस स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकी. सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आईटी और बीपीओ कंपनियां उत्साहित होकर लखनऊ आएं और अपनी इकाइयां स्थापित करें.

सरकार यह भी अच्छी तरह जानती है कि आईसीटी-आईटी-बीपीओ इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश की भीषण बेरोजगारी की समस्या को बहुत हद तक हल कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की अनदेखी आश्चर्यजनक और दुखद है. भारत के आर्थिक विकास में और देश की बेरोजगारी की समस्या को कम करने में आईटी-बीपीओ उद्योग का कितना योगदान और श्रेय है, यह सब जानते हैं. देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.2 फीसदी हिस्सा आईटी-बीपीओ उद्योग से आता है. तेल आयात से होने वाली आय का यह तकरीबन आधा है. पिछले 10 वर्षों से आईटी-बीपीओ उद्योग 20-25 प्रतिशत सालाना की दर से विकसित हो रहा है. जिस गति से वैश्विक तकनीक और अवसर बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से वित्तीय वर्ष 2014-15 में देश का विकास दर बढ़ने वाला है. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नासकॉम) को उम्मीद है कि आईटी-बीपीओ क्षेत्र से निर्यात आय में 84 से 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बढ़ोत्तरी होगी और 12 से 14 प्रतिशत का विकास दर बना रहेगा. घरेलू राजस्व भी 13 से 15 फीसदी की दर से बढ़ कर 1180 से 1200 बिलियन (भारतीय मुद्रा में) पहुंचने की संभावना है. आईटी-बीपीओ क्षेत्र में देश में तकरीबन 15 हजार फर्म्स हैं, जिसमें 11 बड़ी कंपनियां 40 प्रतिशत राजस्व दे रही हैं. मध्य आकार की करीब डेढ़ सौ फर्में मिल कर आईटी इंडस्ट्री के राजस्व में 35 से 40 प्रतिशत तक योगदान करती हैं. आईटी-बीपीओ क्षेत्र देश का ऐसा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर नियोक्ता है जो तीन मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है. यह चौथा बड़ा सेक्टर है जो एक मिलियन से अधिक शहरी महिलाओं को रोजगार दे रहा है.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा के होते हुए भी उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ी आईटी-बीपीओ कंपनी अपना केंद्र नहीं बना पाई. यहां तक कि मझोले दर्जे की आईटी कंपनियां भी नोएडा में डेवपलमेंट सेंटर्स नहीं खोल पाईं. जबकि आईटी-बीपीओ सेक्टर देश की विभिन्न 99 आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) के जरिए विकास का क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहा है और अपने व्यवसायिक प्रबंधन से देश के राजस्व में 175 से 196 बिलियन (भारतीय मुद्रा में) का योगदान दे रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बिल्कुल पिछड़ा है. आईटी-बीपीओ सेक्टर उत्तर प्रदेश के विकसित शहरों में भी प्रवेश नहीं कर पाया है और आगामी 10 साल तक कोई ऐसी योजना भी नहीं दिखती. यह उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. उत्तर प्रदेश सरकार को कदाचित यह समझ में नहीं आ रहा कि आईटी-बीपीओ सेक्टर देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख उत्प्रेरक तत्व बन चुका है और इसका बेहतर उपयोग उत्तर प्रदेश और बिहार को गरीबी और पिछड़ेपन से उबारने के लिए हो सकता है, लेकिन इस तरफ सरकार की कोई गंभीरता ही नहीं दिख रही. नौकरशाही की कृपा से देश में मंथर गति से चलने वाले आर्थिक विकास को तीव्र गति देने और देश का आर्थिक स्वरूप बदल डालने में आईटी सेक्टर का महत्वपूर्ण रोल है. इसने पूरी दुनिया में भारत की छवि बदली है और अब भारतवर्ष को प्रयोगधर्मी उद्योगपतियों की उर्वर भूमि के रूप में देखा जा रहा है. जिसने भारत के कृषि आधारित ग्रामीण-अर्थ वाली छवि को बदल कर ज्ञान और सूचना आधारित अर्थ के रूप में विकसित करने वाले देश के रूप में पहचान दी है. आईटी-बीपीओ सेक्टर ने लोगों का जीवनस्तर बढ़ाया है और विभिन्न किस्म के रोजगार के रास्ते खोले हैं.

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आर्थिक विकास के ग्रोथ-इंजन के रूप में काम करने वाले आईटी सेक्टर की विशाल संभावनाओं के प्रति उत्तर भारतीय राज्य और खास कर उत्तर प्रदेश आंख मूंदे हुए है.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

अखिलेश से मिले नाडर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए लखनऊ में आईटी सिटी की परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है. इसके जरिए राज्य के नौजवानों को बड़ी संख्या में नौकरी मिलने के साथ-साथ रोजगारपरक प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी और दूसरी ओर व्यापक स्तर पर निवेश भी होगा. इसलिए राज्य सरकार आईटी सिटी परियोजना जल्द से जल्द पूरा कराना चाहती है. अखिलेश ने पिछले दिनों एचसीएल कम्पनी के संस्थापक तथा शिव नाडर फाउन्डेशन के अध्यक्ष शिव नाडर से भेंट की. आईटी सिटी परियोजना का क्रियान्वयन एचसीएल द्वारा किया जा रहा है. शिव नाडर ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए स्पेशल प्री-फैब तकनीक का उपयोग करके एचसीएल अक्टूबर, 2016 तक आईटी सिटी की शुरुआत कर देगा. पहले चरण में लगभग एक हजार लोगों को परियोजना के जरिए रोजगार प्राप्त होगा. परियोजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कम्पनी द्वारा शिव नाडर फाउन्डेशन के माध्यम से हरदोई जनपद के चयनित गांवों में संचालित प्रोजेक्ट समुदाय' के बारे में शिव नाडर ने बताया कि इन गांवों के समग्र विकास के लिए कार्य किया जा रहा है. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, स्वच्छ पेयजल तथा बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया जा रहा है. इन पांच मुख्य मानकों के लिए कार्य सूची तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा, मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक ग्रामीणों की पहुंच, सभी परिवारों को बिजली और शौचालय उपलब्ध कराना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था तथा ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण शामिल हैं. प्रत्येक गांव की जरूरत को ध्यान में रखकर विकास सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

मेक इन इंडिया की तर्ज पर अखिलेश का नारा मेक इन यूपी

अब दो साल में क्या होगा चमत्कार!

उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि व्यवसाय एवं उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप मुंबई और महाराष्ट्र के उद्योगजगत से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है.

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश सरकार के सियासी अलमबरदार राजनीतिक जरूरतों के कारण भाजपा की नीतियों की आलोचना भले ही करते हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्तों का अनुकरण करने में अखिलेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है. स्वच्छता का मसला हो या नदी की सफाई का या फिर पूंजी निवेश की कवायद का, केंद्र सरकार आगे-आगे तो यूपी सरकार पीछे-पीछे. मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेक इन यूपी का नारा उछाल दिया. सामाजिक-आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूंजी निवेश या स्वच्छता के प्रयास सकारात्मक कदम हैं. अब लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जो निवेश तीन वर्ष में नहीं हो सका, वह चमत्कार की तरह अब दो साल में ही कैसे हो जाएगा!

वैसे उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि व्यवसाय एवं उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप मुंबई और महाराष्ट्र के उद्योगजगत से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है. राज्य की निवेश नीतियों एवं औद्योगिक अवस्थापना में विश्वास व्यक्त करते हुए उद्यमियों ने विभिन्न सेक्टरों में प्रदेश में 51098 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है.

इस संबंध में निवेशकों ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पिछले दिनों मुंबई के ट्राइडेंट होटल में आयोजित निवेशक सम्मेलन में इंटेंट फॉर कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए. जिन कंपनियों ने राज्य में निवेश करने के लिए प्रस्ताव दिया है, उनमें प्रमुख रूप से आइडिया सेल्युलर, एलजी, रिलायंस जियो, गोदरेज एग्रोवेट, तोशिबा पावर, सेसा वायो सिस्टम, कंसोरिया पेपर, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, आईटीसी, इंडो-गल्फ फर्टिलाइज़र्स, अमूल संचय आदि प्रमुख हैं. प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, अवस्थापना विकास, आईटी, ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि सेक्टरों में निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया.

लगभग दो सौ भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों व कई बिज़नेस समूहों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मेक इन इंडिया तभी सफल हो पाएगा जब मेक इन यूपी सफल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश न केवल देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा बाज़ार भी है. राज्य की निवेश नीतियां, अच्छे यातायात के साधन, बढ़ती हुई ऊर्जा क्षमता और अन्य सामाजिक सेवाएं निश्चित रूप से दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बेहतर हैं. मेरी सरकार यूपी को प्रगतिशील और समृद्ध बनाने के लिए कृतसंकल्प है और इसलिए कई नई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गई हैं. सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक अवस्थापना विकास के लिए सरकार आईटी पार्क, मेगा फूड पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, प्लास्टिक सिटी, बायोटेक औद्योगिक पार्क एवं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित कर रही है. आगरा से लखनऊ के बीच विकसित किए जा रहे 302 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे के लिए बिना किसी बाधा के भूमि का प्रबंध किए जाने का ज़िक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हमने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए ज़मीन के मालिकों की सहमति से पूरी ज़मीन का इंतज़ाम बिना किसी विवाद के कर दिखाया. इसमें 10 जिलों में कुल 3059 हेक्टेयर ज़मीन का इंतजाम किया गया. हम लखनऊ में विश्व-स्तरीय, सुरक्षित, त्वरित व सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए करीब 12,000 करोड़ की लागत वाली मेट्रो रेल की स्थापना कर रहे हैं. इस पर तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि यह अगले वर्ष 2016 के अंत तक चलने भी लगेगी. इसके अलावा प्रदेश के चार अन्य नगरों-इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर व वाराणसी में भी मेट्रो रेल विकसित करने की योजना है. राज्य सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और लखनऊ में साइकिल ट्रैक्स बना रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्थानीय परिवहन के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें ताकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम किया जा सके. सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण एवं पारम्परिक उद्योगों के विकास पर जोर दिया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में किसान मंडियों का घनत्व बढ़ाने के उद्देश्य से हर 100 किमी पर एक मंडी परिसर की स्थापना के लिए 1651 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब के निर्माण हेतु 466.53 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और सात जिलों में किसान बाज़ार स्थापित की योजना पर काम चल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक व उद्यमियों के लिए यूपी के दरवाजे खुले हैं.

मुंबई गए प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा, मुख्य सचिव आलोक रंजन, सूचना विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव महेश कुमार गुप्ता समेत कई लोग शामिल थे.

उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर मुंबई में हुए निवेशक सम्मेलन में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन नादिर गोदरेज, किंगडम इन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी अभिनेता संजय खान, जैक्सन पावर के सीएमडी समीर गुप्ता, अमूल के प्रबन्ध निदेशक आरएस सोढी, फिल्म निर्देशक बोनी कपूर, मुजफ्फर अली, अभिनेता मनोज बाजपेई, केतन मेहता, दिव्या दत्ता, पूजा भट्ट, अनुराग कश्यप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जाएद खान तथा राहुल मित्रा के अतिरिक्त कई अन्य हस्तियां मौजूद थीं. सम्मेलन के बाद प्रमुख बैंकरों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की. इनमें एसबीआई, ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह के प्रतिनिधि अधिकारी मौजूद थे. बैंकरों ने भी उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ रुपये की लेंडिंग तथा निवेश का वादा किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को मुंबई में आयोजित 'इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव' में शीर्ष बैंकर्स के साथ विचार-विमर्श करते हुए.

फिल्म नहीं भूलते अखिलेश

इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव के दौरान ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फिल्म बंधु द्वारा विकसित फिल्म निर्माण संबंधी सभी क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम तथा अनुदान हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के शुरू होने से अब फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में फिल्मों के निर्माण में अत्यन्त आसानी होगी और उन्हें छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा. इस पोर्टल के माध्यम से अब फिल्म निर्माता शूटिंग सहित अन्य क्लियरेंस के लिए अपने स्थान से आवेदन कर सकते हैं. अब फिल्म निर्माण के लिए शूटिंग से संबंधित सभी क्लियरेंस निश्चित समयावधि में प्राप्त हो जाएंगी. इससे प्रदेश में फिल्म निर्माण के कार्य में निश्चित रूप से तेजी आएगी.

कार्यक्रम के दौरान फिल्म उद्योग से जुड़े प्रमुख लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म नीति तथा सरकार द्वारा फिल्म निर्माण के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जिक्र किया. फिल्म निर्माता संजय खान ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण अत्यन्त आसान एवं सुविधाजनक हो गया है और यहां के अधिकारीगण तत्परता से हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं. फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. उत्तर प्रदेश में की गई शूटिंग का अनुभव उन्हें बहुत ही अच्छा लगा. फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने भी फिल्म निर्माताओं को आगे बढ़कर मदद करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की. उन्होंने कहा कि फिल्म बन्धु फिल्म निर्माताओं के लिए एक अत्यन्त फ्रेंडली संस्था के रूप में उभर कर सामने आई है. ■

लापरवाही के चलते भागीदारी से वंचित

पृष्ठ 17 का शेष

उत्तर भारत के राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन तेजी से गहराता जा रहा है. भारत की 40 प्रतिशत आबादी उत्तर भारत में रहती है, लेकिन विडंबना है कि इसके बावजूद यहां की युवा आबादी का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा. जबकि आईसीटी-आईटी-बीपीओ सेक्टर में इस आबादी का भरपूर इस्तेमाल हो सकता था. दक्षिण के कुछ राज्यों को आईटी-बीपीओ सेक्टर का फायदा काफी पहले समझ में आ गया था. उन्होंने समय रहते इस सेक्टर के उद्योगपतियों को अपने राज्य में स्वागत करके बुला लिया. आप देख सकते हैं, उन राज्यों में रोजगार और आर्थिक विकास किस तेजी से बढ़ा. पहले तो यह उन राज्यों की राजधानियों में स्थापित हुआ और धीरे-धीरे उन राज्यों के अन्य शहरों में भी विस्तार लेने लगा. इससे ग्रामीण इलाकों की भी बेरोजगारी की समस्या हल होने लगी. कम पढ़े-लिखे और सेमी-स्किल्ड युवकों को भी नौकरियां मिलने लगीं. दक्षिण के उन राज्यों में राजधानी से लेकर छोटे-छोटे शहरों तक आईटी-बीपीओ सेक्टर के विस्तार के कारण बेहतरीन ढांचागत विकास शक्ल ले चुका है. इसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अदूरदर्शिता के कारण काफी देर कर दी.

नब्बे के दशक में नोएडा भी आईटी-बीपीओ हब के रूप में विकसित हो रहा था. आईटी उद्योग के लिए नोएडा आकर्षण का केंद्र भी बन रहा था, लेकिन कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरू को सिलिकॉन सिटी के रूप में इस तरह विकसित किया कि सारी प्रतिष्ठित कंपनियां उसी तरफ चली गईं. इसके लिए कर्नाटक सरकार ने टैक्स से लेकर जमीन तक में सब्सिडी दी, एकल खिड़की व्यवस्था को सुचारू कर लालफीताशाही का फंदा हटाया, अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराईं और कानून व्यवस्था की पुख्ता गारंटी दी. आईटी-बीपीओ उद्योग सेक्टर को आमंत्रित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने अमेरिका के विभिन्न शहरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए और प्रमुख कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया. बाद में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कर्नाटक का अनुकरण किया और इसी तरह हैदराबाद और सिकंदराबाद को सिलिकॉन सिटी के रूप में विकसित किया. दक्षिण में आईटी सिटी का विकास इतना हो गया कि अमेरिकी आर्थिक मंदी के दौर में कई अमेरिकी कंपनियों ने यहां पर अपने आईटी-बीपीओ के डेवपलमेंट सेंटर्स स्थापित किए. अब उत्तर प्रदेश में सूचना संस्थान और सूचना-क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बारे में भी जायजा लेते चलें. केंद्रीय, प्रदेशीय, निजी और डीम्ड मिला कर उत्तर प्रदेश में 57 विश्वविद्यालय हैं. इनके तहत 3104 कॉलेज हैं, आईटी के 15 सौ संस्थान, 197 व्यवसायिक शिक्षा-संस्थान और 320 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं. उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर, एचआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी इलाहाबाद, आईएमटी गाजियाबाद,

सी-डीएसी नोएडा, आईटी-बीएचयू जैसे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के कई विश्व स्तरीय संस्थान हैं. उत्तर प्रदेश में हर साल बीएससी में 0.28 मिलियन छात्रों का एडमिशन होता है. इंजीनियरिंग में यूपी में 96 हजार बच्चे सालाना एडमिशन लेते हैं.

देश में सबसे अधिक कॉलेजों वाले प्रदेश में यूपी का स्थान तीसरा है और आईटीआई/आईटीसी शिक्षण संस्थाओं में यूपी का दूसरा स्थान है. बिजनेस स्कूलों में भी उत्तर प्रदेश का स्थान देश में तीसरा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में चौथा स्थान है. पॉलिटेक्निक संस्थानों में उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे देश में प्रथम है. उत्तर प्रदेश कुशल मानव संसाधन (स्किल्ड मैन पावर) देने में भी अव्वल है, लेकिन सरकारी अदूरदर्शिता के कारण इस प्रदेश से निकलने वाली अधिकांश योग्यताओं का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता और उन्हें दक्षिण के राज्यों में विस्थापित होने पर विवश होना पड़ रहा है. दक्षिण के राज्यों में 20 प्रतिशत तकनीकी योग्यता उत्तर प्रदेश और बिहार से आ रही है. ऐसे में लोगों के जेहन में यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि तकनीकी संसाधन से सम्पन्न उत्तर प्रदेश क्या अपने शहरों में आईटी-बीपीओ हबों की स्थापना नहीं कर सकता? क्या उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिणी राज्यों की तरह सुविधाएं देकर अपने यहां आईटी-बीपीओ कंपनियों को अपने उद्योग विकसित करने में मदद नहीं कर सकती?

दक्षिणी राज्यों के आईटी-बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री के समक्ष अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ का खतरा सामने आ रहा है, क्योंकि ये राज्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में काफी सस्ते में अपने काम का निस्तारण कर रहे हैं. नए राज्य अब और अधिक प्रभावी तरीके से आईटी-बीपीओ उद्योग को अपने यहां आकर्षित कर रहे हैं. यह सेक्टर एक परस्पर प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है. पुराने स्थापित केंद्रों और तेजी से उभर रहे नए केंद्रों के बीच प्रतियोगिता बढ़ रही है. उत्तर प्रदेश को इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर इसका फायदा उठाना चाहिए था, जहां का ऑपरेटिंग-कॉस्ट अपेक्षाकृत और सस्ता व तकनीकी योग्यता की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, लेकिन इसके लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली, निर्बाध कानून व्यवस्था और निर्बाध नौकरशाही-अंकुश जरूरी है, जिसे उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम है. एचसीएल, मोज़रबेयर, सैमसंग जैसी कंपनियां नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विकसित भी हुईं, तो वे यूपी के पूर्वी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र में मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना नहीं कर पाईं, जबकि वहां इसकी काफी जरूरत थी.

आईसीटी-बीपीओ सेक्टर अब केवल आईटी के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र के कई अन्य आयामों को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं. हेल्थ, मैनुफैक्चरिंग, पावर, बैंकिंग-फाइनैंस, कानून व्यवस्था, शिक्षा, रक्षा से लेकर सरकार को सेवाएं मुहैया कराने तक में आईटी-बीपीओ सेक्टर प्रभावकारी रोल अदा कर रहा है. दूरस्थ और दुर्गम इलाकों तक ब्रॉडबैंड की वजह से प्रशासनिक से लेकर शैक्षणिक स्तर तक पहुंच हो गई है. इसे केंद्रित कर सरकारी सेवाओं के व्यवहार में सुगतमा लाई जा सकती है और रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं. 2011 की जनगणना बताती है कि देश की 69 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है. यानी, देश की अधिकतम आबादी शिक्षा की पहुंच से दूर, सामाजिक गतिविधियों से दूर और असंगठित है. दिहाड़ी मजदूरों का बढ़ता बाजार भी इसी वजह से है, जिनकी आय अत्यंत कम है. सरकार की अदूरदर्शिता के कारण देश की आर्थिक प्रगति में ग्रामीण आबादी की सक्रिय भागीदारी बहुत कम हो गई है. यूपी में मैनुफैक्चरिंग उद्योग अब नहीं के बराबर हैं, लिहाजा इस आबादी का रोजगार का रास्ता बंद है. कृषि उत्पादन में किसानों की क्या स्थिति है, यह किसी से छिपी नहीं है. ग्रामीण अकुशल श्रमिक और शहरी कुशल श्रमिक की संख्या का फर्क काफी अधिक है, लेकिन अधिसंख्य अकुशल श्रमिकों का कोई समुचित इस्तेमाल नहीं है, लिहाजा देश के विकास में इस आबादी की कोई हिस्सेदारी नहीं है. इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहां की सरकारें दोषी हैं. चीन की तरह हम अपने आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में अधिक से अधिक अकुशल श्रमिकों का संसाधन झोंक कर हार्ड वेयर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं. कुशल और शिक्षित श्रम की जरूरत सॉफ्टवेयर उत्पाद में होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विशाल अकुशल मानव-संसाधन का इस्तेमाल करके हम हार्डवेयर उत्पादन क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं.

भारतवर्ष अब आईटी क्रांति के दूसरे दौर में प्रवेश कर रहा है. पिछले दो दशक में आईटी सर्विस प्रोवाइडर विकसित देशों में अपनी सेवाएं देने पर केंद्रित थे. भारतीय इंजीनियरों ने विकसित देशों में ई-गवर्नेंस और ई-एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने और ई-कॉमर्स व बीटूबी सर्विस के जरिए वहां के आर्थिक विकास को पुख्ता करने में पूरी मदद की. लेकिन भारतवर्ष के आईटी इंजीनियरों की प्रतिभा को भारत में ही तरजीह नहीं मिली, जिससे भारतवर्ष के लोगों को भी उस मेधा का फायदा नहीं मिल सका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महसूस किया है और डिजिटल भारत बनाने का उनका सपना इसी का परिणाम है. अब यह महसूस किया जाने लगा है कि चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों और शिक्षकों को दूरस्थ इलाकों में पहुंचने के लिए भौतिक रूप से जाने की जरूरत नहीं बल्कि गांव-गांव में ब्रॉडबैंड और मल्टी-सर्विस होना जरूरी है, जिसके जरिए कोई भी कहीं भी जाकर सीधे लोगों से संवाद स्थापित कर सकता है, उनके काम देख सकता है और उन्हें जरूरी सलाह दे सकता है. डिजिटल इंडिया योजना के तहत हम उत्तर प्रदेश को डिजिटल-सम्पन्न सोसाइटी और सूचना आधारित अर्थ उत्पादन करने वाला प्रदेश बना सकते हैं. डिजिटल इंडिया योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, ई-गवर्नेंस से प्रशासन को दुरुस्त करने और भारत को नॉलेज-इकोनॉमी से जोड़ने की कवायद है. इससे हम पावर सेक्टर और बैंकिंग-फिनांस सेक्टर में भी मजबूत हो पाएंगे. उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किए बगैर डिजिटल इंडिया का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता. यूपी डिजिटल हो गया तो समझें पूरे देश के डिजिटल होने में देर नहीं लगेगी. पिछले दो साल से उत्तर प्रदेश सरकार आईटी-बीपीओ की छूट चुकी बस को ही पकड़ने का बेमानी प्रहसन कर रही है. लखनऊ में एचसीएल की तरफ से आईटी सिटी विकसित किया जा रहा है. चार शहरों में आईटी पार्क्स भी विकसित किए जाने की योजना है. लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि बिना सरकार के सक्रिय सहयोग से यह लक्ष्य निर्धारित समय में कैसे पूरा हो सकता है! अभी भी समय है, उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी आईटी कंपनियों का उत्तर प्रदेश में स्वागत करे और विकास के एक बड़े कैनवस को आकार लेने का रास्ता प्रशस्त करे, लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी बेलगाम और अराजक नौकरशाही की नाक में लोहा डालना ही होगा. ■

(लेखक एसोसिएशन ऑफ नॉलेज वर्कर्स के अध्यक्ष और कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुष्टाहार योजना फेल, सरकारी दस्तावेज़ से खुलासा

कुपोषित बच्चों का प्रदेश

उत्तर प्रदेश को कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के दावे बिल्कुल ही खोखले साबित हो रहे हैं. प्रदेश में राज्य पोषण मिशन के तहत जरूरतमंद लोगों तक पौष्टिक पदार्थ पहुंचाने के अखिलेश सरकार के दावे हकीकत से बिल्कुल विपरीत हैं. सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने यह खुलासा किया कि कुपोषण के खिलाफ जंग की रफ्तार उत्तर प्रदेश में अत्यंत धीमी है.

सूफी यायावर

बच्चों के पुष्टाहार से संबंधित देश के नौ गरीब प्रदेशों के जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे खराब है. यह आधिकारिक आंकड़े हैं, जो भारत सरकार के महानिबंधक की तरफ से जारी किए गए थे. यूपी में पिछले दशक में नाममात्र की प्रगति रही. केंद्र की पूर्ववर्ती सरकार ने पहले की स्थिति जानने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों पर त्वरित सर्वे कराया. यह सर्वे सरकार और यूनिसेफ ने मिल कर 2014 में कराया था, जिसके आंकड़ों को वर्तमान केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद जारी नहीं किया. अचानक आंकड़े लीक हो गए और कुछ मीडिया संस्थानों को मिल गए. यह प्रकाशित भी हुआ.

सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि सभी प्रदेशों ने बच्चों के बौनेपन की समस्या से निजात पाने में प्रगति की है. इसके उलट सीएबी के आंकड़े बताते हैं कि केवल पांच प्रदेशों में इस पैमाने पर प्रगति हुई है. इनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडीशा और उत्तराखंड शामिल हैं. बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारने में बच्चों का वजन और उनकी लंबाई को महत्वपूर्ण मानक माना गया. जिसमें यह सामान्य से कम होता है वे लगभग बचपन से ही अक्षमता के शिकार होने लगते हैं. इन मानकों में केवल चार प्रदेशों ने उन्नति की उसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड हैं.

दोनों आंकड़े बताते हैं कि 2005-06 में लड़कियों में सामान्य से कम वजन होने की समस्या अधिक थी, लेकिन 2014 के आंकड़े इससे उलट हैं. इसमें लड़कों के सामान्य से कम वजन होने की समस्या में बढ़ोतरी हुई है. अब मूल सवाल यह खड़ा होता है कि बच्चों के विकास में उत्तर प्रदेश फिसड्डी क्यों साबित हुआ? यहां बाल पुष्टाहार के नाम पर तमाम योजनाएं चल रही हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए मिड डे मील योजना चल रही है.

उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में डॉक्टरों, खंड विकास अधिकारियों के ऊपर यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि बच्चों के पुष्टाहार से संबंधित चल रही योजनाओं की नियमित समीक्षा करते रहें. प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय भी हैं. उनकी जिम्मेदारी है कि उन्नत एवं पौष्टिक प्रजाति के खाद्यान्न का उत्पादन खेतों से कराएं. साथ ही सरकार के संबंधित विभाग से तालमेल करके उन्नत प्रजाति के दुधारू पशुओं के पालन का कर्तव्य निभाएं. मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन आदि की आधुनिक तकनीक प्रदेश में विकसित करके इनका उत्पादन बढ़ाएं.

इन सबके बावजूद बच्चों के पोषण के आंकड़ों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस नाम से जो कार्य हो रहे हैं वह केवल हवा-हवाई हैं. छोटा-सा उदहारण मूंगफली का है. सबको पता है कि मूंगफली प्रोटीन, वसा और मिनरल का सस्ता और सुलभ खाद्यान्न है. बच्चों के पुष्टाहार में इसकी उपयोगिता बेमिसाल है, लेकिन मूंगफली के उत्पादन और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने में कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है. इसकी पौष्टिकता को बनाए रखकर प्रयोग के तरीके के बारे में जागरुकता विकसित करने की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है. ऐसी हालत में प्रदेश बच्चों के सामान्य से कम वजन और उनकी लंबाई की कमी की समस्या से निजात कैसे पाएगा?

उत्तर प्रदेश को कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के दावे बिल्कुल ही खोखले साबित हो रहे हैं. प्रदेश में राज्य पोषण मिशन के तहत जरूरतमंद लोगों तक पौष्टिक पदार्थ पहुंचाने के अखिलेश सरकार के दावे हकीकत से बिल्कुल विपरीत हैं. सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने यह खुलासा किया कि कुपोषण के खिलाफ जंग की रफ्तार उत्तर प्रदेश में अत्यंत धीमी है. उर्वशी शर्मा ने आरटीआई के तहत यह जानने की कोशिश की थी कि प्रदेश में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या कितनी है. बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने जो जवाब दिया है वह वाकई चौंकाने वाला है.

प्रदेश के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय ने आरटीआई के जबाब में बताया कि मायावती का कार्यकाल रहा हो या अखिलेश सरकार का, पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने कुपोषण के संबंध में कोई भी अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं कराया है, जिससे यह बात सामने आ सके कि प्रदेश में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या कितनी है. यानी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय के पास पिछले पांच सालों में कुपोषण की समस्या से ग्रसित पुरुषों, महिलाओं, किन्नरों, बालकों, बालिकाओं और शिशुओं की संख्या की कोई भी सूचना नहीं है. सवाल है कि आखिर किस आधार पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य पोषण मिशन के शुभारंभ पर जरूरतमंद लोगों तक पौष्टिक पदार्थ पहुंचाने का दावा किया था. जब आंकड़े ही उपलब्ध नहीं हैं तो कैसे इस मिशन से प्रदेश की एक लाख महिलाओं को जोड़े जाने का दावा किया गया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

पशु खा रहे बच्चों का पोषाहार

सत्यम सिंह

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बाल विकास एवं बाल पुष्टाहार योजना समूचे अम्बेडकरनगर जनपद में औंधे मुंह गिरी हुई है. ज्यादातर केंद्रों का संचालन महज कागजों पर ही हो रहा है. आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आने वाले बाल पोषाहार की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, मुख्य सेविकाओं एवं सीडीपीओ से लेकर अधिकारियों तक की मिलीभगत से पोषाहार बाजार में बिक रहा है. बच्चों और गर्भवती महिलाओं में वितरित होने वाला पुष्टाहार पशुओं का आहार बन रहा है. बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा चलाई जा रही हॉटकुक्ड व पुष्टाहार योजना जिले में पूरी तरह धराशाई है. विभाग के आला अधिकारियों की अनदेखी के कारण योजना औंधे मुंह है. हाटकुक्ड योजना के तहत बच्चों को गर्म भोजन व फल वितरण का प्रावधान है, लेकिन गर्म भोजन व फल की कौन कहे, यहां बच्चों को सत्तू भी मयस्सर नहीं है. योजना के तहत समुचित एवं संतुलित भोजन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों को नहीं मिल पा रहा है. जनपद में ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र फर्जी हैं.

यों तो प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के अलावा विकास खंड स्तर पर मुख्य सेविकाओं की तैनाती की गई है. एक-एक मुख्य सेविका को कई-कई न्याय-पंचायतों का प्रभार सौंपा गया है. लेकिन सारी कवायद सिर्फ कागजों पर ही सिमटकर रह जा रही है. बच्चों के पोषाहार को गांवों में पशुओं को खुलेआम खिलाते देखा जा सकता है. आखिर कालाबाजारी पर अंकुश लगे भी तो कैसे, जब केंद्रों की जमीनी हकीकत जानने व जांचने की जहमत विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी व सीडीपीओ उठाते ही नहीं. मुख्य सेविकाओं द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के रजिस्टरों का सत्यापन कर दिया जाता है. जिसके एवज में तयशुदा रकम भी इन मुख्य सेविकाओं एवं सीडीपीओ से लेकर विभाग के उच्चाधिकारियों तक पहुंच जाती है. जिले में ज्यादातर केंद्रों का संचालन प्राथमिक विद्यालयों से ही होता है. लिहाजा प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को मिलने वाले दोपहर भोजन से इन बच्चों का भी काम चला लिया जाता है. इतना ही नहीं, योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले पुष्टाहार में भी लीपापोती की जा रही है. आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को न संतुलित भोजन मिल पा रहा है न ही पुष्टाहार.

कुछ महीने पहले जिले की आईसीडीएस के कार्यक्रम अधिकारी की कार्यशैली के बारे में मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित होने से प्रतीत होता था कि एकीकृत बाल विकास परियोजना में वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार अब जिले से लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अक्टूबर 2014 में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले दुर्गेश प्रताप सिंह ने जिस तरह का ऐक्शन और स्टाइल दिखाना शुरू किया था, वह महज दिखावा ही निकला. वह एक खानापूर्ति थी, साथ ही अपने अधीनस्थों से पारम्परिक रूप से चली आ रही मासिक बंधी रकम में बढ़ोत्तरी किए जाने का एक नियोजित ड्रामा था. हालांकि डीपी सिंह ने कहा था कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन ही उनका प्रयास है और शासन द्वारा मिलने वाले धन का सदुपयोग होगा, लेकिन उनके सभी वक्तव्य हवा-हवाई ही साबित हो रहे हैं. सभी योजनाओं का संचालन मात्र कागजों पर हो रहा है. जमीन पर उसकी कोई शिनाख्त नहीं है. कुछ केंद्रों का औचक निरीक्षण कर मीडिया मैनेज करके अपने मनमाफिक खबरें छपवाकर प्रचार करवा लिया जाता है. अम्बेडकरनगर के जिलाधिकारी विवेक ने आज-कल सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मुहिम चला रखी है, इसके चलते कई विभागों के अधिकारी सकते में तो हैं, लेकिन परियोजनाओं पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा. ■

feedback@chauthiduniya.com

ना मानू रे दग़ाबाज़ तोरी बतियां...

रेनू शर्मा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि देश के हर घर में 2022 तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी और देश का हर गांव जगमगाएगा. प्रधानमंत्री के इस एलान ने एक बार फिर उत्तराखंड के लोगों को हैरत में डाल दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब प्रदेश के लोगों को वादों की घुट्टी पिला रहे थे, उसी समय एक महिला हिन्दी सिनेमा का एक गीत गुनगुना रही थी. गाने के बोल इस प्रकार थे ना मानू ना मानू रे दगाबाज तोरी बतियां...

इस गृहणी महिला का इशारा साफ था कि प्रधानमंत्री जी आप जो कहते हैं, वो करते नहीं है. इसका इशारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव में किए वादों से था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ. वह चाहे कालाधन की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो या भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो. वह गृहणी प्रधानमंत्री को फिल्मी गीत के माध्यम से दगाबाज बता रही थी और मुस्कराते हुए गाने के माध्यम से कह रही थी कि अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी.

मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद डेढ़ वर्ष तक देवभूमि की धर्मनगरी और गुरू दोनों को भूल हुए थे, लेकिन देर आए दुरूस्त आए. इस क्षेत्र की हिमालयी जनता ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने पुराने वादे को पूरा किए बिना जनता से एक और वादा कर गए. प्रधानमंत्री के इस वादे ने कांग्रेस के नेताओं को उन पर हमला बोलने का मौका दे दिया. शराब, सीडी सहित अन्य मुद्दों पर विरोध झेल रही कांग्रेस अब प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड की उपेक्षा किए जाने को मुद्दा बनाकर नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन और विरोध की आवाज बुलंद कर रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आश्वासन के भरोसे आपदा पीड़ित

चौथी दुनिया ब्यूरो

तीन वर्ष गुजर जाने के बाद भी वर्ष 2012 की दैवी आपदा पीड़ितों के जख्म आज भी हरे हैं. सरकार द्वारा आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कोरे आश्वासन तो दिये गए, लेकिन आज तक आपदा पीड़ितों की मांगों पर अमल न होने से पीड़ित अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं. 13 सितम्बर वर्ष 2012 की मध्य रात्रि को ऊखीमठ क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बादल फटने से मंगोली दस, चुन्नी 18, प्रेमनगर पांच, ब्रातामणखोली चार, किमाणा-जुआ 11, डंगवाडी चार, गिरिया के तीन लोगों के साथ ही पूर्ति विभाग के गोदाम में चार नेपाली मजदूरों सहित कुल 62 लोग जिंदा दफन हो गए थे, जबकि सैकड़ों आवासीय भवनों को गंभीर व आंशिक क्षति पहुंची. प्रदेश सरकार ने आपदा से पूर्णत: क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा मात्र एक-एक लाख रुपये देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दी, जबकि उनमें से मलबा हटाने में ही आपदा पीड़ितों का डेढ़ से दो लाख रुपये खर्च हो गए थे. आपदा पीड़ितों द्वारा आपदा के समय से ही गंभीर क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा दो लाख रुपये अतिरिक्त देने की मांग की गई. आपदा पीड़ितों की मांगों पर अमल करते हुए प्रदेश सरकार ने आपदा से पूर्णत: क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों को दो लाख रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की जो आज तक नहीं मिला. सरकार की वादाखिलाफी का दंस झेल रहे आपदा पीड़ित टीनशेड में रात काटने को मजबूर हैं. सर्दियों के समय टिनशेडों में रात्रि गुजारने वाले आपदा पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. आपदा पीड़ितों का कहना है कि सरकार ने 16-17 जून को आई आपदा पीड़ितों के क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा पांच से सात लाख तक देकर ऊखीमठ आपदा पीड़ितों के साथ भेद-भाव किया है. केंद्र सरकार ने मृतक आश्रितों के लिए दो लाख रुपये की सहायता घोषित थी, कई प्रभावित परिवारों को तीन साल गुजर जाने पर भी यह धनराशि नहीं मिल पाई है. तंग हाली झेल रहे लोगों का सामूहिक फैसला हो चुका है कि वे भविष्य में लोकतंत्र का हिस्सा नही बनेंगे, उनका साफ कहना है कि प्रदेश सरकार की घो-षणाओं के अनुसार यदि आपदा पीड़ितों को क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा नहीं दिया गया तो आपदा पीड़ित 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव का पुरी तरह बहिष्कार करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी की यात्रा से भाजपा को मिली संजीवनी

राजकुमार शर्मा

अपनी गुरु भक्ति के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म नगरी ऋषिकेष आए. इतनी कम समय की सूचना के बावजूद सम्पन्न रैली में उमड़ी जनता के उत्साह को देखकर कांग्रेस के दिग्गजों के होश उड़ गए हैं. साथी ही सूबे की सरकार के मुखिया हरीश रावत की बनियाद हिला कर रख दी है. उत्तराखंड इस यात्रा में एक बार फिर मोदी ने जनता को न कोई सौगात दिया, न आपदा की दंश झेल रहे राज्य की जनता को कोई मदद की. उसके बावजूद भाजपा के जानकार मानते हैं कि हरीश की राजनीतिक कौशल से लगातार मात खा रही भाजपा को निश्चित रूप से संजीवनी मिली है. प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं को भी अब इस बात का एहसास हो गया है कि मोदी को गुटबाजी पसंद नहीं है. यही वजह है कि मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में प्रदेश के किसी भी सांसद को अब तक स्थान नहीं दिया है. मोदी की ऋषिकेश यात्रा से नेताओं व कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश से किसी न किसी सांसद को अपने मंत्रिमंडल में जरूर जगह देंगे. अब संघ भी यह चाहता है कि प्रदेश को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए. इसलिए भाजपाइयों ने आपसी गुटबाजी को त्याग कर अपने आप को मोदी के समक्ष एक साथ खड़ा किया है. इस यात्रा में कभी एक लय स्वर में न रहने वाले सूबे के चार के चारों दिग्गज भगत सिंह कोश्यारी, जनरल भूवन चन्द्र खडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक एवं नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट अनुशासन के दायरे में कतार बद्ध कदमताल करते दिखे. लोकसभा चुनाव बाद जिस तरह भाजपा के दिग्गजों का कलह सतह पर आया कि भाजपा के मोदी लहर की हवा ही उनकी अपनी करनी से निकल गई. दिग्गजों की हरकत से देवभूमि में भाजपा का भगवा ध्वज फहरने से पहले ही उलझ गया. लोग कह रहे हैं कि गुरु दर्शन के बहाने ही सही मोदी के उत्तराखंड आगमन से देवभूमि में अब पुन: भाजपा के दिन बहुरने के संकेत मिले हैं. भाजपा नेताओं को लगने लगा है कि मोदी के मन में प्रदेश के प्रति काफी लगाव है. वैसे भी प्रदेश में वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. संघ की मंसा थी कि एक बार दिग्गज गुटबाजी करने वाले नेताओं को उनकी औकात बता दी जाए, संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की मानें तो प्रधानमंत्री आभार रैली से काफी प्रसन्न हैं. भाजपा सांसदों का भी मानना है कि मोदी ने मंच से किसी भी तरह की नई घोषणा तो नहीं की है, क्योंकि वे पहले ही काफी कुछ उत्तराखंड को दे चुके हैं. कांग्रेस की सरकार केंद्र द्वारा पहले के दिए गये पैकेज का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रही है. यदि राज्य सरकार केंद्र को समय पर फंड का हिसाब भेज दी होती, तो यह संभव था कि मोदी प्रदेश के लिए किसी नई घोषणा का एलान करते. राज्य की हरीष रावत सरकार के ढुलमुल रवैया से मोदी पूरी तरह से अब वाकिफ हो गए हैं. इसलिए उन्होंने पैकेज मामले पर चुप्पी साधना ही उचित समझा. प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि राज्य सरकार पहले तो केंद्र द्वारा दिए गए पैसों का हिसाब दे. कम अवधि में केंद्र ने राज्य को बहुत कुछ दिया है. राज्य सरकार पहले इसका उचित उपयोग करे. प्रदेश सरकार को दबाव की राजनीति छोड़ देनी चाहिए और सरकार को अपना ध्यान विकास योजनाओं पर लगाना चाहिए. पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ऋषिकेश यात्रा से न ही भाजपाइयों बल्कि प्रदेश के लोगों में काफी उत्साह है. सच्चाई तो यह है कि मोदी की इस यात्रा से सभी के हौंसले बुलंद हैं. इस यात्रा ने नेताओं को झकझोरने के साथ जमीनी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार किया है. मोदी की यात्रा ने आस जगाने के साथ सत्ता का स्वाद चख रहे कांग्रेसी खेमें में बेचैनी बढ़ा दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपद मिर्जापुर की चुनार तहसील के पचेवरा गांव निवासी एक ग़रीब परिवार की निधि सिंह पटेल का जीवन काफी अभावों के बीच गुज़रा है. निधि के पास न केवल संसाधनों का अभाव था, बल्कि उनके परिवार को दो वक्त की रोटी के लाले थे. आगे बढ़ने के लिए बेहतर खेल संसाधनों के स्थान पर पत्थर के टुकड़े थे, लेकिन वह केवल अपने बुलंद हौसले के बल पर आगे बढ़ती गईं. आज उन्होंने अपनी कामयाबी से लोगों को हतप्रभ कर दिया है. 29 सितंबर को निधि को ओमान के लिए उड़ान भरनी है, लेकिन वहां जाने के लिए पैसों की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है.

पुलिस उत्पीड़न पर एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठी है

पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन तथा अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के आंकड़े भयावह हैं. हमारे देश में पुलिस वालों को दंडित करने की व्यवस्था बहुत कमजोर है. यही कारण है कि पुलिस वाले धड़ल्ले से गैरकानूनी कार्रवाइयां करते रहते हैं और उन्हें इसके लिए दंडित किए जाने का कोई भय भी नहीं है.

एसआर दारापुरी, आईपीएस (रि)

हाल में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) ने क्राइम इन इंडिया शीर्षक के अंतर्गत पूरे देश में वर्ष 2013 में घटित अपराध के आंकड़े प्रकाशित किए हैं. इन आंकड़ों में पुलिस से संबधित दो आंकड़े बहुत रोचक हैं, क्योंकि वे आम जन में व्याप्त पुलिस की उत्पीड़क छवि को झुठलाते दिखाई देते हैं, जो कि जमीनी वास्तविकता से परे हैं. यह सर्वविदित है कि पुलिस ही प्रतिदिन मानवाधिकारों का सब से ज्यादा हनन करती है. केस दर्ज न करना, आरोपियों/गैर आरोपियों की अवैध गिरफ्तारी, पुलिस हिरासत में हिंसा, तफ्तीश में कानून के बजाय डंडा तफ्तीश, झूठे मुकदमों में फंसाना, फर्जी बरामदगी दिखाना, रिश्वतखोरी और फर्जी मुठभेड़ों में मारना आदि के रूप में यह सामने आता है. पुलिस की यह कार्रवाई स्पष्ट तौर पर लोगों के मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है. अतः यह स्वाभाविक है कि पुलिस की इन गैर कानूनी कार्रवाइयों के विरुद्ध बहुत सारी शिकायतें भी होती होंगी, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2013 के लिए जारी किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि इस पूरे वर्ष में पूरे देश में पुलिस के विरुद्ध मानवाधिकार हनन की कुल दो शिकायतें ही प्राप्त हुई थीं जिनमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. इसी प्रकार उक्त अवधि में फर्जी मुठभेड़ की केवल दो शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. क्या इन आंकड़ों पर विश्वास किया जा सकता है? काश हमारी पुलिस वैसी होती जैसा कि ये आंकड़े दर्शाते हैं.

अब अगर उपरोक्त अवधि में पुलिस के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की स्थिति देखी जाए तो वह भी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में दर्ज आंकड़ों जैसी ही है. यह भी सर्वविदित है कि आम आदमी पुलिस के विरुद्ध शिकायत करते हुए डरता है. वह तभी शिकायत करता है जब उसके साथ चरम ज्यादती होती है और उसे कहीं से कोई राहत नहीं मिलती. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2013 के लिए जारी किए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उक्त अवधि में पुलिस के विरुद्ध 51,120 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 14928 में विभागीय जांच, 247 में मैजिस्टीरियल जांच और 655 में न्यायिक जांच की गई. इन जांचों के परिणाम बहुत स्तब्धकारी हैं, क्योंकि इनमें से 26,640 यानी 52 प्रतिशत शिकायतें झूठी पाई गईं. इन जांचों के परिणामस्वरूप 1989 (तीन फीसदी) मामलों में ही पुलिस वालों के विरुद्ध केस दर्ज हुए. जांच में दोषी पाए जाने पर 3896 (सात फीसदी) मामलों में विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए और 799 अर्थात महज एक प्रतिशत मामले में न्यायालयों में आरोप पत्र प्रेषित किए गए. यह आंकड़े भी दर्शाते हैं कि पुलिस के विरुद्ध की गई शिकायतों में केवल आठ प्रतिशत मामलों में ही विभागीय तथा मुकदमा चलाने की कार्रवाई की गई और 92 प्रतिशत मामलों में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई.

पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन तथा अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के आंकड़े भयावह हैं. हमारे देश में पुलिस वालों को दंडित करने की व्यवस्था बहुत कमजोर है. यही कारण है कि पुलिस वाले धड़ल्ले से गैरकानूनी कार्रवाइयां करते रहते हैं और उन्हें इसके लिए दंडित किए जाने का कोई भय भी नहीं है. पुलिस वालों के लिए दंड से इस छूट का मुख्य कारण विभाग के अन्दर उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होना है, क्योंकि निचले अधिकारियों द्वारा बहुत से गैर कानूनी काम उच्च अधिकारियों की सहमति से ही किए जाते हैं. ऐसी हालत में उनसे गैर कानूनी कामों के लिए निचले अधिकारियों को दंडित करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है. इसी का नतीजा है कि वर्ष 2013 में पुलिस के विरुद्ध शिकायतों में से 52 प्रतिशत मामलों के फर्जी/झूठे होने का जिक्र किया गया है. इसके इलावा बहुत से पुलिस कर्मचारी अपनी राजनीतिक अथवा अन्य पहुंच के कारण भी दंड से बच जाते हैं. दरअसल पुलिस में जन-शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था बहुत कमजोर है. यद्यपि मानवाधिकारों के संरक्षण और उनके हनन के मामलों में जांच/कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग बने हैं, लेकिन वे विभिन्न कारणों से निष्प्रभावी हैं. एक तो उनमें नियुक्तियां राजनीतिक लिहाज़ से की जाती हैं और दूसरे उनके पास स्टाफ बहुत कम होता है, जो कि प्राप्त शिकायतों की जांच अपने स्तर से करने में अक्षम होता है. इसीलिए आयोग में प्राप्त शिकायतों को उसी पुलिस के पास भेज दिया जाता है जिनके विरुद्ध शिकायत होती है. इससे शिकायतकर्ता का दोहरा उत्पीड़न होता है और जांच भी निष्पक्ष तौर पर नहीं होती. यही स्थिति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी है.

अतः जनता की पुलिस के विरुद्ध शिकायतों के त्वरित और सही निस्तारण के लिए एक स्वतंत्र शिकायत निवारण व्यवस्था की सख्त जरूरत है, ताकि लोगों को न्याय मिल सके और कानून का उल्लंघन करने वाले दोषी पुलिस कर्मचारी दंडित हो सकें. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित किए गए पुलिस सुधारों को लागू किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उनमें पुलिस के विरुद्ध जन शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रदेश तथा जिला स्तर पर पुलिस शिकायत निवारण कमेटियां बनाने की व्यवस्था है. अतः यह लोगों के हित में है कि वे पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए जनांदोलन चलाएं और सभी राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाएं ताकि उन्हें वर्तमान में शासक वर्ग की पुलिस के बजाय जनता की पुलिस मिल सके जो उत्पीड़क की जगह जन-मित्र बन सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

सबसे बर्बर यूपी पुलिस

आम जनता के उत्पीड़न और मानव अधिकार के उल्लंघन में उत्तर प्रदेश पुलिस देशभर में अव्वल है. पिछले पांच वर्ष (2010 से जनवरी 2015 तक) में देशभर में पुलिस पर मानवाधिकार उत्पीड़न के 4,90,206 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2,44,936 मामले केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ दर्ज हैं. यूपी में वर्ष 2010 में पुलिस उत्पीड़न के 49,751 मामले दर्ज किए गए. वर्ष 2011 में यह संख्या 53,913 पर पहुंच गई. वर्ष 2012 में पुलिस उत्पीड़न के 45,090 मामले दर्ज हुए. वर्ष 2014 (जनवरी 2015 शामिल) में पुलिस उत्पीड़न के दर्ज मामलों की संख्या 50,176 थी. मानवाधिकार आयोग के ये आधिकारिक आंकड़े जन सूचना अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछे गए सवालों के जरिए उपलब्ध हुए हैं. इलाहाबाद के आरटीआई एक्टिविस्ट और पूर्व सभासद आनंद अग्रवाल ने मनावाधिकार आयोग से बीते पांच वर्षों की जानकारी मांगी थी. आयोग ने वर्ष 2010 से जनवरी 2015 की रिपोर्ट उपलब्ध कराई, जिसमें प्रति वर्ष के हिसाब से जानकारी उपलब्ध कराई गई है. ये आकंड़े यूपी पुलिस के अमानवीय व्यवहार की सच्चाई उजागर करते हैं. मानवाधिकार आयोग के आंकड़े खुद बताते हैं कि पूरे देश में मानव अधिकार उत्पीड़न के जितने मामले दर्ज किए जाते हैं, उसमें से 50 फीसदी से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के होते हैं. हाल के दिनों में शाहजहांपुर के पत्रकार को जला कर मार डालने की घटना और बाराबंकी के एक थाने में महिला से बलात्कार की कोशिश करने और उसे जिंदा जला डालने की घटना से दुनियाभर में यूपी पुलिस का बर्बर चेहरा उजागर हुआ है. ■

प्रतिभावान खिलाड़ी निधि सरकारी उपेक्षा की शिकार

प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपद मिर्जापुर की चुनार तहसील के पचेवरा गांव निवासी एक ग़रीब परिवार की निधि सिंह पटेल का जीवन काफी अभावों के बीच गुज़रा है. निधि के पास न केवल संसाधनों का अभाव था, बल्कि उनके परिवार को दो वक्त की रोटी के लाले थे.

संतोष देव गिरी

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के पास फिल्मों के विकास के लिए बेपनाह धन है, लेकिन राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए उसके पास फंड नहीं है. प्रतिभावान खिलाड़ी सरकारी मदद के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते. मिर्जापुर की आयरन गर्ल निधि सिंह पटेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं, लेकिन उन्हें राज्य सरकार की तरफ़ से कोई मदद नहीं दी जा रही. गांव की पगडंडियों से निकल कर पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली निधि सिंह अब तक पांच बार विदेशी धरती पर पदक जीत चुकी हैं. और, यह सब उन्होंने अपने बलबूते किया. जब भी उनका चयन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चैंपियनशिप के लिए होता है, उस समय उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती. चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए उन्हें दूसरे लोगों से मदद लेनी पड़ती है.

बीते जुलाई माह में हांगकांग के एलिजाबेथ स्टेडियम में हुई एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप (सीनियर वर्ग) में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कांस्य पदक जीता है. अब निधि सिंह पटेल का चयन ओमान के मस्कट शहर में 29 सितंबर से आयोजित होने वाली एशिया बेंचप्रेस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है, जहां वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. निधि को उक्त चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए एक लाख तीस हज़ार रुपये जमा करने हैं, जो निधि के लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है. किसी तरह मशक्कत करके वह हांगकांग जाने में तो सफल रही थीं, लेकिन इस बार उनकी राह में पैसों की कमी बाधा बनकर खड़ी है. इस बार समाज से सहयोग मांगने में भी संकोच आड़े आ रहा है, लिहाजा मस्कट की राह कठिन दिखाई दे रही है. होनहार खिलाड़ी निधि सिंह पटेल की मदद के लिए न सरकार आगे आ रही है और न कोई ग़ैर सरकारी संस्था (एनजीओ) ही पहल कर रही है.

प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपद मिर्जापुर की चुनार तहसील के पचेवरा गांव निवासी एक ग़रीब परिवार की निधि सिंह पटेल का जीवन काफी अभावों के बीच गुज़रा है. निधि के पास न केवल संसाधनों का अभाव था, बल्कि उनके परिवार को दो वक्त की रोटी के लाले थे. आगे बढ़ने के लिए बेहतर खेल संसाधनों के स्थान पर पत्थर के टुकड़े थे, लेकिन वह केवल अपने बुलंद हौसले के बल पर आगे बढ़ती गईं. आज उन्होंने अपनी कामयाबी से लोगों को हतप्रभ कर दिया है. 29 सितंबर को निधि को ओमान के लिए उड़ान भरनी है, लेकिन वहां जाने के लिए पैसों की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है. फिर भी निधि को भरोसा है कि उनकी मदद के लिए कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा. निधि 2009 से 2015 के बीच अब तक भारत के लिए पांच स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक जीत चुकी हैं. बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी. निधि को यश भारती पुरस्कार देने की जन-सिफारिश की गई, लेकिन सरकार ने उस पर विचार नहीं किया. निधि के कोच कमलापति त्रिपाठी कहते हैं कि कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, यदि उनका सहयोग मिल गया, तो निधि के ओमान जाने की राह आसान हो जाएगी.

निधि की उपलब्धियां

अगस्त 2010 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप में निधि सिंह पटेल ने रजत पदक हासिल किया. अगस्त 2011 में चीन के ताइवान में आयोजित एशिया पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक और जनवरी 2012 में लंदन में हुए पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम में पांच गोल्ड मेडल हासिल किए. जुलाई 2015 में हांगकांग में हुए एशिया पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप सीनियर वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश स्तर के अनगिनत पदक हासिल किए. चार से सात मार्च 2015 तक स्टील नगरी झारखंड राज्य के जमशेदपुर स्थित जेआरडी कॉम्प्लेक्स में आयोजित राष्ट्रीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए निधि सिंह पटेल ने स्वर्ण पदक जीता और उन्हें स्ट्रॉंग वूमेन आफ इंडिया-2015 के सम्मान से नवाजा गया. ■

ठगों की भारी जमात

विदेशी धरती पर एक बार नहीं, पांच बार भारतीय पताका फहराकर अपने देश, अपने जिले और गांव का नाम रौशन करने वाली निधि और उनके परिवार के जीवन में कोई खास बदलाव भले ही नहीं आया हो, लेकिन निधि की कामयाबी को कई और लोगों ने भुनाया. इनमें कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जो निधि के साथ फोटो खिंचवा कर अखबारों में जगह बना लेते हैं और सियासत की दुकान सजा लेते हैं. मिर्जापुर स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री चुनार ने तो निधि को आर्थिक मदद और पढ़ाई में सहयोग के साथ स्कूटी देने, स्पोर्ट डायरेक्टर के पद पर नौकरी देने इत्यादि का वादा जनता व जनप्रतिनिधियों के सामने किया था, लेकिन उसे आज तक पूरा नहीं किया. कंपनी द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि भी कुछ दिनों के बाद बंद कर दी गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार-झारखंड

28 सितंबर-04 अक्टूबर, 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार चुनाव के राजनीतिक परिपेक्ष्य दिनोंदिन बदल रहे हैं. कभी कोई नेता महगठबंधन से टूटता है तो कभी एनडीए से. सभी जातीय गणित लगा रहे हैं. लेकिन अब लगता है कि महागठबंधन और एनडीए की गणित फेल हो सकती है. इसका कारण है बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और उद्धव ठाकरे जैसे दो नेताओं की मौजूदगी. इस चुनाव में पहली बार सीमांचल इलाके में ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी. उद्धव ने भी शिवसेना के प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है. अब एक बात तो तय है कि इन दोनों नेताओं की मौजूदगी से पहले से बैठाई गई एनडीए और महागठबंधन की गणित गड़बड़ा सकती है. इन नेताओं के बिहार चुनाव पर पड़ सकने वाले असर की पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट...

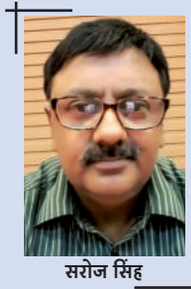

सरोज सिंह

बिहार में चुनावी मुद्दे के तौर पर विकास का नाम तो सभी दल के नेता लेते हैं पर ज़मीनी सच्चाई तो यह है कि मतदान का दिन आते-आते वोटिंग पर जातीय रंग बढ़-चढ़ कर बोलने लगता है. इस कड़वी सच्चाई से बिहार के चुनावी गणित को समझने वाले अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक पंडितों की इस समझ में भी पेच फंस गया है. यह पेंच फंसाया है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने. शिवसेना तो पहले भी बिहार के चुनावों में शिरकत कर चुकी है पर ओवैसी ने पहली बार बिहार के सीमांचल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. ओवैसी के ऐलान के साथ ही राजनीति गरमानी थी और वह गरमा गई. सीमांचल के साथ ही साथ अब पूरे बिहार में यह बहस शुरू हो गई है कि जातीय ध्रुवीकरण पर धार्मिक ध्रुवीकरण हावी तो नहीं हो रहा है. राजद ने साफ किया है कि वह किसी भी तरह की कट्टरता के खिलाफ है चाहे वह हिंदू-कट्टरवाद हो या फिर मुस्लिम कट्टरवाद. बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद ओवैसी की बिहार चुनाव में एंट्री से ख़ासे चिंतित हैं. दरअसल उनकी चिंता सीमांचल की केवल 25 सीटों को लेकर नहीं है बल्कि पूरे बिहार में धर्म आधारित ध्रुवीकरण को लेकर है. राजद के थिंक टैंक का मानना है कि ओवैसी केवल सीमांचल के 25 सीटों को ही प्रभावित नहीं करेंगे बल्कि उनके तीखे भाषणों का असर बिहार की सभी 243 सीटों पर पड़ सकता है. इधर ओवैसी ने जैसे ही चुनाव लड़ने की घोषणा की वैसे ही शिवसेना ने 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का एलान कर दिया. जानकार बताते हैं कि शिवसेना ने तय किया है कि जहां-जहां ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी होगा वहां शिव-सेना के उम्मीदवार भी चुनावी दंगल में उतरेंगे. शिवसेना प्रमख उद्धव ठाकरे भी अपने आक्रामक तेवर वाले भाषणों के लिए जाने जाते हैं. अगर बिहार में ओवैसी और ठाकरे का आमना-सामना हो गया और दोनों एक दूसरे के आर-ोपों का जवाब देने लगे तो फिर बिहार के चुनाव में जातीय रंग के ऊपर धार्मिक रंग चढ़ना तय है. ऐसे हालात में तय है कि चुनाव अपने पुराने फार्मूले में नहीं होगा और यही लालू और नीतीश कुमार की चिंता का कारण है. अभी तक यह मान कर चला जा रहा था कि महागठबंधन के पक्ष में कम से कम माय समीकरण यानि की मुस्लिम और यादव के वोट एकमुश्त पड़ेंगे. लेकिन ओवैसी ने इस समीकरण में ही सेंध लगा दी. ओवैसी की किशनगंज की सभा में जिस तरह से मुस्लिम समाज ख़ासकर युवा वोटर आए उससे साफ है कि माय समीकरण का टूटना तय है. राजद का थिंक टैंक इतना तक तो बर्दाश्त करने की स्थिति में है लेकिन अगर शिवसेना के आक्रामक तेवर के बाद बिहार का चुनाव धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ गया, तब क्या होगा इसका जवाब महागठबंधन के पास नहीं है. ऐसे हालात में तमाम जातीय समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे. शिवसेना के आने का कुछ नुकसान एनडीए को भी होगा लेकिन इस नुकसान से कहीं ज्यादा लाभ चाहे-अनचाहे एनडीए के प्रत्याशियों को मिल जाएगा. अब थोड़ा यह जान लेना ज़रूरी है कि आखिर मुसलमानों का एक तबका खासकर युवा मुस्लिम क्यों ओवैसी का दीवाना हो गया है. ग़ौरतलब है कि अयोध्या के विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद और उदारीकरण के दौर में पली-बढ़ी मुसलमानों की नई पीढ़ी भाजपा भय से उस तरह ग्रसित नहीं है जिस तरह उनकी पुरानी पीढ़ी रही. युवा पीढ़ी में विकास की रफ्तार से कदमताल करने की बेचैनी है. वह उदारीकरण के बाद उभरते नए भारत में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहती है. मध्य वर्ग के विस्तार और शिक्षा के प्रसार ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. करोड़ों युवा मुसलमानों की इसी बेचैनी को वोट में तब्दील करने का काम कर रही है दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन. इसके नेता असदुद्दीन ओवैसी अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं. उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तो अपने भाषणों में अक्सर बहुसंख्यसकों के ख़िलाफ जहर उगलते रहते हैं. ओवैसी मुसलमानों के हक के लिए वोट बैंक की बजाये सीधी राजनीतिक लड़ाई लड़ने का आह्वान करते रहे हैं. दशकों से हैदराबाद तक सिमटी उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने निकल चुकी है. महाराष्ट्र में मौजूदगी दर्ज कराने के बाद पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की है. इनकी इस घोषणा के बाद से ही एम-वाई यानी मुस्लिम-यादव फॉर्मूले वाली वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों-नेताओं की नींद उड़ गई है. ओवैसी की धमक से आतंकित ये नेता अपनी खामियों को दूर करने की बजाय इसे भाजपा की चाल बता रहे हैं.

ओवैसी मुसलमानों के हक के लिए वोट बैंक की बजाय सीधी राजनीतिक लड़ाई लड़ने का आह्वान करते रहे हैं. दशकों से हैदराबाद तक सिमटी उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने निकल चुकी है. महाराष्ट्र में मौजूदगी दर्ज कराने के बाद पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की है. इनकी इस घोषणा के बाद से ही एम-वाई यानी मुस्लिम-यादव फॉर्मूले वाली वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों-नेताओं की नींद उड़ गई है. ओवैसी की धमक से आतंकित ये नेता अपनी खामियों को दूर करने की बजाय इसे भाजपा की चाल बता रहे हैं.

– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

एक नज़र

चुनावी हलचल

मोबाइल की शानदार लॉन्चिंग

पटना के होटल पाटलीपुत्र में हल्ला बोल कार्यक्रम एवं चैनल पार्टनर मीट का आयोजन किया गया. आयोजन में बाजार में मजबूती से पकड़ बना रही मोबाइल ओरई के द्वारा किया गया. कार्यक्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री श्याम रजक के साथ साथ, बेतिया के पूर्व विधायक सतीष चन्द्र के अलावा मोबाइल कम्पनी के बिजनेस कंट्री हेड, मनोज कुमार के अलावा बिहार हेड एजीएम संतोष भी मौजूद रहे. कंपनी ने सरकार की महत्वकांक्षी प्रोग्राम 'मेक इन इंडिया' के तहत नोएडा में अपना पहला भारतीय संयंत्र स्थापित किया है. कंपनी हेड ने बताया कि नोएडा में स्थापित एवं बनने वाले इस फोन की बिक्री भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी होगी. भारत को विनिर्माण का केन्द्र बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कर में छूट जैसे उपायों के तहत कंपनी के संयंत्र को स्थापित करने का प्रोत्साहन मिला है. कंपनी का दावा है, प्रोडक्ट हर पहलू पर खरा है और कम समय में ही यह मार्केट में अपनी जगह बना लेगा. इस मौके पर सुपर स्टॉकिस्ट प्रमोद कुमार एरिया सेल्स मैनेजर संतोष कुमार, मार्केटिंग मैनेजर संतोष कुमार सहित अन्य कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद रहे.

- चौथी दुनिया ब्यूरो

उम्मीदवार विकास शपथ पत्र के साथ

बिहार की राजनीति में पहली बार कोई उम्मीदवार शपथ-पत्र लेकर विकास करने का दावा कर रहा है. इस उम्मीदवार का कहना है कि 183 कुम्हरार विधानसभा में विकास नहीं हुआ तो जनता उनपर मुकदमा कर सकती है. यह बात खुद निर्दलीय प्रत्याशी सह मोर्चा के संयोजक ब्रजेश मिश्र ने कही है. ब्रजेश ने आगे बताया कि विधायक बना तो अपने वेतन की 50 प्रतिशत राशि प्रतिमाह युवा विकास एवं महिला सम्मान में खर्च करूंगा और जनता को धोखा दिया तो मुझ पर आईपीसी की धारा 406 एवं 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं. ब्रजेश ने शपथपत्र के साथ लोगों के घर-घर जाकर जागरूक भी किया है. ब्रजेश अपने क्षेत्र की प्रत्येक जनता तक इस शपथ-पत्र को पहुंचाने का काम कर रहे हैं. ब्रजेश ने लोगों को बताया कि बिहार के विकास में बाध पहुंचता है तो विधायक से ज्यादा आम वोटर ही जिम्मेवार है. जब तक शपथ-पत्र उम्मीदवार अपने वोटर को न दे, वोट देना तो दूर इसको अपने मोहल्ले में भी आनें नहीं दे.

-रजनीकांत पाण्डेय

विधायक बना तो बदल दूंगा तस्वीर

राजद प्रमुख लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप ने कहा कि अगर वे विधायक बने तो क्षेत्र की तस्वीर बदल कर रख देंगे. यह बातें महुआ विधानसभा क्षेत्र के महुआ कोल्ड स्टोरेज परिसर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए तेज प्रताप ने कही. तेज प्रताप कार्यकर्ताओं को एकजुट रह कर चुनाव पर विजय पाने के लिए अपील भी की. इस मौके पर उजियारपुर के पूर्व सांसद अलोक मेहता ने अपने सम्बोधन में कहा साम्प्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए पुन: सरकार बनानी होगी. इस सम्मेलन की अध्यक्षता महुआ प्रखंड के अध्यक्ष मो. कलाम ने की और संचालन जदयू अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह ने की इसके आलावा सम्मेलन में अन्य लोग भी मंचासीन रहे.■

- नसीम रब्बानी

17 पीपरा विधान सभा

न मोदी लहर, न जंगलराज का कहर केवल जाति का असर

राकेश कुमार feedback@chauthiduniya.com

> कुशवाहा के टिकट नहीं मिलने के कयास के बाद दावेदारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. जदयू से भी दावेदार खड़े हो गये हैं. जदयू अति पिछडा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष लव किशोर निषाद प्रबल दावेदारी कर रहे हैं. श्री निषाद अतिपिछडा वर्ग से आते हैं और वर्तमान में जिला 20 सूत्री के सदस्य हैं. इसके पूर्व जदयू अतिपिछडा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रहे हैं. शहीद जुब्बा सहनी संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष है. पीपरा कोठी पंचायत के तजेयापूर निवासी श्री निषाद महागठबंधन के वोट पर चुनाव जीतने का दावा करते हैं.

अरुण कुशवाहा | ललित कुमार सिंह | लव किशोर निषाद | डॉ. वीके राय | अवधेश कुशवाहा

पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत 17 पीपरा विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के चुनाव के लिए मतदान चौथे चरण में 1 नवम्बर को होगा. अभी तक यह निश्चित नहीं है कि यह सीट एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के किस घटक दल को मिलेगी. लेकिन दावेदारों की फौज तैयार है. सभी दल के दावेदार इस सीट को अपना बता रहे हैं. पीपरा विधान सभा क्षेत्र तीन प्रखण्डों से बना है, जिसमें चकिया प्रखण्ड की 18 पंचायत, मेहसी प्रखण्ड की 16 और तेतरिया प्रखण्ड की 9 पंचायत शामिल हैं. इस सीट का चुनावी दंगल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहां के विधायक अवधेश कुशवाहा हैं. श्री कुशवाहा बिहार सरकार के गन्ना मंत्री, लघु सिचाई मंत्री रह चुके हैं. वर्तमान में वे बिहार सरकार के निबंधन विभाग और मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं. जानकारों की मानें तो जदयू के श्री कुशवाहा के टिकट पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है. वहीं उनके राजनीति से सन्यास लेने और अपने बेटे कृष्णार्जुन कुशवाहा को खड़ा करने की चर्चा से यह बात पुष्ट होती है. हालांकि सीटिंग विधायक होने के कारण श्री कुशवाहा सीट को लेकर आश्वस्त दिखते हैं. क्षेत्र की जनता मंत्री कुशवाहा से खासी नाराज है. खासकर किसानों में तो आक्रोश दिखता है. इसका मुख्य कारण है कि गन्ना मंत्री रहते हुए भी वे चकिया चीनी मील को चलवा नहीं सके. दूसरे शब्दों में कहें तो चीनी मिल को खोलने को लेकर इन्होंने कभी कोई सार्थक कदम भी नहीं उठाया. गन्ना इस क्षेत्र का अकेला नकदी फसल माना जाता है. चकिया मील बन्द होने के कारण किसानों को गन्ना दूसरे मिलों में ले जाना पड़ता है जहां उन्हें घटतौली, ससमय भुगतान नहीं होने और अतिरिक्त भाड़ा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता रहा है. हालांकि मंत्री इस मामले से अपना पल्ला यह कहकर झाड़ते रहे हैं कि यह मील सरकारी नहीं है और इसका मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है.

बहरहाल, श्री कुशवाहा के टिकट नहीं मिलने के कयास के बाद दावेदारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. जदयू से भी दावेदार खड़े हो गये हैं. जदयू अति पिछडा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष लव किशोर निषाद प्रबल दावेदारी कर रहे हैं. श्री निषाद अतिपिछडा वर्ग से आते हैं और वर्तमान में जिला 20 सूत्री के सदस्य हैं. इसके पूर्व जदयू अतिपिछडा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रहे हैं. शहीद जुब्बा सहनी संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष ...

... सदस्य रहे. ताम्र पत्र से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी रूपलाल राय आजीवन समाज की सेवा में लगे रहे. वहीं संजय निराला के पिता श्री विद्यानन्दन प्रसाद राय भी राजनीति से जुड़े रहे. 1978 से वे लगातार 35 वर्षों तक लहलादपुर के मुखिया रहे. राजनीतिक परिवार के संजय निराला शुरू से ही राजद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं. 2008 से लगातार भूमि विकास बैंक ...

... था. जाति-धर्म से उपर उठ कर पूरे समाज को साथ लेकर चलने वाले रूपलाल राय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे. तब पीपरा का क्षेत्र भी मधुबन में ही आता था. रूपलाल राय तीन बार 1952, 1957 और 1977 के चुनाव में जीते और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. 1947 से 1957 तक डिस्ट्रिक बोर्ड के

... वर्गों में इनकी पैठ है. भाजपा के ही अरुण कुशवाहा भी जोर आजमाइश कर रहे हैं. भाकपा से राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले पूर्व मुखिया श्री कुशवाहा 2004 से हीं भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं. 2005 के दोनों चुनाव में वे चुनाव प्रभारी रहे और दोनों हीं बार पीपरा से भाजपा विजयी रही. बकौल श्री कुशवाहा 2009 और 2014 के लोक सभा चुनाव में वे पीपरा ...

... कुमार मौर्य टिकट के दावेदार हैं. श्री मौर्य क्षेत्र की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं. वैश्य समाज के श्री मौर्य बड़े व्यवसायी हैं और राजनीति से जुडे रहे हैं. पूर्व में वे राजद के सक्रिय राजनीति में थे. 2014 के लोस चुनाव में वे भाजपा के साथ जुड़े और सक्रियता से काम किया. वैश्य मत के साथ सभी ...

... पार्टी से किस जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है. क्षेत्र में न तो मोदी लहर दिखाई दे रहा है और न हीं विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है. हालांकि मतदाता जातीय समीकरण के गणित में लगे है परन्तु चुप्पी साधे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ 17 का शेष

धार्मिक ध्रुवीकरण को हवा देंगे उद्धव और ओवैसी

एमआइएम की रणनीति देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी बनने की है. उसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीती हैं. यह जीत भले छोटी लगे, लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी के बुलंद होते इरादों ने क्षेत्रीय और सेकुलर नेताओं की नींद हराम कर दी है. अब वे ...

... चाहिए और विकास की बात होनी चाहिए. ओवैसी की ऐसी बातें सुनने में तो ठीक लगती हैं पर इसे पेश करने का उनका अंदाज ऐसा होता है कि इसका साइड इफेक्ट बिहार के कई चुनावी समीकरण को तहस नहस कर सकता है. यह ओवैसी और शिवसेना के बिहार चुनाव ...

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

चुनावी दंगल में फतह को लेकर कसरत शुरू

> सीतामढ़ी जिले की बेलसंड विधानसभा सीट पर वर्तमान में जदयू का कब्जा है. इस सीट से सुनीता सिंह चौहान विधायक हैं. इस क्षेत्र में 1 लाख 25 हजार 869 पुरूष एवं 1 लाख 9 हजार 335 महिलाओं के अलावा थर्ड जेंडर का 1 मतदाता है. अबकी बार चुनावी सुगबुगाहट के साथ ही बेलसंड क्षेत्र में स्थानीय बनाम बाहरी का नारा बुलंद होना शुरू हो गया है. चर्चा है कि क्षेत्र की जनता इस चुनाव में प्रत्याशी के चयन का अंदाज बदलने का मिजाज बना रही है. चुनाव अब सिर पर है. मतदाता का निर्णय क्या होगा, इसका खुलासा भी हो जायेगा. बस टिकट वितरण किये जाने का इंतजार है. रुन्नीसैदपुर विधानसभा सीट पर लगातार दो बार से जदयू का कब्जा है. इस सीट से गुड्डी देवी विधायक हैं.

गुड्डी देवी | रंजू गीता | सुनीता सिंह चौहान | शाहिद अली खान | सुनील कुमार पिंटू | मोतीलाल प्रसाद

वाल्मीकि कुमार feedback@chauthiduniya.com

बिहार विधानसभा चुनाव का आचार संहिता लागू होने के साथ ही सीतामढी जिला में चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गयी है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि निर्धारित किये जाने के साथ ही राजनीतिक एवं प्रशासनिक हलको में चुनावी कसरत जोर पकड़ने ...

... पर लगातार दो बार से जदयू का कब्जा है. इस सीट से गुड्डी देवी बतौर विधायक है. अबकी बार इनको चुनावी घेराबंदी करने को लेकर एनडीए चक्रव्यूह रचने में लगी है. भाजपा, रालोसपा व लोजपा उपयुक्त प्रत्याशी की तलाश में हैं. इस क्षेत्र में करीब 1 लाख 37 हजार पुरुष एवं 1 लाख 18 हजार 845 महिला मतदाता के अलावा थर्ड जेंडर के 7 मतदाता हैं.

बाजपट्टी विधानसभा सीट से पिछले चुनाव में बतौर विधायक चुनी गयीं जदयू की डॉ. रंजू गीता सूबे की सरकार में गन्ना उद्योग विभाग में मंत्री हैं. 2015 के विधानसभा चुनाव में पुन: दावेदारी को लेकर प्रयासरत हैं. परंतु अबकी बार उनके चुनावी घोड़े की लगाम थामने के लिए उनके स्वजातीय कुछ पंचायत प्रतिनिधि माहौल बना रखे हैं. इस क्षेत्र से 1 लाख 51 ...

> अब चुनावी रणभेरी बज चुकी है. चुनावी समर में प्रत्याशी आमने - सामने ताल ठोंकने को तैयार है. गठबंधन की राजनीति को लेकर कुछ के अरमान पूरे तो बाकी का अधूरा रह जाने की पूरी संभावना बन रही है. अबकी बार के चुनाव में साफ लगता है कि सीतामढ़ी जिले में एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी चुनावी टक्कर होगी. जाति व पार्टी के बीच चल रहे चुनावी घमासान का परिणाम क्या होगा ? फिलहाल कहना मुश्किल है. टिकट वितरण के बाद ही यह खुलासा भी हो सकेगा कि बेटिकट वाला खेमा क्या करता है.

हजार 31 पुरुष एवं 1 लाख 32 हजार 723 महिला मतदाता हैं. रीगा विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है. इस सीट से मोतिलाल प्रसाद विधायक हैं. चर्चा है अगर कोई मजबूत प्रत्याशी महागठबंधन से मैदान में आता है तो उनके लिए परेशानी बन सकता है. इस क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार 631 पुरुष एवं 1 ...

... चर्चा है कि क्षेत्र की जनता इस चुनाव में प्रत्याशी का चयन का अंदाज बदलने का मिजाज बना रहे हैं. चुनाव अब सिर पर है. मतदाता का निर्णय क्या होगा, इसका खुलासा भी हो जायेगा. बस टिकट वितरण किये जाने का इंतजार है. रुन्नीसैदपुर विधानसभा सीट ...

... जेंडर के 14 मतदाता हैं. बथनाहा सुरक्षित सीट पर भी भाजपा का कब्जा है. इस सीट से दिनकर राम विधायक हैं. अबकी बार महागठबंधन की पैनी नजर इस सीट पर है. बथनाहा क्षेत्र में 1 लाख 45 हजार 122 पुरुष एवं 1 लाख 30 हजार 872 महिला मतदाता ...

... के अलावा थर्ड जेंडर के 12 मतदाता हैं. परिहार विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है. इस सीट से राम नरेश प्रसाद यादव बतौर विधायक रहे हैं. परंतु हाल के महीनों में एक मुकदमा में सजा होने के कारण उनका चुनावी सपना ध्वस्त होता दिख रहा है. चर्चा है कि इस सीट पर एक ओर महागठबंधन कब्जे के चक्कर में है तो दूसरी ओर भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखने को लेकर प्रयासरत है. इस क्षेत्र में 1 ...

... चुनाव में बेटिकट पार्टी कार्यकर्ता कुछ अलग ही गुल खिलाने की फिराक में है. अगर ऐसा होता है तो किसी भी दल के प्रत्याशी के लिए एक अलग मुसीबत खड़ी हो सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

हॉस्टल बना अपराधियों की पनाहगाह

सुरेश चौहान feedback@chauthiduniya.com

राजकीय जीडी कॉलेज का ओल्ड हॉस्टल छात्रों की बजाय अपराधियों की पनाहगाह बनता जा रहा है. विद्या की देवी सरस्वती का आवास ...

... उच्च विद्यालय तेघड़ा के छात्रावास में मिडल स्कूल स्थापित किया जा चुका है. उच्च विद्यालय तेयाय का छात्रावास जर्जर हो घराशायी हो चुका है. जयमंगला उच्च विद्यालय मंझौल का छात्रावास जर्जर होकर खंडहर बन चुका है.

सिर्फ उच्च विद्यालयों के छात्रावास की ...

एक नज़र

चुनावी हलचल

बढ़ जाता है शराब और पैसों का खेल

चुनाव के समय महादलित बस्तियों में पैसे और शराब का खेल बढ़ जाता है. महादलितों के मतों का हरण किया जाता है. उक्त बातें महादलित उत्थान संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक अवधेश राम एवं मानवाधिकार उल्लंघन नियन्त्रण प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताईं. संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अवधेश राम ने आगे कहा कि हम पिछले दशक से ही महादलितों के साथ हो रहे अन्य को देख रहे हैं. महादलितों के वोटों को खरीदा जाता है और इन्हें बेचा दिया जाता है. महादलितों को पता तक नहीं चलता कि उनके हितों की हत्या कब और कैसे हो गयी. अवधेश ने बताया कि हमारी संस्था महादलितों के बीच जाकर उन्हें उनके अधिकार के प्रति जागरूक करती है और इस काम में मानवाधिकार उल्लंघन नियंत्रण प्रकोष्ठ हमारी मदद करती है .

- रजनीकांत पाण्डेय

शत-प्रतिशत मतदान का हो प्रयास : डीएम

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है. आयोग के निर्देश के आलोक में सीतामढ़ी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रौशन ने आवश्यक निर्देश प्रशासनिक महकमे को जारी कर दिया है. चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान को लेकर स्वीप कोशांग की गतिविधियों को बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया गया है. गैर राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं के अलावा प्रेस प्रतिनिधियों से भी अभियान में भागीदारी की अपील की गयी. सीतामढ़ी जिले में भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के पत्रकारों का संगठन मीडिया फॉर बोर्डर हारमोनी ने भी अपनी भागीदारी जागरूकता अभियान में देने का निर्णय लिया है. संगठन के कार्यक्रम प्रभारी सर्वधीर मिश्र ने बताया कि मीडिया संवाद के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का संगठन ने निर्णय लिया है. इस संबंध में जिला के वरीय पदाधिकारियों से सहयोग का आग्रह किया गया है.

- ब्रजेश

भारतीय क्षेत्र में हो रहा प्रदर्शन

नेपाल में मधेशियों की उपेक्षा एवं संविधान मसौदा के प्रारूप को लेकर उपजा आक्रोश अब भारतीय सीमा को पार कर चुका है. पिछले दिनों सीतामढ़ी जिले में भिटठा मोड, सुरसंड, बैरगनिया व बेला समेत अन्य स्थानों पर लोगों ने मधेश आंदोलन के समर्थन में रोष व्यक्त किया. साथ ही भारतीय सीमा से होकर नेपाल में किसी भी प्रकार के सामानों की आपूर्ति नहीं होने देने का निर्णय लिया. नेपाल-भारत भातृ संघ के अध्यक्ष डॉ. नवल किशोर सिंह व संघर्ष यात्रा के अध्यक्ष शशि शेखर ने साफ लहजे में कहा कि भारत विरोधी शक्तियां भारत-नेपाल के संबंध को जलाने की साजिश कर रही हैं. सीतामढ़ी जिला मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के ई. राकेश कुमार मिश्र ने 10 सदस्यीय कमिटी का गठन कर मधेशियों से उनकी समस्या के संदर्भ में मुलाकात की योजना बनायी है.

- विकास

डॉ आनंद प्रकाश हुए सम्मानित

सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित गीता भवन में हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मौके पर आयोजित कवि सम्मेलन के दौरान हिंदी साहित्य जगत में बेहतर योगदान के लिए डॉ आनंद प्रकाश वर्मा को सम्मानित किया गया. ई सचिंद्र कुमार हीरा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन गीतकार गीतेश ने किया. कार्यक्रम में तौहिद अश्क, सत्येंद्र मिश्र, वाल्मीकि, पृथ्वीराज राणा, शफी अजीज, प्रो डॉ राज कुमार गुप्ता, डॉ अवधेश अरूण, रामबाबू सिंह, डॉ शत्रुघ्न यादव व प्रो जीतेंद्र कुमार वर्मा समेत अन्य ने काव्य प्रस्तुती से वातावरण में साहित्य पवन का प्रवाह कर दिया.

- विकास

खगड़िया विधानसभा क्षेत्र

खगड़िया में दिग्गजों का भारी जमावड़ा

मनेन्द्र /गीता

लोकसभा चुनाव परिणाम से जहां लोजपा उत्साहित है वहीं भाजपा के द्वारा खगड़िया जिले के चार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के दावेदारी का सिलसिला का कतार लगा हुआ है. इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बेताब एनडीए गठबंधन का प्रचार अभियान ज़ोरों पर है. वहीं, महागठबंधन की ओर से वर्तमान प्रत्याशी अपनी दावेदारी को लेकर चिंतित हैं. कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां प्रत्याशी बदलने की बात हो रही है. इसकी वजह से कई दिग्गज नेताओं का भविष्य अधर में लटक गया है. जिले की वर्तमान जदयू विधायक पूनम देवी यादव, आरएन सिंह, पन्ना लाल पटेल का विजय अभियान पिछले कई चुनावों से जारी है. वहीं अलौली विधानसभा क्षेत्र में साल 2010 में पहली बार जदयू के रामचंद्र सदा ने लोजपा के दिग्गज नेता पशुपति कुमार पारस को पराजित किया था. इस बार भरोसे की बात है कि उक्त प्रत्याशी अपनी जीत की प्रति आश्वत हैं.

अगर भाजपा की बात करें तो जिले में कमल खिलाने को लेकर चारों विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों प्रत्याशियों के द्वारा दावेदारी की जा रही है. वहीं लोजपा-रालोसपा भी ताल ठोंके हुए हैं. विधान पार्षद सम्राट चौधरी द्वारा भी उम्मीदवारी की अप्रत्यक्ष ढंग से दावेदारी दी जा रही है.

अलौली में जदयू के विधायक रामचन्द्र सदा, जदयू की जिला अध्यक्ष साधना देवी, राजद के जिला अध्यक्ष रामवृक्ष सदा, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, भाजपा से कमलदेव चौपाल तथा डोमन सदा एवं कांग्रेस के अविनाश कुमार अविनाश अपनी दावेदारी को लेकर पटना के चक्कर लगा रहे हैं. वहीं खगड़िया विधानसभा की बात की जाय तो जदयू की ओर से वर्तमान विधायक पूनम देवी यादव का टिकट पक्का माना जा रहा है. इसलिए जदयू में टिकट को लेकर ऊहापोह की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है. वहीं भाजपा और लोजपा की ओर से चन्द्रमुखी देवी,विजेन्द्र यादव, रामानुज चौधरी सहित कई दावेदार हैं. जन अधिकार पार्टी की तरफ से मनोहर कुमार यादव को प्रबल दावेदार माना जा रहा है. वैसे तो जिले के चर्चित डॉ. विवेकानंद के भाई ई. धर्मेन्द्र कुमार, संजय यादव सहित वाममोर्चा की भी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है. बेलदौर विधानसभा की बात की जाय तो महागठबंधन की ओर से जदयू के वर्तमान विधायक पन्ना लाल पटेल, जिप उपाध्यक्ष सुनील कुमार, अशोक सिंह, बब्लू मंडल, नप सभापति गोगरी रंजिता कुमार निषाद सहित कई दावेदार हैं. लोजपा की ओर से सुशांत यादव, पूर्व विधायक सुनीता शर्मा, हम की ओर से अधिवक्ता मो. अफरोज आलम, भाजपा की ओर से प्रदेश के वरीय नेता संजीव क्षत्रिय, भवानी सिंह तथा बेलदौर विकास मोर्चा की ओर डॉ. अखिलेश कुमार विद्यार्थी की चुनाव लड़ने की चर्चा है. जबकि बीते चुनाव में भाग्य अजमाने वाले विजय कुमार पाण्डव भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है. वहीं जिले के सबसे रोचक विधानसभा क्षेत्र की बात की जाय तो परबत्ता विधानसभा है जहां लोकसभा में लोजपा को अपार बहुमत मिला था ठीक इसके विपरीत विधानसभा के उपचुनाव में उसे काफी मतों के अन्तर से हार का सामना करना पड़ा था.

परबत्ता क्षेत्र से जदयू की ओर से आरएन सिंह का टिकट पक्का माना जा रहा है. वहीं एनडीए गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों को टोटा है कि कौन प्रत्याशी आरएन सिंह को पटखनी दे सके. बीते प्रो. सुहेली मेहता को लोजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया. वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, अभी यह चर्चा का विषय है. वहीं भाजपा की ओर से अखिल कुमार राय, रामानुज चौधरी, सुमिता देवी राय तथा सुनिल चौरसिया, लक्ष्मण सहनी का तथा पूर्व छात्र नेता बाबू लाल शौर्य के द्वारा भी दावेदारी प्रस्तुत की गई है. जबकि मुखिया मो. इरफान आलम भी चुनावी समर में कूदने की तैयारी में हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

विकास करने वाली सरकार बने

समाज का विकास जटिल रास्तों से होकर गुजरता है. इसकी गतिविधि को समझा जा सकता है, लेकिन, जनहित के मनोवांछित परिवर्तन की दिशा में समाज के विकास को मोड़ा भी जा सकता है, पर यह तभी संभव है, जब हमारे शासक विकास कार्य को जन-मानस तक पहुचाएं. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे की गतिविधियों पर पटना हाईकोर्ट के जाने-माने वकीलों से चौथी दुनिया के संवाददाता रजनीकांत पाण्डेय ने बातचीत की. पेश हैं कुछ अंश...

केंद्र सरकार के पिछले अठारह महीनों के शासनकाल पर दीनू कुमार ने बताया बहुत दिनों के बाद भारत को एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला है जिससे देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है. लोगों का जातिवाद की ओर से भी ध्यान हट रहा है. युवा रोजगार पाने की उम्मीद देख रहे हैं. आगामी सरकार को सुझाव देने के सम्बन्ध में दीनू कुमार का मानना है कि सरकार जिसकी भी बने राज्य को विकास को गति दे. बिहार की शिक्षा, हेल्थ और कानून व्यवस्था पर अधिक से अधिक ध्यान दे.

दीनू कुमार

वरिष्ठ वकील दीनू कुमार का मानना है कि बिहार की शिक्षा, हेल्थ, कानून व्यवस्था, पंचायत और ब्लॉक स्तर की मूलभूत सुविधा बिल्कुल चौपट हो गई है. सरकार की ओर से दिए गए जातिवाद के आधार पर आरक्षण से राज्य में हो रही समस्या पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए. वहीं वर्षों से सुगर मिल बंद पड़ी है जिनको पुन: चालू करने पर भी विचार करना चाहिए. दीनू जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद को स्पष्ट नहीं बताया. स्पष्ट बहुमत या खिचड़ी वाली सरकार की संभावना पर दीनू कुमार का मानना है कि सरकार तो पूर्ण बहुमत की ही होनी चाहिए इसके आलावा विपक्ष भी सशक्त हो तभी सरकार अच्छी चलेगी. केंद्र सरकार के पिछले अठारह महीनों के शासनकाल पर दीनू कुमार ने बताया बहुत दिनों के बाद भारत को एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला है जिससे देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है. लोगों का जातिवाद की ओर से भी ध्यान हट रहा है. युवा रोजगार पाने की उम्मीद देख रहे हैं. आगामी सरकार को सुझाव देने के सम्बन्ध में दीनू कुमार का मानना है कि सरकार जिसकी भी बने राज्य को विकास को गति दे. बिहार की शिक्षा, हेल्थ और कानून व्यवस्था पर अधिक से अधिक ध्यान दे.

गौरंगा चटर्जी

पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरंगा चटर्जी ने मुख्यमंत्री की पसंद एनडीए के चेहरे को बताया. वहीं उन्होंने एनडीए की सरकार बनने की पूर्ण उम्मीद भी जताई. गौरंगा राज्य सरकार की ओर से मांगों के सवाल पर कहते हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है. प्रशासन अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है. जिसपर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए. अभी तक के बेहतर शासनकाल पर गौरंगा ने नीतीश सरकार के शुरुआती पांच सालों का जिक्र किया. वहीं केंद्र सरकार के मोदी शासनकाल को उन्होंने बेहतर बताया. बिहार में बनने वाली नई सरकार को सुझाव के तौर पर चटर्जी बताते है कि सरकार को बहुत कड़ाई से काम करना चाहिए. न्याय मिलने की प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए. शिक्षकों को सम्मान दिया जाना चाहिए तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा.

विभूति प्रसाद पांडेय

पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील विभूति प्रसाद ऐसे नेता को सीएम बनते देखना चाहते हैं, जो बदलाव की बयार ला सके. उन्होंने बताया कि हम एक ही चेहरे के समर्थन में नहीं हैं. आगामी सरकार से मांग पर विभूति बताते हैं कि जनता की सरकार को भलाई करनी चाहिए. आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा 1972-73 के बाद पूरी तरह से बाधित हुई है जिसपर सरकार को सोचना चाहिए. पूर्ण बहुमत की सरकार पर उन्होंने बताया कि स्पष्ट बहुमत की सरकार होना बहुत ही जरूरी है साथ में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, ताकि सरकार को सही गलत पर पकड़ा जा सके. केंद्र सरकार के अठारह महीनों के शासनकाल पर विभूति पाण्डेय ने कहा चुनाव के समय में मोदी जी ने एक सपना दिखाया काला धन लाने के सम्बन्ध में, जो आज जुमला बन गया है. उनके राज्य में भी बेईमानी पनपनी शुरू हो गयी है. आनेवाली सरकार को सुझाव पर विभूति पाण्डेय बताते है की सरकार को विकास करना है तो पहले गांव से शुरू कर शहर में आएं तभी विकास नजर आएगी.

रेणुका शर्मा

वरिष्ठ अधिवक्ता रेणुका शर्मा ने मुख्यमंत्री की पहली पसंद रविशंकर प्रसाद को बताया. उन्होंने कहा रविशंकर अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक कुशल नेता हैं. वे जिसे भी यहां के लिए चुनेंगे वो अच्छा काम ही करेगा. राज्य सरकार से मांगों पर रेणुका कहती हैं, सरकार को बहाली प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए, उम्मीदवार की क्षमता को देखा जाना चाहिए न की उसके दस्तावेज को. पूर्ण बहुमत की सरकार और खिचड़ी वाली सरकार पर रेणुका का मानना है कि जिस तरह से सीट बंटवारे के आकड़े हैं, उससे पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नहीं दिख रही है और खिचड़ी वाली सरकार सिर्फ पकाने के लिए ही होती है खाने के समय विफल हो जाती है. बेहतर शासनकाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की एनडीए प्रथम की सरकार बेहतर थी. नरेन्द्र मोदी के शासनकाल के बारे में रेणुका ने कहा उनमें प्रशासनिक क्षमता अधिक है जिससे भारत विकास की ओर है. रेणुका वोटर के नाते आनेवाली सरकार को कहती हैं कि सरकार विकास की बात न करे, विकास करे और अपने कामों में निष्पक्षता लाने की ज़रूरत है.

सोनी श्रीवास्तव

अधिवक्ता सोनी श्रीवास्तव का मानना है कि नई सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और स्वच्छ बिहार बनाने में अधिक ध्यान देना चाहिए, जिस तरह कानून की स्थिति में तब्दीली आई है, उससे बिहार की महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी हैं. सोनी श्रीवास्तव ने यहां की शिक्षा को बद से बदतर बताया. बेहतर शासनकाल वाली सरकार के बारे में सोनी का मानना है कि एनडीए के साथ वाली नीतीश सरकार की रही है. वहीं पिछले अठारह महीनों के नरेन्द्र मोदी की सरकार को वह बताती हैं मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन अभी उनके बहुत से काम नजर नहीं आ रहे हैं पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वह अच्छा करेंगे. सोनी ने आने वाली सरकार के सुझाव पर कहा कि जनता के बीच में नेताओं की गरिमा थोड़ी अच्छी नहीं है. इसलिए, नेताओं को कुछ ऐसा करना चाहिए की उनकी जनताजनार्दन के बीच में अच्छी इमेज बने. आगे उन्होंने कहा कि सरकार को अपराधियों के लिए कड़ा नियम बनाना चाहिए ताकि उनमें भय हो.■

गुलाबबाग मंडी में नहीं

पहुंची विकास की रोशनी

नीरज सिंह

feedback@chauthiduniya.com

राज्य की वर्तमान जदयू और महागठबंधन की सरकार विकास के लाख दावे पेश कर ले लेकिन हकीकत यह है कि शहरी विकास की योजनाएं 8 किमी की दूरी तय करके पिछले चालीस सालों में गुलाबबाग मंडी तक नहीं पहुंच पायी है और हकीकत यह है कि वर्तमान में सरकार को करोड़ों का राजस्व देने वाला मंडी आज भी पिछड़ा और अविकसित रह गया है. हालांकि विकास के प्रशासनिक दावे हमेशा होते रहे हैं. गुलाबबाग को अब इस बात का मलाल है कि यह इलाका भाजपा का वोट बैंक रहते हुए राज्य में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने के वाबजूद भी यह इलाका विकास के लिए तरसते रह गया और भाजपा-जद(यू) के राजनितिक दांव-पेच में फसा रहा और वह भी तब जहां राज्य और केन्द्र में पूर्णिया से भाजपा प्रतिनिधित्व रहा. मालूम हो कि बिहार सरकार ने 1965 में किसानों को उनके उत्पादों का समुचित लाभ और मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रमुख शहरों में कृषि उत्पादन बाजार समिति की स्थापना की. कालान्तर में जहां बिहार के अधिकतर बाजार समिति तहस-नहस हो गईं वहीं पटना के मारूफगंज मंडी के बाद गुलाबबाग मंडी उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी के रूप में इभरी लेकिन वर्तमान में धूल, टूटी-फूटी सड़कें, गंदी नाली, कीचड़ युक्त जल जमाव, जाम और सुअरों का रैन बसेरा ही गुलाबबाग मंडी की पहचान बन गई है. आज यहां के करोड़ों का राजस्व देनेवाले व्यवसायी शुद्ध पेयजल, सड़क, चिकित्सा, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं. यहां के वाशिन्दों और व्यापारियों के मन में यह सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि सरकार को करोड़ों का टैक्स देने के बावजूद भी हम इतने उपेक्षित क्यों हैं? यहां का एक विडम्बना यह भी है कि यहां का नेतृत्व हमेशा कमजोर रहा है जिसके कारण सरकार और प्रशासन के सामने इनकी दमदार वकालत कभी भी नहीं हो सकी, हालांकि व्यपारियों की बुनियादी सुविधा और समस्याओं को लेकर यहां व्यवसायी संघ निजी हित साधने की पॉकेट की संस्था बनकर रह गई है. यहां की बुनियादी सुविधाओं, पार्क, स्वास्थ केन्द्र, स्टेडियम आदि को लेकर मारवाड़ी युवा मंच, यूथ सोसाईटी जैसे संगठन जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के आलाधिकारियों से स्मार पत्र के माध्यम से यदा-कदा मांग करते रहे है लेकिन उनकी मेहनत भी रंग नहीं ला रही है.

मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सुमित लोहिया का कहना है कि जद(यू) सरकार के पूर्व कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह ने गुलाबबाग मंडी का दौरा किया था और मंडी की समस्याओं को लेकर जमीनी तौर पर अवगत हुए थे और बुनियादी सुविधाओं के विकास को लकर आश्वासन भी मिला लेकिन यह हवा-हवाई ही साबित हुई. बहरहाल एक बार फिर चुनाव का मौसम आ गया है और यहां के व्यापारियों समेत जद(यू) के तमाम विरोधी दल चुनावी मुद्दा बनाने का मन बना रहे हैं. भाजपा उद्योग मंच के जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय खेमका का कहना है की राज्य में भाजपा-जद(यू) गठबंधन की सरकार बनने पर कृषि मंत्रालय जद(यू) के कोटे में चला गया वैसे गुलाबबाग को शहरी विकास योजना अन्तर्गत विकसित करने को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तमाम वैसे प्रयास किये लेकिन कृषि विभाग भाजपा के पास नहीं रहने के कारण जद(यू) ने मामले को राजनीतिक पेंच में फंसा दिया. भाजपा महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं धमदाहा से भाजपा टिकट की दावेदार ज्योति रानी का कहना है कि गठबंधन में रहते हुए जद(यू) ने कभी भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, जिसके चलते भाजपा से जुड़े मुद्दे को जद(यू) ने कभी भी तरजीह नहीं दी.

रालोसपा के संगठन सचिव सह धमदाहा से रालोसपा टिकट के दावेदार निरंजन कुशवाहा का कहना है कि किसानों से जुड़े मुद्दे से जद(यू) का

कोई वास्ता नहीं रहा है. गुलाबबाग मंडी किसानों पर निर्भर है जिसके चलते मंडी पहुंचने वाले किसानों को बुनियादी सुविधा तो क्या स्वच्छ पेयजल भी नसीब नहीं है. भाजपा क्रीड़ा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष और बहादुरगंज से भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार वरुण सिंह का कहना है कि गुलाबबाग मंडी बिहार की सबसे बड़ी मंडी है. जब नीतीश कुमार करोड़ों की टैक्स देने वाली मंडी को बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाये तो बतायें ऐसे में बिहार भला कैसे आगे बढ़ा. कसवा से भाजपा टिकट के दावेदार संजय मिर्धा का कहना है गुलाबबाग की पहचान पूरे भारत की मंडियों से जुड़ी हुई है ऐसे में दूसरे प्रांतो से आये व्यवसायी नीतीश के बदलते बिहार की जो तस्वीर पेश करते होंगे, समझ लीजिए. जद (यू) नेता सह पूर्णियां सीट से जद(यू) टिकट के प्रबल दावेदार जितेन्द्र यादव का कहना है कि गुलाबबाग के विकास और जाम की समस्या के निदान को लेकर गुलाबबाग से फोर्ड कम्पनी तक सिक्स लेन सड़क बनाया जा रहा है. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर मेला ग्राउंड में जलमीनार बनाया गया है. 24 घंटे में से कम से कम 22 घंटा बिजली इपलब्ध कराया जा रहा है. अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है और दवाई इपलब्ध है.■